साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com
Cell: +91 9425125569

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष : 13 अंक : 28 | प्रति सोमवार, इंदौर 18 फरवरी से 24 फरवरी 2019 | पृष्ठ : 12 | मूल्य: 2 रुपए

कोई भी राष्ट्र गंभीर नहीं विश्व के पर्यावरण को सुधारने और बचाने में

पर्यावरण को सुधारना आवश्यक है, बंद करो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का लूट का व्यवसायिक तरीका

यदि दुनिया के बड़े राष्ट्रों में पेट्रोल, डीजल की खपत को कम करने की, और यूरोपियन बहुराष्ट्रीय कंपनियां दुनिया की जनता को लूटने, कृषि उत्पादों में खाद्य कीटनाशक का प्रयोग, अपनी खाद्य सामग्री को जब तक प्लास्टिक पैकिंग में बेचना बंद नहीं करेंगे, तब तक पूरे विश्व में किसी भी हाल में पर्यावरण सुधार नहीं हो सकता चाहे फिर अंटार्कटिका, हिमालय व दुनिया के अन्य सभी बर्फीले स्थानों की बर्फ पिघल कर पूरी दुनिया की धरातल को पानी में ही क्यों ना डुबो दें। दुनिया की अधिकांश कृषि भूमि बंजर क्यों ना हो जाए। वन और वन्य प्राणी पूरे नष्ट ही क्यों ना हो जाए पूंजी राक्षसों को इन से कोई लेना देना नहीं।

विश्व भर में दुनिया के सभी बड़े देश में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन, रूस, जैसे बड़े औद्योगिक राष्ट्र और उनकी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो दुनिया में सबसे ज्यादा अपने उद्योगों के उत्पादन से, पेट्रोल डीजल के उपभोग से, अपने देशों में सबसे ज्यादा वातानुकूलित यंत्रों से, अपनी सभी खाद्य सामग्री को प्लास्टिक पैकिंग में लूटने के लिए बेचकर सबसे ज्यादा विश्व की पर्यावरण को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है, अपने दुष्कर्मो को छुपाने अन्य देशों को पर्यावरण के बारे में ज्ञान बांटते रहते हैं। जबकि उसके पीछे उनका उद्देश्य पर्यावरण को बचाना नहीं, वरन दूसरे देशों को पर्यावरण की आड़ में डरा धमका कर, उनको औद्योगिक उत्पादन मे अपना प्रतिद्वंदी बनने से रोक अपना व्यवसाय बढ़ाना होता है। यह बात स्पष्ट हो चुकी है। दूसरी ओर दुनिया भर में अधिकांश सरकारों में बैठे नगर निगम और पालिकाओं से लेकर मंत्रालय के लोग अपनी मोटी कमाई के लिए चारों तरफ सड़कों पर कांक्रीट से लेकर बड़े-बड़े स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के नाम पर कांक्रीट जंगल खड़े करना भी एक तरफ वनों को बर्बाद करता है, पानी के प्राकृतिक बहाव को रोकता है बरसात को बर्बाद करता है।

अपनी हमारी आधुनिकता हमारे लिए अभिशाप बनती जा रही है।पूरी दुनिया में बढ़ते प्रदूषण से चारों तरफ बिगड़ते पर्यावरण से पूरे विश्व की जलवायु में चारों तरफ घोर परिवर्तन आने लगे हैं। समुद्र का बढ़ता हुआ जलस्तर, गलती हुई अंटार्कटिका की, हिमालय की, रूस के साइबेरिया व अन्य सभी बर्फीले स्थानों की हिम खंडो व हिमनदों के पिघलने से विश्व के सभी देशों की सत्ताओं को अपने देश की धरती को डूबने की चिंता तो सताने ही लगी है। बेशक सभी बड़े लोकतांत्रिक देश की सत्ताओं को यथार्थ में यूरोपियन और वहां की बहुराष्ट्रीय कंपनियां और वहां के बड़े पूंजीपति अधिकांश देशों की राजनीतिक पार्टियों को मोटा चंदा देकर वहां पर अपने तरीके से देश के प्राकृतिक व मनुष्य निर्मित सभी संसाधनों का अधिकतम दोहन व शोषण कर अपने मोटे लाभ के लिए कानून बनवाते हैं। फिर उसी कानून के माध्यम से वहां की सरकारें उन कंपनियों को जनता व वहां के पर्यावरण को लूटने और बर्बाद करने की पूरी छूट दे देते हैं। बदले में वे बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वहां के सरकारी अधिकारियों मंत्रियों को मोटा कमीशन बांटते रहते हैं। भारत में व दुनिया के अन्य सभी लोकतांत्रिक देशों में 1965 के बाद कोई भी कानून वहां की सरकारों ने जनहित के लिए नहीं बनाये और लगाये।

शेष पृष्ठ 4 पर

लोकसभा चुनाव में पुनः ईवीएम की जालसाजी से जीतने का षड्यंत्र

3 राज्यों में हारकर 2019 के पुनः सत्ता हथियाने का खेल

तीन राज्यों में जानबूझकर ईवीएम में गड़बड़ी करके भी कांग्रेस को चुनाव जिता देना शाह और मोदी की लंबी गहरी शतरंज की चाल है। अपने राजा और वजीर को बचाने के लिए हाथी घोड़े ऊंट पिटवा ने ही पड़ते हैं।

यह शतरंज की चाल इसलिए चली गई। ताकि लोग ईवीएम पर विश्वास करके ईवीएम पर उंगली ना उठाएं और वह आसानी से 2014 की तरह पुनः जालसाजी से 2019 मे सत्ता हथियाने में कामयाब हो जायें।

गुजराती घोर जालसाज, महा धूर्त मोदी और शाह अच्छी तरीके से जानते हैं। कि वो किसी भी हाल में वेलेट पेपर से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और यदि इन तीनों राज्यों में यदि पुनः ई वी एम की जालसाजी से गुजरात और उत्तर प्रदेश की तरह चुनाव जीत लेते हैं तो देश की जनता और विश्व के मीडिया में स्पष्ट संदेश जाएगा की मोदी और शाह ने तीनों राज्यों में ईवीएम की जालसाजी से चुनाव पुनः जीत लिये है। इससे पूरे देश में जनता में ईवीएम मशीनों के प्रति अविश्वास बढ़ेगा, और मांग बढ़ेगी की। ईवीएम मशीन जालसाजी से चलाई वाह मनमर्जी से प्रणाम देती है।

शेष पृष्ठ 11 पर

मोदी का अंतरिम बजट 2019, पाखंड और आंकड़ों की बाजीगरी

मोदी के कुकर्मों के घावों पर भारी वोटों के लिए लोक लुभावन बजट का मरहम

मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को यथार्थ में पूरी तरीके से चौपट कर दिया। अपनी मौज मस्ती, अपने पूंजी पतियों की मोटी कमाई के लिए बैंकों में हर लेन-देन पर भारी सेवा शुल्क, नगदीहीन अर्थव्यवस्था, नोटबंदी, जीएसटी, से उद्योग धंधों को चौपट करने के बाद चारों तरफ उपजी बेरोजगारी, पेट्रोल, डीजल, गैस में चौगुनी लूट के घावों पर् मरहम लगाने का इस अंतिम बजट में बहुत छोटा सा नाकाम दिखाऊ और काम चलाऊ प्रयास किया।जिस रु5 लाख तक की आय पर आयकर की छूट। केवल छलावा।वह भी तब जब भाजपा जीतेगी दूसरी ओर एक रुपए भी ज्यादा हुआ तो ढाई लाख के बाद से आयकर। तिगुनी कीमत पर डीजल पेट्रोल की आय, बैंकों में न्यूनतम शेष के नाम पर रुपए 5 लाख करोड की आय आखिर बजट की आय में क्यों नहीं दिखाई। जबकि बैंकों में पांचवे लेन-देन के बाद जीएसटी और सेवा शुल्क के नाम पर जनता से लूट कर बैंकों को आकाओं के डूबंत ऋणों की भरपाई की जा रही है। बेरोजगारों के लिए कोई नई योजना नहीं।ईज ओफ डूइंग बिजनेस,स्टार्ट अप, के लिए धन की कोई व्यवस्था नहीं। यदि 3 बड़े राज्यों में नहीं हारते, तो $50-55 का अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकने वाला क्रुड भी भारत में पेट्रोल की रु100 प्रति लीटर की कीमत बिकने लगा था। तीन राज्यों में हारने के बाद जीएसटी की कीमतों में बदलाव किए जाने के साथ पेट्रोल की कीमतें भी रु72-75 पर के आस पास आ गई। आगम प्राप्तियां19-20 मैं 19 लाख 77693 करोड, पूंजीगत प्राप्तितयां 806507करोड 6650 61करोड़ केबल देसी विदेशी हीरोइनों के ब्याज में भुगतान कर दिया जाएगा। राजस्व घाटा रुपए 443602 करोड प्रभावी राजस्व घाटा रुपए 252568 करोड राजकोषीय घाटा 591064 करोड़। जनता से हर कदम यहां तक कि बैंकों से लेन देन पर भी लूट के बाद मोदी की उसके वित्त मंत्री ने अगर इस लूट के पैसे से देश का अरबों लाख करोड़ का कर्ज कम कर दिया होता जिस पर सरकार को 6 लाख 65 हजार61 करोड का ब्याज ही चुकाना पड़ रहा है तो भी मान लिया जाता।

शेष पृष्ठ 8 पर

अपने आका पूंजीपतियों के लिए नोंच मारा दोनों धूर्तों ने देश व जनता को

57 महीनों में मोदी ने चारों तरफ मचा दी घोर तबाही

गुजराती घोर, झूठे, मक्कार, मोदी और शाह दोनों खानदानी अपराधियों ने पूरी भाजपा के बड़े नेताओं को ब्लैकमेल कर पूरे तरीके से बंदी बना पूरी केंद्र की सत्ता को हथिया कर पिछले 57 महीनों में देश की संपत्तियों, उपक्रमों, और देश की जनता, को बहुराष्ट्रीय और देसी पूंजीपतियों के लिए अपनी मौज मस्ती अय्याशी के लिए गिरवी कर दिया।अपनी तानाशाही के लिए सर्वोच्च न्यायालय, रिजर्व बैंक, वित्त, तेल, स्वास्थ्य, रेलवे, रक्षा, ग्रह, उद्योग व रोजगार मंत्रालय, भारतीय सांख्यिकी ब्यूरो, आदि सभी मंत्रालयों को अपने बाप की जागीर समझ हर जगह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही।अपनी खबरें, सच्चाईया देश व दुनिया की जनता को मालूम ना पड़े। इसलिए इन दोनों अपराधियों ने देश के 90% समाचार चैनलों को, सोशल मीडिया की फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, गूगल,आदि को डरा धमका कर उसके बीच चलने वाले समाचारों को रोकने के लिए कानून बनाने से लेकर लाखों करोड़ का मोटा धन खर्च कर, समाचार को प्रसारित होने से क्यों रोका जा रहा है। लगातार पिछले 5 सालों से इतना डरपोक और भयभीत क्यों है यह पिल्ले मोदी और अमित शाह आखिर अपने कुकर्म और भ्रष्टाचार की लूट डकैती की सच्चाई से।

अच्छे दिन का वादा तो चुनावी सिद्ध हो गया। सत्ता संभालते ही देश के संसाधनों को भेडियों ने अपने बाप की जागीर समझ कर, लाल किले को गिरवी करने से लेकर, रेलवे के सभी बड़े 256 रेलवे स्टेशन गिरवी कर दिए, ओएनजीसी, रेलवे, सभी तेल कंपनियां, बैंको, बीमा कंपनियों, आदि की लूटपाट करने बर्बाद करने अपने पूंजीपति आकाओ को खुली छूट दी । आयुष्मान भारत, किसान और फसल बीमा का जनता से लगभग सवा लाख करोड रु इकट्ठा कर अपने बाप अनिल अंबानी को सौंपा। 8 नवंबर 2016 को नोट बंदी से 60 दिन पूरे देश को ठप्प कर दिया गया। 2 साल बाद में भी भारत की अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर नहीं आ पाई। उससे 2 करोड़ लोग स्थाई रूप से बेरोजगार हो गए। 50 लाख से ज्यादा लघु एवं कुटीर उद्योग नगदी के अभाव में सदा के लिए बंद हो गए। यह नोटबंदी उसने अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला, बहुराष्ट्रीय कंपनी वॉलमार्ट, यूनिलीवर, आईटीसी आदि से हजारों कोड खाकर उनके फायदे के लिए की थी उससे उनका व्यापार 4 गुना बढ़ गया। जसि काले धन को खत्म करने, के विपरीत अपने पूंजीपतियों के काले धन को बढाने रु दो हजार के 5लाख करोड के नोट चलन में डाल दिया गया। विदेश यात्राओं में जनधन के लाखों करोड बर्बाद करा जो विभिन्न मंत्रालयों से लिया गया।

शेष पृष्ठ 11 पर

मुखेरा जन पार्टी के गुजराती मोदी व शाह का मुख में राम बगल में छुरी

खुद की मौज मस्ती और विकास, ले डूबा 3 राज्यों में

मप्र में शिवराज का अहंकार व सवर्णों का हर कदम अपमान ने दिखा दिया आसमान

शिवराज ने प्रदेश में काम बहुत किए परंतु सवर्णों का हर कदम अपमान, अधिकारियों कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित कर केबल वोटों की खातिर एसटीएससी के विकास का पक्षधर बन गए। ये वहीं भाजपा है । जिसे सवर्णों ने तन मन धन से पाला पोषा बड़ा किया जब उनके हितों की बात उठी तो उन्हीं का शत्रु बन हर तरह से उनकी बर्बादी पर तुल गया। जो उसकी स्वयं की बर्बादी का कारण बन गया। सबसे पहले ही sc-st ने हीं उसे वोट नही दिए।

भाजपा की तीनों हिन्दीभाषी प्रदेशों में करारी शिकस्त से बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ,क्योंकि यह तो होना ही था। हां कुछ साथी जरुर इस हार को लेकर बौखला जरुर रहे हैं। क्योंकि वे मानते हैं कि यह हिन्दुत्व की हार है ,और वे हिन्दू मतदाताओं को "जयचन्द"जैसे विशेषण से नवाज रहे हैं।जबकि मेरा मानना है कि जनता ने काँग्रेस को नहीं जिताया है। बल्कि सिर्फ़ भारतीय जनता पार्टी को हराया है। जिसके लिए पार्टी के विधायक और मंत्री स्वयं दोषी हैं।वे अपने आप को जनता का भाग्यविधाता समझ बैठे थे। उन्होने अपना स्वयं का एक ऐसा काल्पनिक आभामण्डल तैय्यार कर लिया था कि वे खुद चौंधिया गये थे।उस आभामण्डल तक कुछ खास लोगों की ही पहुंच थी।आम कार्यकर्ता को दुत्कार दिया जाता था ।जिससे कार्यकर्ता पार्टी से दूर होता चला गया।और परिणाम सबके सामने है। यहाँ विशेष रुप से उल्लेखनीय है कि पार्टी ने जिस तरह से जातिवादी कार्ड खेलना शुरु किया था। वह चाल उल्टी पड़ गई। मध्यप्रदेश राज्य में पिछले सत्ताईस साल से स्कूली शिक्षा विभाग में सवर्ण व्याख्याताओं को प्रमोशन नहीं दिया गया है। वहीं ,उनके साथ ही भर्ती हुए SC/ST वर्ग के साथी प्रमोशन ले लेकर काफी ऊंचे पदों तक पहुंच चुके हैं। इस विसंगति को लेकर इस वर्ग में व्यापक असंतोष है। किन्तु शिवराज चौहान प्रमोशन में भी आरक्षण देने के लिए हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट तक पहुंच गए।"कोई माई का लाल आरक्षण नहीं हटा सकता" वाला उनका बयान उनके लिए मुसीबत बन गया । परिणामस्वरूप भाजपा का स्थायी वोट बैंक जोकि सवर्ण था।

शेष पृष्ठ 2 पर

संपादकीय

चोर- चोर मौसेरे भाई

सत्ता किसी की भी हो सभी लूटने आए हैं।सत्ता की काल की, काली कोठरी में दूध का धुला तो कोई भी नहीं।कोई कम, कोई ज्यादा। बस रहता है। तो मौके का इंतजार, जिसको मौका मिलता है। वह येन कैन प्रकरेण, जनता को अत्यधिक करों से लूट कर, जनता के विकास के नाम बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाई जाती है मात्र मोटे कमीशन के लिए, भारी कमीशन हजम किया जाता है। लूटे हुए धन से अपनी नश्वर काया मोह माया के झूठे रिश्तों के लिए के लिए अपना घर भरने लगते हैं। पहले देश में जमीन, संपत्तियां बंगले खरीदते हैं। दूसरों के नाम से फैक्ट्रियां लगाते हैं। पैसा ब्याज पर चलाते हैं। कंपनियों के अंश पत्र, ऋण पत्र, खरीदते हैं फिर भी धन बचता है। तो विदेशी बैंकों में भी जमा करते हैं। यह सच सभी राजनीतिक पार्टियों के आपराधिक प्रवृत्ति से लेकर जीवन भर अफसरशाही करने वाले नेताओं का भी होता है। इन सब में, सबसे मजेदार बात यह है, कि लोकायुक्त, आयकर, सीबीआई, एनफोर्समेंट, एसआईटी, आदि सब के छापे, व्यवसायियों, उद्योगपतियों, अधिकारियों, कर्मचारियों पर पड़ते हैं।परंतु यह सभी छापे और कार्रवाईयां किसी भी राजनीतिक दल के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री आदि पर कभी नहीं होती। जबकि कश्मीर से लेकर केरल तमिलनाडु तक मुंबई महाराष्ट्र से लेकर शिलांग इंफाल मणिपुर तक सभी नेता सारे दुष्कर्म के बाद में भी इन सब कार्यवाहीयों से सदा सुरक्षित रहते हैं। जब तक कोई मोटा कांड मीडिया की सुर्खियों में समाचार चैनलों और अखबारों में ना आ जाए। मंचों पर भलाई एक दूसरे को गाली बकें, चोर बोलें, मीन मेख निकालें।सदन में एक दूसरे पर भारी कीचड़ उछाले छिछालेंदार करें। परंतु बाहर निकलते ही एक दूसरे के गले में हाथ डालकर गपियाते हंसी ठिठोली करते हुए नजर आएंगे।

चुनाव के समय, सार्वजनिक मंचो पर, बड़े से बड़ा नेता भी सब एक दूसरे की बुराई कर और एक दूसरे पर दोषारोपण कर अपनी झूठे वादों की दर्शकों और मतदाताओं को चासनी पलिाते हैं। झूठे वादों के सब्जबाग दिखाकर सत्ता हथिया लेते हैं। यह कम से कम भारत में तो पिछले 70 साल से चल ही रहा है। इस पर कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं होती। सब एक दूसरे का इस मामले में ख्याल रखते हैं। सबको मालूम है। सब के पास काले धन का अंबार है। चुनाव में सैकड़ों करोड खर्च किए जाते हैं। विधायकों की खर्च की सीमा रु30लाख और सांसद की रु70 लाख की सीमा से 10 से 100 गुना तक ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है।खुले में शराब, शबाब, कबाब, के साथ नगद लोगों को बांटने का भी चलन अधिक बढ़ जाने के साथ सब खुले में होता रहता है। परंतु सब चुनाव अधिकारी क्षेत्रीय व बाहर के छोटे नेताओं निर्दलीय उम्मीदवारों को ही भर परेशान करते हैं। परंतु सभी बड़े दल के नेता उम्मीदवार आदि यहां भी सब कुछ करने के बाद पूर्ण सुरक्षित रहकर सारे दुश्कर्मो को चुनावों के लिए अंजाम देते रहते हैं। चुनाव आयोग की चुनावों से पहले निष्पक्ष चुनाव करवाने की लंबी चौड़ी घोषणायें होती है।वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। चुनाव खर्च पर नियंत्रण रखा जाएगा। अवैध दारू नोटों का वतिरण रोका जाएगा। परंतु कुछ नहीं रोका जाता।पर सारे चोर अपने अपने कामों को खुलकर अंजाम देते हैं और चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं यही सभी मौसेरे भाई जब विधान लोकसभा में पहुंच जाते हैं।और सदन में भी इस बात की पूरी कोशिश की जाती है कि तू लूट रहा है। तो लूट। मुझे भी दे लूटने की पूरी छूट। जनता की वास्तविक परेशानियों, मूलभूत आवश्यकताओं, शिक्षा, रोजगार, आदि के लिए आज भी करोडो की आबादी वंचित है। पर सत्ता में आते ही जन धन से विदेश यात्राओं में मौज, मस्ती, अय्याशी से फुर्सत मिलते ही कांग्रेस व भाजपा व अन्य दलों के सहयोगियों ने जनता को लूटने और पूंजीपति आकाओं को कमाई के लिए अनेकों कानून और षडयंत्र रचे।

खुद की मौज मस्ती और विकास, ले डूबा 3 राज्यों में

पृष्ठ 1 से जारी

वह उससे दूर हो गया और जिनके आरक्षण के लिए पार्टी ने इतना बडा दांव खेला था। उन्होंने भी पार्टी को वोट नहीं दिया।

इसके अलावा शिवराज सिंह जी मन्दिरों में भी दलित पुजारी रखे जाने के पक्षधर रह चुके हैं। शायद उन्हें नहीं मालुम होगा कि मन्दिरों में पूजापाठ करने वाला गरीब ब्राह्मण किस दरिद्रता में अपना जीवनयापन करता है। किन्तु दलित वोटबैंक की खातिर यह कुत्सित प्रयास करने में भी वे नहीं चूके। फिर भाजपा की हार के लिए किसी वर्ग विशेष को दोषी कैसे ठहराया जा सकता है?

हां केन्द्र सरकार की कुछ नीतियाँ भी भाजपा की हार के लिए जिम्मेदार हैं। जिस में सबसे बड़ा मुद्दा था पूंजी पतियों के लिए मोदी ने देश की बर्बादी मे कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड 28 डॉलर प्रति बैरल बिक रहा था तब भी देश में पेट्रोल की कीमत रु75 से रु 80 चल रही थी इसका पूरा फायदा अंबानी की रिलायंस पैट्रोलियम को मिल रहा था। उसने अपने खास आकाओं के लिए भारतीय तेल कंपनियों का जो कि अंतरराष्ट्रीय बाजार से देश के लिए पेट्रोल खरीद खरीद करती थी मैं अधिकार उसने रिलायंस पैट्रोलियम को दे दिये। जो 15 से 20 % कमीसन खाकर भारतीय तेल कंपनियों को आपूर्ति करती थी। और चोगुना लाभ कमाने के बावजूद भी जनता को उसका लाभ नहीं दिया गया। स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट मात्र 20 से 30% कमीशन खाने के लिए बनाकर पुरानी अधिकांश देश के शहरों में भारी तोड़फोड़ की गई ऑफ और हजारों लोगों को सड़क पर लाकर पटक दिया बिना किसी मुआवजे के। फरि नोटबंदी ने तत्काल 10 करोड़ लोगों को 2 महीने तक के लिए बेरोजगार कर दिया। नगदी की कमी ने हीं देश के 50 लाख से ज्यादा लघु उद्योग, 10000 से ज्यादा मध्यम श्रेणी के उद्योगों पर मंदी की मार ने हीं 5 करोड लोगों को बेरोजगारी दी। अपनी पूंजीपति बापू का पेट भरने बैंकों की कमाई करवाने नगदी हीन व्यवस्था के नाम उपरांत 50 करोड़ लोगों के बैंकों में खाता खुलवा कर न्यूनतम जमा ओं के नाम पर जनता का रु4.5 करोड निजी व सरकारी बैंक हजम कर गई और बदले में अपने पूंजीपति बापों का लाखों करोड़ का कर्ज माफ कर दिया गया। इससे पेट नहीं भरा तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों और पूंजी पतियों की मोटी कमाई छोटे उद्योगों, दुकानदारों को समाप्त करने के लिए जीएसटी लाद दिया गया। फरि राममन्दिर ,धारा370, 35 A (जम्मूकश्मीर के सम्बन्ध में) कश्मीर में पत्थरबाजों पर नरमी और सैनिकों का अपमान और उनकी शहादतें जैसी तमाम सारी छोटी बडी बातों की लम्बी फेहरिस्त है।

भाजपा को "जोर का झटका धीरे से"लगना जरुरी था कि 2019 के लिए अभी भी वक्त है संभल जाओ नहीं तो "ये पब्लिक है ये सब जानती है।

शास. नीतियां अच्छी परंतु प्रस, संचालक से लेकर कृ.वि. अधिकारी तक घोर भ्रष्ट

आखिर हर वर्ष प्रदेश, देश में लाखों किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है?

प्रदेश के 51 जिलों में बैठे उपसंचालक जो कि क्षेत्रीय बीज, खाद कीटनाशक कृषि यंत्र, व अन्य किसी सामग्री विक्रेताओं व उत्पादकों से मोटा कमीशन खा कर विक्रय और उत्पादन के लिए अनुज्ञप्ति और नवीनीकरण लाइसेंस जारी कर देते हैं। जब सबको चाहिए मोटा कमीशन खाद बीज कीटनाशक उत्पादन कर्ताओं और विक्रेताओं से, जब एक मोटा कमीशन देंगे तो किसानों को माल तो स्तरहीन हीं देंगे ना। बेशक, केंद्र व राज्य सरकार अधिकतम अनुदान फसल बीमा, और मध्य प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार ने तो फसल उत्पादन कम कीमत पर बिकने पर भावांतर भी दिया। निसंदेह इस भावंतर योजना में भी व्यापारियों को फायदा पहुंचा कर एक तरफ से मोटी वसूली की गई तो दूसरी तरफ कृषि, विपणन, सहकारी समितियों खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के अधिकारियों आदि ने जोकि इस खरीदी मेंशासन की तरफ से अधिकृत वह निगरानी के लिए नियुक्त किए गए थे।मिलकर यहां भी भारी घोटाले करते हुए प्याज गेहूं अन्य फसलों में इस भावंतर के माध्यम से एक तरफ सस्ता माल अपने ही एजेंट किसानों से बकिवा कर, व्यापारियों को सस्ते में लिखवाया गया मोटी कमाई कर प्रदेश के जनधन की अरबों रुपए की लूट करवा कर शासन को अरबों रुपए की क्षति पहुंचाई।इस बंदरबांट में मुख्यमंत्री कृषि मंत्री मुख्य सचिव कृषि प्रधान सचिव आयुक्त संचालक सभी ने करोड़ों रुपए पर हाथ साफ किए इसकी भी नए मुख्यमंत्री को जांच करवानी चाहिए अभी तक सैकड़ों किसान प्रदेशभर में भावंतर की राशि के लिए डेढ़ 2 वर्षों से चक्कर लगा रहे हैं कृषि विभाग प्रदेश की कृषि मंडियों में इस भ्रष्टाचार की भी जांच करवा दोषी अधिकारियों को सजा देते हुए पीड़ित किसानों को तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए।

कृषि विभाग को कृषि मंत्रालय में बैठा घोर भ्रष्ट राजेश राजौरा जिसने पिछले 5-6 सालों में हजारों करोड़ की कमाई की। रु27 किलो का ढेंचा या जैविक खाद की खरीदी रु130/- प्रति किलो खरीदी करवा जिसमें गोबर की खाद के नाम पर खुले में 50 से 60 प्रतिशत तक मिट्टी, फसलों के कचरे को सड़ा करवजन बढ़ाने के लिए मिलाकर प्रदेश भर में आपूर्ति की गई।जिसकी वास्तविक कीमत मात्र रु8-10 थी। प्रदेश के 10 से ज्यादा आदिवासी जिलों में हजारों टन 75 % अनुदान पर, अनुसूचित जाति के किसानों को 66% व सामान्य वर्ग को 33% अनुदान में बेचा गया जबकि खुले बाजार में उससे बेहतर जैविक खाद रु25/- प्रति किलो में उपलब्ध था। इसी प्रकार मृदा परीक्षण किट जो की बाजार में रु5000 में उपलब्ध है। रु105000/-- में खरीदी करवाकर सभी जिलों के उप संचालकों को 1000 नग आपूर्ति कर भुगतान करने के लिए कह दिया गया।यह हाल उस में उपयोग किए जाने वाले रसायन, खाद बीज कीटनाशक व अन्य कृषि सामग्री मैं भी पिछले 6 सालों से लगातार हो रहा है। जिसमें उसकी कठपुतली संचालक मोहन मीणा आंख मींच कर उसके हर आदेश पर अंगूठा लगाकर पालन करने में लगा हुआ था। उम्मीद की जा रही थी। नाथ की सरकार इन दोनों को संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए मीणा और राजौरा को लूप लाइन में भेज देगी। इसके विपरीत राजौरा और मीणा दोनों शीश पर बैठे अधिकारी वहीं जमे हुए है।फिर राजौरा का तो पिछले 6-7 सालों का इतिहास रहा है। कि पहले स्वयं भ्रष्टाचार करते हुए अपने भ्रष्ट अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने की छूट देकर वसूली करना। मामला अगर प्रसार माध्यमों में यथा टीवी न्यूज चैनल्स और समाचार पत्रों में आ जाने के बाद, उनको कारण बताओ पत्र जारी करना फिर उन अधिकारियों से वसूली करना यदि पर्याप्त वसूली मिल गई तो उन्हें बख्श देना और नहीं तो निलंबित कर देना जब मनचाही वसूली मिल जाए तो उन्हें पुनः उनकी इच्छा अनुसार जिलों में पदोन्नत कर महीने की मोटी रॉयल्टी पर पदस्थी कर देना। इंदौर का संयुक्त संचालक सिसोदिया, उज्जैन का पांडे इंदौर में उपसंचालक विजय चौरसिया उज्जैन में केवड़ा देवास में सुभाष राजपूत धार में कुनेरे जैसे प्रदेश भर के 51 जिलों में पदस्थ सभी उपसंचालक को संयुक्त संचालकों के यही हाल है सभी किसी न किसी भ्रष्टाचार के अपराध में गले तक लिप्त होने के बाद भी शान से खुलकर भ्रष्टाचार करते हुए बिना किसी जांच पड़ताल की नौकरी कर रहे हैं। प्रधान सचिव राजेश राजौरा इसके पहले भी लोकायुक्त की जांच में उलझे रहे बाद में ले देकर मामले को ठंडा किया गया। राजेश राजौरा की नीमच और उसके आसपास

> तत्काल 100 से ज्यादा सहायक, 20 उप, 5 संयुक्त व संचालक तक सबको बदला जाए , जो 5 वर्षो से ज्यादा एक ही जगह पर जमे हुए हैं और घोर भ्रष्टाचार अंजाम दे रहे हैं। वैसे तो पूरे विभाग के कृषि विस्तार अधिकारियों से लेकर ऊपर तक सबको बदला जाना चाहिए।

के प्रदेश के और राजस्थान के जिलों में पिछले 20 वर्षों में अपने आप अपनी पत्नी के रिश्तेदारों के नाम से कितनी जमीन और संपत्तियां खरीदी गई उसकी जांच भी लोकायुक्त से गोपनीय रूप से करवाई जानी चाहिए तब राजोर का भ्रष्टाचार सामने आएगा।

इसके साथ ही दो-तीन बार निलंबित किया गया इंदौर के उपसंचालक विजय चौरसिया जो कि राजोरा का खास एजेंट बनकर, सारे विक्रेताओं से वसूली करता, यहां बैठा हुआ है। राजोरा के भ्रष्टाचारों के संबंध में विस्तार से जानकारी जो कि समय माया ने पिछले कई वर्षों से छापी हैं। पुराने समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं। जो कि www.samaymaya.com के ईपेपर पर देखी जा सकती है।वर्तमान में 51 जिलों में बैठे हुए अधिकांश उपसंचालक जो कि घोर भ्रष्टाचार के आरोपों में घरि में होने के साथ-साथ राजोरा को मोटी रकम देकर मासिक रॉयल्टी पर कार्य कर रहे हैं। जो यह सब नहीं कर पाता उन्हें आत्मा में बैठा दिया जाता है। इंदौर का उपसंचालक विजय चौरसिया जो तीन तीन बार निलंबित हो जाने के बाद में भी मोटी रायल्टी के लिए पुनः इंदौर में पदस्थ कर दिया गया। वही हाल देवास के उपसंचालक सुभाष राजपूत का भी है। जो बैतूल में अनेकों कांड करके आया था। अधिकांश उपसंचालको और सहायक संचालकों पर अनेकों भ्रष्टाचार के आरोपो की जांच लंबित हैं। कई बरसों से परंतु मोटा धन मिलने के कारण राजोरा ने उनको दबाकर रखा हुआ है। अधिकांश भूमि संरक्षण अधिकारी रहे जो वर्तमान में जिलों के उपसंचालक पदों पर पदस्थ हैं। अनेकों पर सैकडों तालाब चोरी होने के कांडों की जांच लंबित है। कृषि मंत्री को चाहिए पिछले 15 सालों में 33% से लेकर 75% अनुदान पर खेत का पानी खेत में और बलराम तालाब के जिसके अंतर्गत प्रदेश में हर जिले में हजारों तालाब बनाये गये थे जिनमें से 25% से 75% तालाब चोरी हो गये। की बारीकी से जांच करवाई जाए। भारत में कृषि सहस्त्रों बरसो से ही कृषि की इस अवधारणा जिसमें किसान कर्ज में जन्म लेता है जीता है और कर्ज में ही मर जाता है। आजाद भारत के पिछले 70 सालों के इतिहास से लेकर वर्तमान में भी पूरे देश मैं लाखों और प्रदेश में हजारों किसानों की हर वर्ष आत्महत्या इस सत्य का औचित्य सिद्ध करती है। निःसंदेह जब कोई किसान आत्महत्या करता है और उसके समाचार समाचार पत्रों, दृश्य श्रव्य श्रृखलाओं में प्रकाशित होते हैं या दिखाये जाते हैं। तो सामने भले ही मुझ जैसे आमजन के आंसू भले ही ना निकलते हो। पर दिल कहीं ना कहीं तो अपने अन्न दाता की ऐसी असामयिक व अकाल मृत्यु को देख कर कसक से भर उठता है। इसके संबंध में मस्तिष्क में अधिकतम बेहतर करने के लिए काफी लंबे समय के अध्ययन के परिणाम स्वरूप यह निष्कर्ष निकाला गया। की किसान तो पूरी मेहनत करता है। अच्छे से अच्छा खेतों की जुताई, बखराई, निराई, गुड़ाई करता है। फिर साथ ही में अपने कर्ज से लिए हुए धन से अच्छे से अच्छा बीज, खाद, कीटनाशक, खरपतवार नाशक आदि का प्रयोग कर अपनी मेहनत से अच्छी से अच्छी फसल तैयार करने का प्रयास करता है। इसके विपरीत उसे मनचाहे परिणाम नहीं मिलते और फसल बिगड़ जाती है। नकली, स्तर हीन बीज, खाद आदि का प्रयोग करने से जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है। शासकीय कृषि विभाग और उसमें बैठे नीचे से ऊपर तक घोर भ्रष्ट जाल साज मक्कार और डकैतों की फौज जो किसानों के साथ हर कदम पर छलावा करती है। निसंदेह सरकार की तरफ से कृषकों को वर्तमान में जो सुविधाएं मिल रही है। उसके पहले उतनी कभी नहीं मिली थी। अधिकतम अनुदान खाद बीज पर, फसल बिगड़ने पर बीमा, फसल का कम दाम पर बिकने पर भावांतर से किसान की हर तरह से हानि की भरपाई करने की कोशिश की जाती है। सरकार की तरफ से केंद्र व राज्यों में कृषि को लाभ का धंधा बनाने, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अच्छी योजनाएं बनाई जाती है। अच्छे नियोजन किए जाते हैं। इसके विपरीत अच्छे परिणाम सामने ना आने के कारण, कारणों में जो कृषि विभाग में बैठे प्रधान सचिव संचालक संयुक्त संचालक उप संचालक सहायक संचालकों वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारियों ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों निरीक्षकों की मोटी कमाई जो की पूर्णतः जालसाजी से घटिया बीज, घटिया खाद महंगे दामों पर दिलवाई जाती है। जिसके मूल में होते हैं। कृषि निरीक्षक, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारियों से लेकर सहायक संचालकों, उपसंचालक, संयुक्त संचालक, संचालक और प्रधान सचिव जो मोटा कमीशन लेकर ऐसे उत्पादकों को अनुज्ञप्ति जारी कर अपना माल उत्पादन व बेचने का अधिकार दे देते हैं। जिससे किसान हर कदम पर ठगा जाता है परिणाम स्वरूप अच्छी फसल ना मिलने के कारण या फसल बर्बाद हो जाने के कारण इसलिए किसान अंत में कर्ज ना चुका पाने के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। यह निष्कर्ष मैंने बीज उत्पादक सोसायटीयों, घटिया, समयबाधित, बीज पेकिंग करने वाली कंपनियों, स्तरहीन खाद उत्पादकों, घटिया, समयबाधित, कीटनाशकों आदि का बढ़ाचढ़ाकर विज्ञापन करने वालों का माल गांवों में किसानों को बेंचने के कारण होता है। जिनके उत्पादन और बिक्री के लायसेंस व नवीनीकरण उप संचालक जिला कृषि अधिकारीयों द्वारा मोटे कमीशन पर आंख मींचकर बांटे जाते हैं।

साप्ताहिक समय माया

मुमं नाथ को चाहिए तत्काल रद्द करें निजी कंपनी से बिजली खरीदी के समझौते

लाखों करोड़ बर्बाद किए हजारों करोड़ की कमाई कर जनता को लूटा

पिछले 15 वर्षों के बिजली, उत्पादन व वितरण के रखरखाव की खरीदी और बिक्री के सौदों की हो तत्काल जांच। तत्काल सारी कंपनियों को बंद कर पुनः मंडल को जीवित करें। ताकि भविष्य में प्रदेश की जनता और उद्योगों को सस्ती व 24 घंटे 12 महीने आधारभूत आवश्यकता बिजली की आपूर्ति होती रहे।

भारत में 1999 से 2004 तक सत्ता संभालने वाली भाजपा ने हीं जिस तरह से पूरे देश के प्रदेशों के शासकीय विद्युत मंडलों को अपनी मोटी कमाई के लिए देसी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मोटा धन डकार कर निजी कंपनियों की लूट के लिए अरबों करोड रुपए की संपत्तियों के मालिक शासकीय मंडलों को जो कि 50 वर्षों में पूर्ण रूप से स्थापित हो सुचारु रूप से चल रही थी। कंपनियों में बदल कर उसने यथार्थ में जनता और औद्योगिकरण की आधारभूत आवश्यकता बिजली के माध्यम से एक तरफ कई गुना ज्यादा जनता से लूट और वसूलने के लिए तो दूसरी तरफ शासकीय अरबों करोड़ रुपए की संपत्तियों को हजम करने का षड्यंत्र रचा गया। जो सफलतापूर्वक भुखेरा जानवर पार्टी के नेताओं की हजारों करोड रुपए प्रतिदिन कमाई का साधन बन गया । इस षड्यंत्र को नई कांग्रेसी सरकार को तत्काल जनता के सामने लाकर खत्म कर मंडल को पुनर्स्थापना कर देनी चाहिए।

बिजली में हजारों करोड़ रुपए प्रतिदिन 14000 मेगावाट बिजली खरीदने में जोकि ताप विद्युत सौर ऊर्जा और पवन विद्युत की निजी क्षेत्रों से खरीदी में की जाती है। तत्काल रद्द की जानी चाहिए। इससे पहले विद्युत मंडल की पांचों कंपनियों को समाप्त कर पुनः विद्युत मंडल बना दिया जाना चाहिए। जो ताप विद्युत के पावर प्लांट्स और जल विद्युत के बांधों पर बने विद्युत उत्पादक केंद्र हैं। उनको पूरी क्षमता से चलाया जाना चाहिए ताकि निजी क्षेत्र से खरीदी जाने वाली विद्युत खर्च किया जाने वाला धन की बर्बादी को रोका जा सके। और प्रदेश की जरूरतों को अपने स्त्रोतों के इसमें ताप विद्युत व जल विद्युत उत्पादन केंद्रों के पूरी क्षमता से चलाने पर 15000 मेगा वाट के आसपास पर्याप्त विद्युत मिल सकती है।प्रदेश का उच्च उपयोग क्षमता 12500 से 13000 मेगावाट जनवरी-फरवरी में सिंचाई के सीजन में होता है। जो कि अपनी स्त्रोतों से प्राप्त विद्युत से पूरा हो जाएगा। जिसे उन्होंने अभी या तो कई स्थानों पर बंद कर दिया है जिसमें गांधी सागर इंदिरा सागर ओम्कारेश्वर और बरगी पर न्यूनतम उत्पादन कर उसे घाटे में चलाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर बिरसिंहपुर पाली संजय ताप विद्युत केंद्र सारणी सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र खंडवा आदि है।

अपने हिस्से की बिजली राष्ट्रीय ताप विद्युत और जल विद्युत से खरीदने के साथ मध्यप्रदेश में की जा रही उत्पादन की इकाइयों से अधिकतम बिजली का उपयोग किया जाए जो न्यूनतम कीमत पर सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार को मिलेगी।

इसलिए तत्काल में ही निजी क्षेत्रों के ताप, सौर व पवन विद्युत को खरीदने के सारे सौदे रद्द कर देना चाहिए। जिन पर हजारों करोड़

प्रतिदिन सरकार को खर्च करना पड़ रहा है। इसमें आसानी से वित्तीय भार कम होने के साथ विद्युत से आय के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो जायेंगे। दूसरी ओर विद्युत मंडल के सभी कंपनियों में जो आउटसोर्सिंग से व ठेका सेवाएं लेने का काम चल रहा है। उसको तत्काल रोका जाए उससे दीर्घकालीन विद्युत मंडल की कार्यक्षमता ना केवल कम हो रही है। वरन भारी वित्तीय भार भी आ रहा है। और मंडल का वितरण आपूर्ति और उत्पादन का कार्य भी रखरखाव की दृष्टि से काफी बिगड़ चुका है। न केवल विद्युत पारेषण के हाईटेंशन लाइन के 132 केवी 66kv के टावर लाइनों के खंभों तक की क्युप्रस ऑक्साइड व एल्यूमीनियम पेंट तक की पुताई पिछले 12- 15 सालों से नहीं हुई और उसका खर्च दिखा कर पैसा हजम कर लिया गया जो कि सैकड़ों करोड़ में था। यह सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता इस बात की है। की तत्काल सभी वितरण कंपनियों में हेल्पर से लेकर मीटर रीडर, लाइनमैन उपयंत्री सहायक यंत्री तक की स्थाई नियुक्तियां की जानी चाहिए। जिसका मूल उद्देश्य कम से कम स्थाई कर्मचारियों पर वेतन बच्चों का भार ना आए परंतु जो ठेकेदारी प्रथा में हाल सभी उच्च दांव से निम्न दाव की 132 केवी, 66केवी, 33केवी के सब स्टेशनों पर लगे ट्रांसफार्मर खंभों स्टेशनों के रखरखाव की हालत को देखकर मालूम किया जा सकता है जो कि इन्होंने पिछले 15 सालों में पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जिस तत्काल उस पर उच्चस्तरीय रखरखाव की प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता है जो कि विद्युत मंडल ही कर सकता है कंपनियों में बैठे अधिकारियों को नोचने और खाने से ही फुर्सत नहीं मिली।

काम कर रहे हैं। वही कर्मचारी सबसे ज्यादा उपभोक्ताओं के साथ मिलकर भारी चोरी और डकैती या करवा रहे हैं। जिसमें यह स्थाई अधिकारी उपयंत्री सहायक यंत्री जो दीर्घ समय तक एक ही जिले में रहकर इन अस्थाई कर्मचारियों के साथ मिलकर खूब लूटपाट करवाते हैं। बेशक जो इमानदारी से बिल भरते हैं। यह अस्थाई कर्मचारी अपनी कमाई के लिए भारी परेशान कर उनके भारी भरकम बिल तैयार करवाते हैं चाहे वह एक या दो एलइडी बल्ब का ही उपयोग क्यों ना कर रहा हो उनके बिल हजारों में आते हैं जो एक तरफ जनता के आक्रोश का कारण बनते हैं तो दूसरी तरफ विद्युत वितरण कंपनियां बेईमान सिद्ध होती है। कंपनियों का इसका भारी-भरकम खामियाजा भुगतना पड़ता है। बार बार अनावश्यक रूप से अपनी मोटी कमाई के लिए बहाने बना कर उपभोक्ताओं को परेशान करने के लिए मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल फिर इलेक्ट्रॉनिक और अब स्मार्ट मीटर लगाकर विद्युत कंपनियां अपनी डकैती और लूट को छुपाकर वहां के कर्मचारी अधिकारी जो आउटसोर्सिंग से काम करवा रहे हैं। वह विद्युत कंपनियों की बर्बादी का कारण बन रही है। इसलिए स्थाई कर्मचारीयों की नियुक्तियां की जाएं ताकि ऊन पर आसानी से कार्यवाहीयां की जा सकें। दूसरी ओर किसी भी हाल में सेवानिवृत्त इंजीनियरों को समय विस्तार देने की अपेक्षा कनिष्ठों को पदोन्नत कर खाली पदों को भरॉ जाना चाहिए। पुराने घाघ सेवानिवृत्त इंजीनियर मोटा धन खर्च कर ही संविदा पर रखा जाता है वह जानता है की वो कतिना भी भ्रष्टाचार करें। कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा ज्यादा से ज्यादा उसे नौकरी से हटाया जा सकता है इसलिए उन सबको संविदा पर यह भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारी जानबूझकर इसीलिए पदों पर नियुक्त करते हैं ताकि उनके माध्यम से ही आसानी से खुलकर भ्रष्टाचार कर धन डकारने मे उन पर आंच नहीं आती और वह भी आसानी से हजारों करोड डकार कर स्थानांतरित हो कर चले जाते हैं। फिर यहां बैठा पुर्व का घोर भ्रष्ट सुब्रतो राय जो पहले सन 2002-3 में निलंबित कर यहां से हटाया गया था। अपनी नेता पत्नी के दम पर पुनः इंदौर में सालों से जमा हुआ है। वैसे उसकी बदतमीजी के चलते उसे जनता ने हीं घेर कर पटिाई कर दी है।

इसे तत्काल संभाला और मजबूत किया जाना चाहिए जिससे आउटसोर्सिंग में ठेकेदारों ने और कंपनियों के स्तर पर काम होने के कारण वहां बैठे घोर धूर्त गैर तकनीकी प्रबंध संचालकों, सहा संचालकों जोकि आईएएस हैं अधिकारियों ने हजारों करोड़ प्रतिमाह की व्यक्तिगत कमाई के लिए उसको आत्यधिक कमजोर कर दिया है।

कंपनियों को समाप्त करने से तत्काल सैकड़ों करोड़ रुपए की प्रति महा बचत होने से और निजी क्षेत्रों से बिजली खरीदी को खत्म कर देने से हजारों करोड रुपए प्रतिमाह की सीधी बचत होगी जिसका लाभ प्रदेश के एक करोड़ से ज्यादा घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक व कृषि उपभोक्ताओं को सस्ती व 24घंटे आपूर्ति से हर स्तर पर मिल सकेगा।

म प्र के ऐतिहासिक घोर भ्रष्ट सुधीरंजन मोहंती नए मुख्य सचिव

नाथ द्वारा नियुक्त मुख्य सचिव, जन कल्याण नहीं, वसूली के लिए

भारतीय प्रताड़ना सेवा अधिकारी मोहंती पूर्व में 20 वर्ष इंदौर कलेक्टर भी रह चुका है। कलेक्टर रहते हुए उसने खूब भूमाफियाओं कॉलोनी माफियाओं के साथ मिलकर अवैध जमीनों का काफी धन कमाकर खुले में भू माफियाओं और कॉलोनी माफियाओं को मनमानी करने कॉलोनी काटने खूब छूट दी। जिसका परिणाम स्वरूप इंदौर के चारों तरफ शासकीय तालाबों की जमीनों जिसमें पिपलियाहाना तालाब, धार रोड, देवास रोड का मंगलिया का तालाब खंडवा रोड का तालाबों पर व अन्य अनेकों शहर के व आसपास के तालाबों पर कालोनियों का निर्माण इन्हीं की सरपरस्ती में हुए। ये जिस2 विभाग में पदस्थ रहे। घोर भ्रष्टाचार किया। इसलिए दिग्गी के विशेष प्रिय रहे और खुद भी कमाई की। दिग्गी को भी खूब कमा कर दिया।

प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्य सचिव के पद पर बैठाये गये मोहंती इंदौर से जिलाधीश पद से स्थानांतरित होकर भोपाल में जनसंपर्क का आयुक्त बना दिया गया। जहां खूब अपने ही विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों को जिनकी अपनी पत्रिकाएं पत्र छपते थे उन्हें और साथ में खास लोगों को विज्ञापन बांटने के नाम पर खूब कमीशन बटोरा गया।

औद्योगिक केंद्र विकास निगम का का प्र सं बनाया गया। उसमें भी 6.5 सौ करोड के घोटाले का केस लोकायुक्त से लेकर उच्च न्यायालय तक में जहां धन, बल, छल के दम पर उच्च व सर्वोच्च न्यायालय की परंपरिक प्रथाओं के अनुकूल निर्दोषता प्राप्त कर ली गई। फरि प्रदेश में 30 से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में निर्माण कार्यों में भारी घोटाले हुए जिसमें भवनों के निर्माण सडक़ों, बिजली, पानी की आपूर्ति में भारी घोटाले किए गए और काफी पैसा हजम किया गया। उद्योग पतियों से हर कदम कदम पर वसूली वाह भ्रष्टाचार के कारण वर्तमान में प्रदेश भर के औद्योगिक क्षेत्रों में, 40% से ज्यादा उद्योगपतियों को ताले लगाकर प्रदेश छोड़कर भागना पड़ा। यह सारी बातें इसलिए सामने नहीं आई कि सभी ने मिल बांटकर खाया। उसके बाद महिला बाल विकास के आयुक्त भी रह चुके हैं। मोहंती। यह सारी कहानी का सच गूगल पर पैसे खर्च करके वहां से भी हटा दिया गया। जब यह सच श्री अजमेरा ने व्हाट्सएप पर प्रदेश के 800 से ज्यादा पत्रकारों को भेजा तो स्वाभाविक था पदभार ग्रहण करने के पहले मोहंती पत्रकारों से यहां वहां मुंह छुपाते घूमते रहे। इसके विपरीत कमलनाथ ने सारा इतिहास जान कर भी दिग्विजय सिंह के इशारे पर मोहंती को ही मुख्य सचिव नियुक्त किया जो यह सिद्ध करता है कि आने वाले भविष्य में प्रदेश में भ्रष्टाचारियों को भरपूर सरंक्षण मिलेगा। प्रदेश में भ्रष्टाचार फलेगा फूलेगा। तत्काल में इसके परिणाम सामने भी आ चुके हैं। खुलकर सभी विभागों के मंत्रियों ने 10 साल से ज्यादा समय से बैठे अधिकारियों कर्मचारियों, इंजीनियरों, डॉक्टरों, खाद्य एवं औषधि, श्रम, वाणिज्य कर, राजस्व, पुलिस, आबकारी, परिवहन, खनन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, पालिका, पंचायत आदि के निरीक्षकों, मोटा धन वसूल कर सबको अभय दान दे कर बैठा दिया गया।

महिला बाल विकास में भी सब जानते हैं की 61 हजार आंगनवाड़ियों में वर्तमान में भी जो बच्चे पंजीकृत हैं। जिनके नाम से भोजन और खर्च निकाला जाता है। उसके कुल पंजीकृत संख्या की 5% बच्चे भी आंगनवाड़ियों में नहीं जाते हैं। शहरों में तो हालत यह है, कि एक ही बच्चा अनेकों आंगनवाड़ियों पंजीकृत होता है। वही हाल गरीब और गंदी बस्तियों की गर्भवती महिलाओं की खाद्य एवं पोषण आहार के मामले में भी होता है। एक ही महिला अनेकों आंगनबाड़ियों में पंजीकृत होती है। अधिकांश आंगनबाड़ियों नेताओं पार्षदों की खास लोगों के हाथ में होती हैं। उनका सारा पैसा नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे तक हजम कर लिया जाता है। निसंदेह कांग्रेस ने 15 साल का बनवास भोगा है। आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ी हुई है। तो कमाई करने के लिए ऐसे ही भ्रष्टों की आवश्यकता है। बेशक सत्ता का वो खिलाड़ी 15साल पूर्व मुख्यमंत्री रह चुका दिग्गी सारा खेल खेल रहा है। यह सब तो प्यादे हैं। जिन्हें वह अपनी उंगलियों पर नचा कर अपने भाई और बेटे को मुख्यमंत्री कार्यालय में जमा कर कमलनाथ को कमल का ही नाथ बना कर छोड़ेगा। यदि सरकार बची रही तो भी दिग्गी के हस्तक्षेप से भरोसा नहीं 5 साल के बाद पुनः कांग्रेस सत्ता में लौट सकेगी।

शांति से देखिए, अभी तो शुरू हुआ है

दिग्विजय सिंह कमलनाथ की सरकार चलने नहीं देगा उसका मुख्य सचिव सुधिरंजन मोहंती घोर भ्रष्ट जाल साज होने के साथ-साथ घोर निकम्मा भी है।

इस प्रकार दिग्विजय सिंह ने 15 वर्ष पूर्व खुद को प्रदेश की सरकार और जनता को बर्बाद किया। उसका साया कमलनाथ को भी वैसे ही बर्बाद करेगा अभी उसने अपने बेटे और भाई को मुख्यमंत्री कार्यालय से चिपका रखा हुआ है। कर्मकांड और बर्बादी करेगा दिग्विजय सिंह और बदनाम होगा कमलनाथ और कांग्रेसी, जो 6 महीने भी सत्ता नहीं चलने देंगे। भाजपा केवल लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रही है। अगर फिर भाजपा आई तो जुलाई के बाद कांग्रेस के 10 असंतुष्ट विधायकों को खरीद सत्ता पुनः भाजपा की होगी। वैसे भी सत्ता संभाले अभी 50-60 दिन भी नहीं हुए और कांग्रेसियों की सत्ता में अंधेरों का स्वागत करना शुरू कर दिया है। हर दिन बिजली 1- 2 घंटे के लिए जाने लगी है।

साप्ताहिक समय माया

वाणिज्य कर के अधिकारियों ने पिछले 20 साल में लगभग रुपए 2 लाख करोड़ डुबोये

सैकड़ों करोड़ की मोटी कमाई की, हजारों फाइलें जलाई, बंद करो स्वकर निर्धारण

विश्व की अर्थव्यवस्था में, दुनिया के कोई से देश की भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो कर संग्रहण किया जाता है कहीं पर भी 100% पूरा प्राप्त नहीं होता। फरि भारत में तो विभागीय कर अधिकारी स्वयं कानूनों का अध्ययन कर चोरी के रास्ते विकसित कर करदाता को बता कर कर चोरी करवा कुल कर चोरी का 10 से 20 परसेंट हजम कर जाते। यह कटु सत्य है। वर्तमान सरकार पिछले 20 साल की सभी व्यापारियों की डूबंत और स्वकर निर्धारण की फाइलें, खुलवा कर तरीके से वसूली की जाए तो सारा कर्ज खत्म होने के साथ पर्याप्त खजाना भर जाएगा। पिछले 40 सालों से हर साल मात्र वृत्ति कर में ही पूरे प्रदेश में लगभग रु2से3 हजार करोड वसूले नहीं जाते बदले में अधिकारी मोटी रकम हजम कर जाते हैं। एजी एमपी कि पिछले 10 साल की रिपोर्ट तो यही कहती है। पूरे प्रदेश के 35 टोल नाके फिर शुरू करवा दीजिए फिर देखिए। साथ ही 3 से ज्यादा बरसों से जमे उपायुक्तों, सहायक आयुक्तों, सहायक व वाणिज्य कर अधिकारियों को शीघ्र स्थानांतरित किया जाना चाहिए। जो हर साल सैकड़ों करोड़ की कमाई के लिए सरकार का हजारों करोड डूबा देते हैं।

प्रदेश की नई सरकार को खजाना खाली होने कारण आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। जबकि इसका बहुत साधारण सा हल है। सबसे पहले सभी उपायुक्तो, सहायक आयुक्तो, वाणिज्य कर अधिकारियों सहायक कर अधिकारीयो का तत्काल स्थानांतरण किया जाना चाहिए। जो 3 वर्षों से ज्यादा समय से एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं। जिसमें इंदौर के संभाग 3 में 8 वर्ष से बैठा हुआ घोर भ्रष्ट जालसाज उपायुक्त अब्दुल मजीद, जैसे भोपाल ग्वालियर एसके श्रीवास्तव, जबलपुर में नारायण मिश्रा ,सतना आर के सलूजा, रतलाम में आरके तिवारी आदि विभाग में वर्षों से भ्रष्टाचार करते हुए एक ही स्थान पर कुंडली मारे, महीना खर्च करते बैठे हुए हैं। जो वर्तमान में स्वकर निर्धारण की पिछले 10 सालों से ज्यादा समय से प्रक्रिया चल रही है, को तत्काल रोक दिया जाए पिछले 20 सालों की सारी हजारों करोड़ रुपए की फ़ाईलें खोलकर पुनःकर निर्धारण कर वसूली की जानी चाहिए जिसे जानबूझकर जीएसटी लगाने के चक्कर में खत्म कर दिया गया था। 2006--7 मे पकड़ा गया रू 700 करोड़ का पेट्रोलियम घोटाला, धन की बंदरबांट कर फाइलों में दफन हो कर रह गया। वर्तमान में बैठे 20 से ज्यादा उपायुक्त जिन पर अनेकों जांचे लंबित है। एक ही स्थान पर बरसों से कुंडली मारे बैठे हुए हैं। जो एक बार 3 साल से ज्यादा इंदौर में रह चुके हैं। उन्हें पुनः इंदौर में पदस्थी नहीं दी जानी चाहिए। सभी अधिकांश अधिकारियों पर जो पुरानी भ्रष्टाचार की जांच लंबित है। खोलकर सभी अधिकारियों को सजा दी जानी चाहिए बेशक यह संभव नहीं क्योंकि सभी भ्रष्टाचार की काली कोठरी में निवासरत है। इसलिए सब एक दूसरे को बचाने में लगे रहते हैं।

घोर भ्रष्ट संभागायुक्तो द्वारा बिना वृत्ती कर की वसूली किए जा रहे कर निर्धारण

सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर, जानबूझकर अपने लूट, भ्रष्टाचार को छुपाने अपने अधीनस्थों को धारा 6(3) में पत्र अंतरति करने की अपेक्षा हरामखोरों की फौज अधिकांश उपायुक्त जानकारी देने की अपेक्षा 4-4 पेज की दलीलों के जवाब भेजते हैं। मध्य प्रदेश महालेखाकार द्वारा किए गए वर्ष11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16,16-17 की अंकेक्षण रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया कि प्रदेश के किसी भी उपायुक्त ने जानबूझकर अधिकांश सार्वजनिक कंपनियों, निजी कंपनियों, शराब व्यवसायियों, अहाता संचालकों, सिनेमा संचालकों, होटल मालिकों, रेस्टोरेंट, सभी प्रकार की सेवा प्रदाता कंपनियों जिसमें सेलफोन, डिस्क ऑपरेटर्स, कोचिंग संचालकों, स्कूल एवं कॉलेज के शिक्षक व्याख्याता, वकीलों, बीमा प्रतिनिधियों, सभी निजी्अस्पतालों के डॉक्टर, आदि सभी को वृत्ति कर वाणिज्य कर विभाग को भुगतान किया जाना चाहिए। इसके संबंध में मध्यप्रदेश की लोक लेखा समिति मैं यह बात विधानसभा में भी रखी गई और संबंधितों से पूछताछ और वसूली के लिए वाणिज्य कर आयुक्त को भी बार बार लिखा गया परंतु किसी ने भी रु300 करोड़ से ज्यादा की वसूली पर प्रदेश के उपायुक्तो से लेकर आयुक्त वाणिज्य कर अधिकारियों सहायक अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी क्योंकि सभी ने अपनी अपनी मोटी वसूली पहले ही कर ली थी। जबकि सभी संस्थानों की वाणिज्य कर निर्धारण की प्रक्रिया में वृत्ति कर की वसूली को भी शामिल कर वसूली करना आवश्यक होती है।

पूरे मध्यप्रदेश में 80 से ज्यादा वाणिज्य कर अधिकारियों, सहायक आयुक्तों उपायुक्तों ने कर वसूली मैं कुर्क की गई संपत्तियों की पिछले 20 सालों में 90% संपत्तियों की अभी तक नीलामी नहीं की। जिसमें शासन का अरबों रुपए का धन पिछले कई सालों से अटका हुआ है। इसके विपरीत सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर अधिकांश कर वसूली वाले अधिकारियों से लेकर उपायुक्तों तक सभी जानकारी देने की अपेक्षा हरामखोरों और जालसाजों की फौज,पूरे देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों के संदर्भों की 5--5 पेज की दलीलें देते हैं। परंतु जानकारी देने के नाम पर अपने कुकर्मों का भंडाफोड़ ना हो।इसलिए जानकारी नहीं देंगे। दूसरी तरफ इस कार्य में हर दो-तीन साल में बदल जाने वाले वाणिज्य कर आयुक्तों को भी महीना मिलने के चलते अन्ध सहयोग रहता है। इसलिए उसने भी जानबूझकर अपने 20 से ज्यादा उपायुक्तों को बचाने उपायुक्त कार्यालय में उपायुक्तों को ही अपीलीय अधिकारी बना दिया गया।जब कार्यालय प्रमुख ही अपने विभाग का अपीलीय अधिकारी होगा। तो कौन मूर्ख अपने अधीनस्थ कार्य कर रहे सहायक आयुक्त को अपने बारे में जानकारी देने में सहयोग करेगा फिर अपील लगाने पर, अपने खिलाफ ही अपनी अपील सुनकर तथ्यों के परे जाकर उसे विभिन्न कारणों को आधार दिखाकर 90% अपने जो स्वयं के खिलाफ होती हैं। रद्द कर देते हैं। और जानकारी देने से बच जाते हैं।वर्तमान वाणिज्य कर आयुक्त महोदय को शीघ्र बदलना चाहिए। संभागीय उपायुक्तों को लोक सूचना अधिकारी बना कर उसकी अपील को उसके वरिष्ठ संचालक अपर आयुक्त कोसुनवाई के लिए देना चाहिए बेशक वर्तमान में बैठा संचालक मरावी जिस पर विभाग द्वारा एफआईआर करवाई गई है। बेशक है, तो वह भी घोर धूर्त और जालसाज, अपने अधिकारियों को बचाने के लिए सारी अपील है रद्द कर देता है और बदले में मोटा धन ऐंठ लेता है। 13 साल के बाद में भी आज तक विभाग ने धारा 4 के अंतर्गत अपनी कोई भी जानकारियां, खरीदी, कर्मचारियों अधिकारियों के विवरण संपत्ति के, करना देने वाली फर्मो और पार्टियों आदि की जानकारी अभी तक विभागीय पोर्टल पर अपलोड नहीं की ताकि हर कदम मुख्यालय से लेकर प्रदेश के 80से ज्यादा वृतों में हो रहे भ्रष्टाचार और निरीक्षक से लेकर आयुक्तों तक के कर अपवंचन करने वालों से वसूली की कहानी जन सामान्य तक ना पहुंच जाए।।

जबकि व्यापारी ने जनता से विक्रय कर की वसूली कर ली होती है और दूसरी तरफ वह धन जो शासन का था उसे वहीं अधिकारियों के साथ मिलकर 10--20% में आसानी से अपनी भारी करारोपण की फाइलें जलवा कर बचकर निकल लेता है। जिससे जनता को दुगुनी रानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि एक तरफ उसकी जेब से व्यापारी करों के नाम पर वसूली कर लेता है। दूसरी तरफ कर शासन के पास ना पहुंचने पर जनता के आवश्यक विकास कार्यों में धन की परेशानी से कार्य नहीं हो पाते हैं। समय पर।

कर निर्धारण कर वसूली की जानी चाहिए जिसे जानबूझकर जीएसटी लगाने के चक्कर में खत्म कर दिया गया था।

वर्तमान में कार्यरत रतलाम संभाग उपायुक्त आर के तिवारी जिसने शासन का अरबों रुपए डुबोकर करोड़ों की कमाई की 17 साल तक इसी आरोप में सहायक आयुक्त पद पर ही बैठा रहा वर्तमान में 4 साल से ज्यादा समय से रतलाम संभाग में बैठा रह कर 8 से ज्यादा बड़े प्रदेश के बड़े वृत्तों जिसमें रतलाम में एक व दो, ब्यावरा, नीमच 1-2, मंदसौर 1-2, झाबुआ से मोटी वसूली कर रहा है। यही हाल उपायुक्त आर के सलूजा जो की सतना में वर्षों से कुंडली मारे बैठा रह कर सतना 1,2, कटनी, रीवा, बैढ़न, सीधी, शहडोल आदि से मोटी वसूली कर रहा है। वही हाल ग्वालियर भोपाल आदि के उपायुक्तों का भी है।

पुरानी भाजपा सरकार में रहते हुए शिवराज ने सभी शासकीय विभागों के सैकड़ों करोड़ के सॉफ्टवेयर बनवाने के ठेके मोटे कमीशन पर सैकड़ों करोड़ में टाटा कंसलटेंसी को दिए थे। जिसमें वाणिज्य कर विभाग भी था। जो सॉफ्टवेयर की सीडैक मात्र रु25लाख मै बनाया था। जो कि उनके अधिकारियों और कर्मचारियों ने ही बना कर सफलता के साथ विभाग को चलाकर सौंप दिया था। परंतु टीसीएस को वेट का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए रु25 करोड़ 100 गुना में दिया गया। जबकि उसने मुख्यालय इंदौर में अपने लिए दो बड़े कमरे बुक कर रखे थे जो आज भी उसी के पास में है। दूसरी तरफ विभाग के दो उपायुक्तो और अनेकों अधिकारियों व कर्मचारियों का उपयोग अपने सॉफ्टवेयर बनाने में किया इसके विपरीत वह सॉफ्टवेयर 8 साल तक कभी भी ढंग से काम नहीं किया। विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को भारी परेशानियों का कारण बना कभी भी सफलता के साथ उपयोग नहीं कर पाए। जिसका वेट का सॉफ्टवेयर कभी पूरा नहीं हुआ। जिसने 25 करोड़ के सॉफ्टवेयर की आड़ में रु 200 करोड़ का हार्डवेयर अपनी सहयोगी टयूलिप कंपनी से पूरे प्रदेश में 10 गुना ज्यादा कीमत में लगवाया इसकी भी जांच बारीकी से नाथ सरकार को करवानी चाहिए।

जब जीएसटी के अंतर्गत सारा काम कंप्यूटर के माध्यम से स्वयं व्यापारी ही कर लेता है और वर्तमान में उपायुक्तों से लेकर निरीक्षक तक कोई भी काम सीधे वसूली के लिए सौंपा ही नहीं जाता। इसलिए सीधे कोई भी अधिकारी बाजार में जाकर व्यापारियों, फर्मो, दुकानों शोरूम आदि पर जांच और पूछताछ का अधिकार नहीं रखता। तो आखिर क्यों वाणिज्य कर अधिकारी, सहायक, आयुक्तो, उपायुक्तों पर शासन उनके वाहन का करोड़ों रुपए प्रतिमाह का प्रदेश भर में खर्च वहन करता है। जबकि सबको नगर भ्रमण भत्ता मिलता है। इन सब के वाहनों को तत्काल हटाया जाना चाहिए जिससे शासन को करोड़ों रुपए प्रतिमाह की बचत होगी। दूसरी तरफ सच यह भी है। अधिकांश वाणिज्य कर अधिकारी सहायक आयुक्त उपायुक्त बड़े जिलों जिसमें भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर में रहते हैं।प्रतिदिन आसपास के जिलों से जहां उनकी पदस्थापना है। दैनिक आना जाना करते हैं जिसका खर्च शासन को भुगतना पड़ता है। आखिर जनधन का ऐसा दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है सारे वाहनों को उनके शासन के साथ हुए समझौते को समाप्त कर बंद कर दिया जाना चाहिए।

कोई भी राष्ट्र गंभीर नहीं विश्व के पर्यावरण को सुधारने और बचाने में

पेज 1 से जारी

भारत में चाहे बीज अधिनियम 1966, कीटनाशी अधिनियम 1968, एकाधिकारी एवं प्रतिबंधित व्यवसाय गतिविधि अधिनियम 1969, आयोडीन नमक अधिनियम1972 से लेकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तक बनाये , लगाये व देश की जनता पर थोपे गये सारे कानून बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इशारे पर मोटा पैसा हजम कर तत्कालीन सरकार ने बनाये। सभी कानूनों का उद्देश्य देशी व बहुराष्ट्रीय कंपनियों उनके पूंजीपतियों के मोटे लाभ को सुनिश्चित कर जनता को ना केवल उसके पारंपरिक स्वास्थ्यवर्धक खाद्य प्रणाली से वंचित व बर्बाद कर शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर कर बीमार बनाना था और उसमें वे सफल भी रहे। वर्तमान में हालात ये है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दमा, अस्थमा, मधुमेह, हृदय रोगियों, यकृत, प्लीहा, कर्कटार्बुद पीड़ितों का देश बन चुका है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों के कारण राष्ट्र की आबादी के 90% लोग पेट के रोगों से पीड़ित है जो बाद में बड़ी बीमारियों का रूप रख लेती है। जिसका फायदा भी यूरोपियन बहुराष्ट्रीय दवा उत्पादक, चिकित्सा उपकरणों मशीनों की उत्पादक कंपनियों को बड़े बाजार के रूप में लाभान्वित कर रहा है। दूसरी तरफ अनावश्यक विषैले रसायनों के प्रयोग से, पूरा फसल चक्र बिगाड़ा गया। कई वृक्षों, झाड़ियों बनो अस्तित्व नष्ट किया जा रहा है। उस पर निर्भर व विकसित होने वाले कीट पतंगों जिन्हें खाकर सैकड़ों किस्म की चिड़िया व पक्षी जिंदा रहते थे। कीट पतंगों के नष्ट होने से सैकड़ों प्रजाति की रेंगने वाले जीवो जिसमें अनेकों प्रजाति के सांप, चिड़िया और पक्षीयो जिसमें कौऐ, चमगादड़, उल्लू, गिद्ध, चील, आदि जल, थल व नभ के सैकड़ों प्रजातियों के जीवो की प्रजातियां सदा के लिए नष्ट हो गई। इसके साथ ही, कृषि में उपयोग किए जाने वाले खाद, कीटनाशक, एक तरफ फसलों के बीजों की गुणवत्ता को बिगाड़ते हैं, तो दूसरी तरफ यह रासायनिक खाद और कीटनाशक, वर्षा के जल में घुल कर सतह से भूजल मैं मिलकर उसे वषैला बनाते हैं। तो दूसरी तरफ वही जल नदी नालों से होता हुआ समुद्र में मिलता है जॉकी समुद्री जीवो को हजारों मछलियों की प्रजातियां नष्ट हो चुकी है। कृषि मृदा मैं मिलकर कृषि भूमि को बंजर बनाने पर तुले हुए हैं, इन सबको बिगाड़ने के साथ पर्यावरण में घुलकर पूरे बातों को भी साला बना देते हैं जिसका घातक परिणाम भारत के हरियाणा और पंजाब की धरती पर देखे जा सकते हैं। जिस के मूल में यही यूरोपियन व देसी बहुराष्ट्रीय पूंजीपतियों व उनकी कंपनियों का घोर लालची मोटा लाभ कमाने और दूसरे देशों की सत्ता को हथियाने व नचाने का षडयंत्र ही था। इसके साथ ही बालमार्ट, हिंदुस्तान या यूनीलीवर, इंडियन टोबैको कंपनी, देशी घोर धूर्त महाजालसाज रिलायंस, टाटा, बिरला, व अन्य बड़े पूंजीपतियों ने मिलकर इस देश में 2006 में करीबन 5लाख करोड़ रुपए खर्च कर खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम06 लगवाया और अब उसकी आड़ में, अपनी सारी खाद्य सामग्री अपने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से पैकिंग में बेचकर सबसे ज्यादा देश का प्रदूषण के बिगाड़ रही है। जबकि दूसरी ओर छोटे दुकानदारों, उद्योगों, व्यवसायियों को जोकि इन हरामखोर, जाल साज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिद्वंदी है। उनके लूट के व्यवसाय को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। इसलिए इन गिद्धों ने, यहां की सरकारों को, उन शहरों के नगर निगम के महापौर निगमायुक्त को मोटा धन देकर उन्हें खत्म करने पॉलीथिन की थैलियों का उपयोग करने पर प्रदूषण फैलाने और पर्यावरण बिगाड़ने का हवाला देकर देश में सन 2016, 17, 18 में, फुटपाथ पर ठेला लगाने वाले व्यवसायियों के 50 लाख ठेलों को तोड दिया, और देश की 2 करोड़ से ज्यादा लघु उद्योगों, छोटे दुकानदारों पर हजारों करोड़ का दंड लगाकर निगमों के पार्षदों द्वारा लूटा गया, जबकि वह सारा धन सरकारी खजाने में जमा न होकर वहां के अधिकारियों कर्मचारियों और पार्षदों ने हजम कर लिया। जबकि इन अर्ध शासी निकायों, प्रदेश के देश के स्वास्थ्य, पर्यावरण मंत्रालयों व प्रशासन ने इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को पॉलीथिन का उपयोग करने से कभी नहीं रोका। जबकि इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों बड़े पूंजीपतियों के शॉपिंग मॉल में वही माल व खाद्य सामग्री पैकिंग में अपनी मनमानी कीमतों पर जनता को बेचकर लूट का तांडव मचाया जा रहा है।। इस कानून की आड़ में। यूरोपियन, अफ्रीकन ऑस्ट्रेलियन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लूट के इस तांडव के कारण वहां इन शॉपिंग मॉल के अलावा छोटी प्रतियोगी दुकानदारों का अस्तित्व ही नष्ट कर दिया गया। विश्व स्तर पर यह पूंजीवाद का, विश्व के लोकतांत्रिक राष्ट्रों की सरकारों को खरीद कर, राष्ट्र की जनता, वहां के प्राकृतिक व मनुष्य निर्मित स्त्रोतों के शोषण का अपने मोटे लाभ के लिए कानून बनवा कर विश्व और विश्व की पर्यावरण को बर्बाद करने का सबसे घिनौना पहलू है। यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अपने दुष्कर्म और लूट से ध्यान हटाने के लिए, आम जन के माध्यम से प्रदूषण पर हल्ला मचवाती रहती हैं।

साप्ताहिक समय माया

मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल बाबुओं, उपयंत्री से आयुक्तों तक घोर भ्रष्ट और जालसाज

30 वर्ष से जमे शिवाले और श्रीवास्तव, निभाते हैं, दलालो, भू माफिया, ठेकेदारों की भूमिका

पूरा गृह निर्माण मंडल यथार्थ में सरकारी दलालों, भू माफिया व कॉलोनी माफिया गिरोह है। जो कि निजी भू माफियाओं, कॉलोनी माफियाओं, ठेकेदारों और दलालों से ज्यादा खतरनाक, महानीच, धूर्त, मक्कारों का सरकारी कानूनों, अधिकारों, बल संपन्न गिद्धों की फौज है, जो अपने हित धारकों जिसमें इनके बनाए भवनों, बहुमंजिला, इमारतों, कॉलोनियों में निवासरत व ऐसे रहवासी भवनों, भूखंडों, स्थानों को पाने के इच्छुक व्यक्तियों को, हर तरह से हर कदम पर नोचने, खसोंटने और वसूली का काम करता है। यहां पर बैठा चपरासी सुरक्षा सैनिक से लेकर बाबू, उप, सहायक, उप संभाग स्तर पर, कार्यपालन यंत्री, संपदा अधिकारी संभाग स्तर पर, मंडल स्तर पर उपायुक्त, और मुख्यालय स्तर पर आयुक्त तक सीधे जनता को नोचने के साथ मोटी कमाई के लिए निजी क्षेत्र के भू माफिया कॉलोनी माफिया नेताओं मंत्रियों, भारतीय प्रताड़ना सेवा के,भारतीय अपराध संरक्षण सेवा के अधिकारियों, कारपोरेट सेक्टर की बड़ी-बड़ी कंपनियों, प्रकाशन माफिया जिसमें भास्कर, जागरण, जैसों के इशारे पर जनता को बेंचे हुए प्लॉट, कालोनिया, फ्लेट, दुकाने, ऑफिस, हड़पने, छीनने के लिए इनके अधिकारी कर्मचारी इंजीनियर हर तरह के षड्यंत्र रचने में भी मास्टर होते हैं।

इंदौर में 30 वर्ष से उपयंत्री के पद पर भर्ती हुए घोर भ्रष्ट, महा जाल साज करोड़ों की संपत्ति के मालिक वर्तमान में कार्यपालन यंत्री के पदभार को संभालते मनोज शिवाले और मनोज श्रीवास्तव आखिरी इंदौर में लूटो और लूटाओ के दम पर ही जमे हुए है जिन्होंने अपनी 35 साल के इतिहास में बड़े-बड़े भ्रष्टाचार किए 90% कालोनियों, फ्लेट्स, शॉपिंग कांप्लेक्स, बहुमंजिला इमारतों के रखरखाव, निर्माण, सुधार कार्य,रंगाई पुताई आदि का पैसा हजम कर लिया स्वाभाविक था जो लूटा गया उसमें से लूटाया भी गया। इसलिए सबके चहेते बने 35 साल से अजगर की तरह उपयंत्री से कार्यपालन यंत्री बनने तक इंदौर से लिपटे बैठे हुए हैं इनसे 90% रहवासी, भूखंड धारक, कालोनीवासी, इनके पूरा किराया, किस्ते, पट्टा राशि उस पर ब्याज, दंड राशि आदि की वसूली पूरी करने किस्तें चुका देने या खरीद लेने पर नामांतरण के नाम पर लोगों को सालों तक परेशान करना और पूरा करिया व किस्तें देने के बावजूद भी ढंग से रखरखाव न करने, बिजली-पानी, सड़कें, मकानों के पलस्तर, लिपाई, पुताई, मरम्मत आदि का एक तरफ रे बातों रहवासियों से हर बात का पैसा मांगने, दूसरी तरफ मंडल से आवंटित धन का कागजी खानापूर्ति कर पूरा पैसा हजम कर जाने के बाद में भी इन हरामखोर सूकरों की औलाद उपयंत्री से लेकर सहायक कार्यपालन यंत्रियों और कर्मचारी तक सरकारी पिछले 50 सालों से इसी प्रकार लूटपाट से चल रहा है इसमें धन नीचे से होता हुआ उपायुक्त आयुक्त प्रधान सचिव मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचने के कारण सारे अधिकारी कर्मचारी जिसमें मनोज शिवाले और श्रीवास्तव जैसे उपयंत्री से भर्ती होकर कार्यपालन यंत्री तक 30-35 सालों में इंदौर में ही, लूटपाट के धन से न केबल लुटाया वरन् वरिष्ठों से लेकर, अध्यक्ष मंत्रियों तक की, सुरा सुंदरी तक की सेवा कर, यहीं जमे। इस बीच अरबों रुपए के इन हरामखोर जाल साजों ने घोटाले किए करोडों की संपत्ति बनाई। फरि इनके कार्यालय के सामने ही, देश के सबसे बड़ी मीडिया माफिया, भूमाफिया भास्कर समूह जिनकी जांच पछिले 30 साल की, की जाए और सब में सजाएं हो जाए दो या तीन चार जिंदगियां सजाओ के लिए कम पड़ेंगी।

स्वाभाविक सी बात है इतने सालों में जनता से गृह निर्माण मंडल का अरबो करोड़ का जो हेर फेर किया उसमें अब तक 50 करोड से ज्यादा की कमाई इन दोनों ने भी की। जिसमें इनके अनेकों मकान व अन्य संपत्तियां इंदौर और इंदौर के बाहर भी है। जिसमें इनके अनेकों मकान व अन्य संपत्तियां इंदौर और इंदौर के बाहर भी है। इस बीच अनेकों उपायुक्त, आयुक्त, अध्यक्ष, सचवि, प्रधान सचिव मंत्री मुख्यमंत्री आये और गए। सब ने इनकी सेवाओं का लाभ लेकर इन्हें अजगर की भांति मोटा माल हजम करने और करवाने के लिए बैठाए रखा। यह कहानी का बहुत छोटा सा हिस्सा है। यथार्थ इससे आगे और भी बड़ा है इन्होंने हजारों हितग्राहियों के मकानों, प्लाटों की जालसाजी षड़यंत्रों से हड़पने, बिकवाने, हस्तांतरित करने के बदले लाखों रुपए हजम कर जाने का खेल भी पिछले 35 सालों से खेलते आ रहे हैं। इसके आगे अब ये सब इंदौर में बैठे घोर भ्रष्ट जाल साज, उप, सहायक, कार्यपालन यंत्री, शिवाले श्रीवास्तव से लेकर उपायुक्त दोहरे जिस पर अनेकों जांचे लंबित हैं, आयुक्त,अध्यक्ष मंत्री सचिव प्रधान सचिव सब एक बड़े गिरोह के रूप में, अब बड़े भू माफियाओं कॉलोनी माफियाओं की रखैल बन कर, उनके इशारे पर अपनी ही बनाई बेंची कालोनियों, शॉपिंग, हाउसिंग कांपलेक्स के निवासियों को डरा धमका कर खाली करवाना चाहते हैं।जिसमें एबी रोड से लगी हुई एमआईजी एलआइजी, स्वयं का बनाया हुआ शॉपिंग कंपलेक्स जिसमें भूतल पर बनी दुकानें उसके ऊपर गृह निर्माण मंडल का उपायुक्त कार्यालय से लेकर दोनों का. यंत्री निर्माण एवं रखरखाव के साथ का. यंत्री विद्युत एवं यांत्रिकी कार्यालय हैं। जिसमें हर साल रखरखाव और सुधार लिपाई पुताई आदि के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं स्वयं के द्वारा नीचे के किरायेदारों, दुकान मालिकों, पट्टा धारकों से से खाली करवाने के लिए तोड़ा गया जिसके वीडियो समय माया समाचार पत्र के पास में है और सामने ही भास्कर के यहां से महिना लेने वाले पत्रकारों को बुलाकर उसके फोटो भास्कर में छापे गए।

बाद में सूत्रों से मालूम पड़ा कि भास्कर अब मीडिया माफिया ही नहीं जो शासन प्रशासन को पिछले 40 सालों से ब्लैकमेल कर अरबों रुपए की कमाई करता है हर महीने, पिछले 15 सालों से एक देश का जाना माना भू माफियाओं और कॉलोनी माफिया गिरोह भी बन चुका है। वहां पर अपना डीबी मॉल ग्वालियर भोपाल की तरह बनाना चाहता है। इसलिए ये घोर भ्रष्ट सरकारी गृह निर्माण मंडल का गध्दिो का गिरोह, वहां के निवासियों से मकान दुकान खाली करवाने डराने, धमकाने से लेकर अपनी ही शॉपिंग कंपलेक्स के भवन को कमजोर करने के लिए उसने अंदर से, स्नानागार, संडास, मूत्रालय, आदि के पाइप तोड़ कर छतों में कमजोर करने लगातार पानी भरा जा रहा है। जबकि 1980-81 में एलआइजी तरिहे के उस पार बनी पूर्व की सुहाग होटल जो अब सीएचएल हॉस्पिटल की6 मंजिल की वही बिल्डिंग जो हाउसिंग बोर्ड के दिल्ली के उसी ठेकेदार ने बनाई थी जिसने यह तीन मंजिल का पूरा शॉपिंग कंपलेक्स बनाया है बेशक यह पूरा कंपलेक्स काफी मजबूत तो है परंतु जब गिद्धों की निगाह जिंदो को नोच खाने की हो तो वह हराम खोरो की फौज जैसा कि इंदौर में हर बड़ा अधिकारी कमाने खाने के लिए करता रहता है वैसे ही यह दोहरे भी कर रहा है। सूचना के अधिकार में हरामखोरों से जानकारी मांगने पर कैसी-कैसी दलीलें दी जाती है और अपीलें लगाने पर जालसाजों का गिरोह कैसे उन्हें रद्द करता है। दस्तावेजी सबूत समय माया के पास उपलब्ध है।

नई कांग्रेस सरकार से इमानदारी और जनहित में कार्रवाई की ब्लड निर्माण मंडल के गिद्धों के विरुद्ध कार्रवाई की उम्मीद करना बेमानी ही होगा क्योंकि 15 साल से नंगे भूखे अपना पेट भरने आए हैं न की इमानदारी से न्याय कर जनहित करने चाहे फिर वह मुख्यमंत्री कमलनाथ हो या उनका कोई मंत्री।ऐसा ना हो जैसा कि कबीर ने कहा था निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय मरी खाल के चाम ते, लोह भस्म हो जाए, यह भास्कर जो अपने ही पत्रकारों को आंख मींचकर धक्का देकर हत्या करके आत्महत्या सिद्ध करता हो। इन गरीबों की हाय लेकर अपने अस्ताचल की तरफ जाने की तैयारी कर रहा हो। जहां तक गृह निर्माण मंडल के गिद्धों के गिरोह का सवाल है। हर महीने 1-2 लपेटे में आने लगे हैं इनका भी नंबर शीघ्र ही आएगा लाइन में खड़े हैं। बेशक प्रदेश का पूरा गृह निर्माण मंडल महा जालसाज डकैतों गिरोह है।प्रकृति का नियम हैमुट्ठी बांधे आया था हाथ पसारे खाली जाएगा।।

यातायात सुधारने के नाम करोड़ों रुपए हजम करते हैं निगम और पुलिस

यातायात पुलिस अधिकारी बहुत साधारण तरीके से चाहे तो सुधार सकते हैं यातायात की समस्या। पर समस्या सुलझा देंगे तो कमाई कैसे होगी निगम और यातायात पुलिस की जो लाखों रुपए देकर नगर यातायात में आते है। दूसरी तरफ मोटी कमाई के लिए निगम और प्रशासन में बैठे जिलाधीश, निगमायुक्त और संभागीय आयुक्त इंदौर को प्रयोगशाला के रूप में उपयोग करते हुए इंदौर के पुरानी नगरीय बसावट में 36 फुट बाय 9 फुट की बसें व 30 फुट बाय 8 फुट की बसें चलवा कर जानबूझकर इस महानगर के नागरिकों में,दो,तीन, चार पहयिा वाहन चालकों में दहशत पैदा की जाती है। यातायात पुलिस यातायात सुधारने की अपेक्षा यहां कोनों में घुसकर वाहन चालकों को घेरकर चालान काटने की आड़ में मोटी वसूली करती रहती है। पूर्व की बसें भी जेएनयूआरएम धन से अपने खास ठेकेदारों के नाम से खरीदी और उसका पैसा हजम कर लयिा गया। अभी भी सूत्र सेवा की बसें जिसका 50% धन केंद्र सरकार से आया था महापौर मालिनी गौड़ ने अपने खास रिश्तेदारों के नाम से बसें खरीद कर 50% धन हजम कर लिया और उस शासन का मोनो चिपका दिया। बीआरटीएस के नाम पर जे एन आर यू एम का सन 2006 से सन 2013 -14 तक रू11 सौ 50करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ। जिसमें विवेक अग्रवाल से लेकर वर्तमान के घोर धूर्त आयुक्त आकाश त्रिपाठी ने भी मोटा पैसा हजम किया। रेलिंग लगाने, स्टैंड बनाने, सजावट करने के नाम पर भी ज्यादा कीमत में काम करवा कर पैसा हजम किया गया जानबूझकर शहर का यातायात बिगड़ गया उस 30-50 फुट चौड़ी सड़क पर केबल आईबस ही चलेगी।

ऐसे इन हरामखोरओं के बाप की जागीर हो जो जनता को जनता के धन से ही अपनी लूटपाट के लिए मनमर्जी से अपनी लूट के लिए बसें चलाएंगे दूसरी तरफ जनता को परेशानी दहशत मे चलने के लिए मजबूर करेंगे। वैसे भी इन घोर मक्कार भारतीय प्रताडणाा सेवा अधिकारियों के लिए इंदौर मोटी लूट के लिए तरह तरह के प्रयोग करने का अड्डा बन चुका है। जन धन से हर वर्ष सड़कों के बनाने के नाम से 200 से 300 करोड़ खर्च किया जाता है। इस खर्च 70 से 80% पैसा पार्षद उसके ठेकेदार, कर्मचारी अधिकारियों से लेकर निगम के इंजीनियर, उपायुक्त आयुक्त आयुक्त और महापौर हजम कर जाता है। गली मोहल्ला की सड़कों से लेकर बड़ी बड़ी सड़कों को कई बार सीमेंट का बनाने के बाद भी जानबूझकर डामर की सड़कें बनाने के बहाने हर साल जनता से लूटे गये धन का रु 150 हजम कर लिया जाता है।

पुलिस भी वेरीकेड खरीदने, सीमेंट डविाइडर बनाने, खड़े करने, कैमरा लगाने, सड़कों पर इंडिकेटर लगाने, चौराहों पर यातायात संकेतक लगाने, सुधारने आदि में हर वर्ष करोड़ों रु बरबाद कर देती है। जबकि बड़ी आसानी से चाहे तो केबल यातायात संकेतकों के चौराहों पर केबल घड़ियों और समय की लंबाई के हिसाब से किलोमीटर प्रति घंटे की गति की सेटिंग से यातायात को सुचारू रूप से चला सकती हैं परंतु जानबूझकर हराम खोरो की फौज मोटा पैसा हजम करने जनता को परेशान करने चालान काटने की नियत से ही जानबूझकर यातायात सुधारना नहीं चाहते। यदि यातायात सुधर गया यर्द चालान कैसे काटे जाएंगे कमाई कैसे होगी? ये चांडालों की फौज तो इंतजार करती है। कि जितनी ज्यादा दुर्घटनाएं होंगी, जितनी ज्यादा जाम लगेंगे, जनता परेशान होगी उतनी ज्यादा लूटपाट के लिए यातायात सुधारने के लिए धन की व्यवस्था के लिए कहा जा सकेगा। उस की आड़ में लूटा जा सकेगा।

इंदौर पुरानी औद्योगिक नगरी वर्तमान में प्रदेश की व्यावसायिक नगरी में बदल चुका है। स्वाभाविक है कि प्रदेश में 17 लाख से ज्यादा वाहन इंदौर में ही है। यहां जानबूझकर यातायात पुलिस और नगर निगम हर दिन नए प्रयोग, शहर की सड़कों पर यातायात सुधारने व करने के नाम पर करोड़ों रुपए का सामान मोटे कमीशन अपने अपने खास लोगों और उनकी फर्मो से खरीदा जाकर अपने खास चंगू मंगू चेले ठेकेदारों से करवाया जाता है। खास फर्मों को यातायात संकेतको के रखरखाव के लाखों रुपए के ठेके प्रतिमाह मोटे कमीशन पर सौंप दिए जाते हैं। और उसके बाद उनके फर्जी खरीदी मजदूरी भुगतान के बलिों के भुगतान भी आसानी से किए जाते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने बरसों पहले हर यातायात संकेतकों टाइमर लगाने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने को कहा था इसके विपरीत उसके नाम का पैसा हजम करने के बाद में भी इस महानगर के अनेकों चौराहों के संकेतको पर अधिकांश स्थानों के सेकेंड्स के टाइमर बंद पड़े हुए हैं। परंतु उनके हर वर्षष में अनेको बार टाइमर कागजों में बदले भी जाते हैं आप उनकी भुगतान भी हो जाते हैं।

वही हाल सड़कों पर पैदल चलने वालों कीजिगजाग क्रॉसिंग बनाने, वेरीकैड लगाने, सड़कों पर लाइनिंग बनाने स्टॉपर की रंगाई पुताई आदि के नाम पर भी 10-20 पर सेंट काम के 5 से 10 गुना का भुगतान किया जाता है। काम हो या ना हो। सड़कों पर कभी सीधे प्लास्टिक के डंडे मोटी कीलो से ठोक दयि जाते हैं । कभी तिकोने खड़े कर दिए जाते हैं। कभी सीमेंट के मोटे डिवाइडर लगा दिए जाते हैं एक तरफ उनकी खरीद बिक्री, लगाने उखाड़ने, मैं साल भर में लगभग रुपए 5 से 10 करोड़ का खेल कर दिया जाता है। दूसरी तरफ इंस उत्पन्न होने वाली चालकों की परेशानियां देखने समझने वालों की वीडियो रिकॉर्डिंग विश्लेषण कर यातायात में सुधार करने की पहल करने की विपरीत पुलिस नगर निगम को तथ्य और आंकड़े उपलब्ध करवाने की अपेक्षा भाई इसकी आड़ में मोटी वसूली करती रहती है। सड़कों पर व्यावसायिक क्षेत्रों में दो पहिया वाहन, कारें, बसे, ट्रक आदि तक चाहे जहां पर पार्क कर दिए जाते हैं जिससे अन्य वाहन चालकों पैदल चलने वालों को भी न केवल परेशानी वरंन दुर्घटना का भी शिकार होना पड़ता है। यह हालत ना केवल इंदौर वरन पूरे प्रदेश और देश की भी है।

एक मध्यमवर्गीय जन का दर्द .. जय हिंद

अब जब लोन माफी की बात चल ही रही है तो सिर्फ किसान ही क्यों..

गृह निर्माण ऋण, शिक्षा ऋण, वाहन ऋण, पर्सनल चीजों वाला ऋण, किराने वाले का ऋण, पान वाले का ऋण, दारु के ठीए वाले का ऋण, यार दोस्तों ओर महाजन का ऋण.., जूआ-सट्टा वाला ऋण.., वालों को भी मांग करनी चाहिए हो सके तो दिल्ली के लिए कूच भी करना चाहिए सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने-अपने चुनावी घोषणापत्र में इन सबका समावेश करना चाहिए..

100% जीत तय.. जब देश और अर्थव्यवस्था का जनाजा निकलना ही है तो जरा झूम के निकले एक विन्रम अपील कृपया इसे दूर तक पहुंचाएं... समय पर कर (टैक्स) अदा करने वाली भारत की जनता का कांग्रेस / बीजेपी और सभी political parties से निवेदन है कि - वो कर्ज माफी की घोषणा, हमारे द्वारा चुकाये हुए कर से ना करके... अपने पार्टी फंड से करें। क्योंकि वादा कांग्रेस/बीजेपी ने किया है, कर (tax) चुकाने वाली जनता ने नहीं। देश की जनता कर (tax) देश के विकास के लिए देती है ना कि मुफ्त में बांटने के लिये। सहमत हो तो इसे आगे फॉरवर्ड कीजिये। झंझट ही खत्म समझो।

देश में पूरा मीडिया, दृश्य-श्रव्य व मुद्रित को डरा धमका कर सरकार के विरुद्ध समाचार छापने से रोका जा रहा

देश की मीडिया को बिकाऊ कहा जाता है इसके विपरीत सच यह भी है सरकारी तौर पर डराया धमकाया जाने के साथ उनका मुंह बंद रखने के लिए हर दिन 1000से 2000 करोड़ का जन धन भी लुटाया गया है। समाचार चैनलों को विवश कर के समाचार दिखाने से रोका जा रहा, जहां तक अखबारों, पत्र-पत्रिकाओ को हर दिन 4-6 पेज के विज्ञापन देकर सरकार अपने कुकर्मों को ढांकने का असफल प्रयास कर रही है।दूसरी ओर बदले में केंद्र व भाजपा की सरकारें हर दिन रु 1000 से2000 करोड जन धन से लुटे गए करों से मीडिया पर लुटा कर समाचार पत्रों--पत्रिकाओं को अपनी सब सच को छापने से रोका जा रहा है। समाचार पत्र भी यथार्थ को छापने की अपेक्षा भ्रमित करने वाले और दूसरे समाचार समाचारों से अपने समाचार पत्र को पूरा भर कर काम चला रहे हैं। यह वही धन है जो पेट्रोल, डीजल और गैस को दुगना तीन गुना कीमत पर बेचा कर जनता को लूटा जा रहा है।

भारत में पूरे देश में वर्तमान में सारे दूरदर्शनी समाचार श्रृंखलायें समाचार नहीं दिखाती हैं। इसके पीछे मूल कारण आपराधिक प्रकृति के मोदी और अमित शाह जैसे सत्ताधीशों के विरुद्ध चलने वाले भ्रष्टाचार, कुकर्मों, पूंजीपतियों को लूट की पूरी छूट देकर, जनता से लूटपाट और बर्बादी के समाचारों को को विविध दूरदर्शनी समाचार श्रृंखलाओं में चलने से रोकना है। इसलिए अब समाचारों की अपेक्षा श्रृंखलाओं पर पुरानी फिल्मों के नायक नायिकाओ के प्रणय दृश्यों की भरमार दिखाने के साथ उन पर अश्लील कार्यक्रमों जिन्हें प्रतिभा खोज का नाम दिया गया है, मैं कम उम्र लड़के लड़कियों जो 4- 5 साल की उम्र से लेकर 16-18 तक के होते हैं। उन अवयस्कों के ऐसे अश्लील फूहड़ कार्यक्रमों को प्रदर्शित किया जाता है और उनकी कच्ची उम्र में उन्हें वयस्क बनाने की कोशिश की जाती है। क्या यह बच्चों के बचपन को छीनने और बच्चों के प्राकृतिक विकास में बाधक नहीं होगा? क्या यह गैरकानूनी नहीं? आश्चर्य की बात तो यह है। कि इन कार्यक्रमों में अपनी कमाई के लिए वरिष्ठ कलाकार अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर निर्णायक की भूमिका निभाते हैं। इसमें उन्हे काम, दाम, नाम, तीनों की प्राप्ति हो जाती है इसलिए ऐसी अश्लील फ़ूहड़ कार्यक्रमों में उन्हें कार्य करना बिल्कुल भी मानसिक तकलीफ नहीं देता। अधिकांश समाचारी श्रृंखलायें, अब आपराधिक प्रकृति के सत्ता देशों के सामने नतमस्तक होकर देश के दर्शकों का जो शासन और देश के समाचार देखने के लिए उत्सुक रहते हैं व्यर्थ समय बर्बाद करती है बच्चों और महिलाओं को ऐसे कार्यक्रम देखने में भला ही आनंद आता हो दूसरी तरफ यह मानसिक विकृतियों और जीवन का मूल समय नष्ट कर देती है। बेशक ऐसी समाचारी श्रृंखलायें बच्चों और महिलाओं के दर्शक होने के कारण उनकी टीआरपी अवश्य बढ़ा देती है जिससे उन्हें विज्ञापनों की आय प्राप्त हो जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ युवाओं और पुरुष वर्ग का इन दूरदर्शनी समाचार श्रृंखलाओं से मोह भंग हो गया और अधिकांश पुरुष वर्ग टीवी से दूर होकर अपने दैनंदिनी कार्यों में ध्यान देने लगा। दूसरी तरफ वास्तविकता में देश में जो घट रहा है उसके यथार्थ को प्रकट न करने से भी जनता ने टीवी पर समय व्यर्थ् बर्बाद करना बंद कर दिया।

देश के 90% समाचार पत्र, चैनल, समाचारों की अपेक्षा दिखा रहे फिल्मी व नाटकीय कार्यक्रम व अन्य समाचार

जो सरकार के विरूद्ध चलने वाली टीवी चैनल्स जिसमें एनडीटीवी को बंद करने के साथ उसके साथ कई प्रपंच उसकी स्तर पर रचे गए। कई समाचार संपादकों को डरा धमकाकर जो कि सरकार के विरुद्ध सच बोलने की हिम्मत करते थे। उन्हें हटवाने में सरकार की भूमिका स्पष्ट रूप से सामने आई। ज़ी टीवी व सरकारी दूरदर्शन तो भाजपा की अपनी रखैल है। जो केवल उसकी झूठी प्रशंसा में हीं लगे रहते हैं इसलिए उनको और अनाप शनाप करोड़ों रुपए के विज्ञापन हर दनि के लिए जा रहे हैं। भारत के बड़े दैनिक समाचार पत्रों में अपने को कुकर्मों को छुपाने, उनको प्रकाशित ना होने देने के लिए हर दिन विभिन्न मंत्रालयों के नाम से जिसमें वित्त, जिसके अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, आयकर, माल एवं सेवा कर आदि, भूतल परिवहन मंत्रालय, रेलवे, कृषि, स्वास्थ्य, उद्यानिकी एवं वानिकी, उद्योग, विज्ञान एवं तकनीकी, पेट्रोलियम मंत्रालय, जल संसाधन, पर्यावरण एवं वन जैसे मंत्रालय के माध्यम से 4 से 6 पेज के के विज्ञापन अपनी अपनी के साथ संबंधित विभाग के मंत्री के बड़े बड़े फोटो के साथ प्रशंसा और उपलब्धियों का बखान करते हुए पिछले 4 सालों से लगातार प्रकाशित हो रहे हैं जिस पर वर्ष में रुपए 3 से 5 लाख करोड खर्च किया जा रहा है।

वन विभाग इंदौर वृत में मात्र सक्सेना पर ही लोकायुक्त का छापा क्यों

इंदौर वन मंडल के उप वन मंडल अधिकारी सक्सैना पर लोकायुक्त छापा डाला, डायरिया पकड़ी गई, उसमें पीडी के नाम पर हर महीने लाखों के भुगतान की प्रविष्टियां पाई गई स्पष्टत: वह पुरुषोत्तम धीमान का नाम था। परंतु लोकायुक्त ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की और ना ही विभाग से कुछ जानकारी मांगी। विभागीय सूत्रों के अनुसार यह दोनों की जुगल जोड़ी हर साल करोड़ों रुपए की भ्रष्टाचार की जिम्मेदार है।

सरकार के वन मंत्रालय से लेकर, सुदुर वनों मैं हर कदम विभाग में चारों तरफ घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है। यह सच सर्वव्यापी होने के साथ ही वन संपत्तियों, वृक्षों, वन भूमि , प्राणियों, वनोपज व अन्यय सभी प्रकार की वन संपदा के लिए बर्बादी के लिए भी स्वयं विभाग के कर्मचारी और अधिकारी ही जिम्मेदार हैं। यह सच विभाग के ईमानदार कर्मचारियों और अधिकारियों का है। जिन्हें घोर भ्रष्ट, जालसाज, कर्मचारी और अधिकारी मिलकर प्रताड़ित करते हैं। उलझाते हैं।उन्हें झूठे कब्जे कागजों पर हस्ताक्षर करवाने उल्टे सीधे काम करवाने के लिए विवश करते हैं। ना करने पर दूर दराज के इलाकों में उनके पद स्थापना करवाते हैं। यह सच वन विभाग के हर मंडल उपमंडल से लेकर बीटों तक का है। जहां वन विभाग की जमीनों को एक तरफ गर्मियों में पहले तेंदूपत्ता संग्रहण के नाम साफ करवाए जाता है दैनिक वेतन भोगी व अन्य ग्रामीण मजदूरों से, साफ की गई जमीन पर वहीं ग्रामीण मजदूर उस पर मजदूरी से प्राप्त धन से दस 20 किलो मक्का के बीज बिखेर देते हैं जो बरसात आने पर उग आते हैं। फिर जिस ग्रामीण मजदूर ने मक्का बिखेरी थी। व्हाय उस की निराई गुड़ाई कर देता है। और जब वन कर्मी उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो है शासन प्रशासन ने उसकी शिकायत कर देता है कि मेरी फसल को वन कर्मी उजाड़ रहे हैं जिस पर धीरे-धीरे इस प्रकार से वह ग्रामीण खेती करने लगता है। बाद में शासन से उसे खेती करने का पट्टा मिल जाता है इस प्रकार यह वन भूमि कब्जा करने का सदियों पुराना षड्यंत्र स्वयं बीट गार्ड वन कर्मी उपवन पाल वन पाल की देखरेख में आसानी से जमीनी ग्रामीणों को हस्तांतरित हो जाती है। और बाद में पट्टे की जमीन पर स्वात्वाधिकार प्राप्त कर कुछ सालों में पट्टा मुक्त हो जाने के बाद, उसे राजस्व ग्राम में शामिल कर दिया जाता है जिसकी बाद में खरीद फरोख्त होने लगती है इस प्रकार से वन भूमि को सालों से हड़पा जा रहा है। ऐसी सैकड़ों एकड़ जमीन के बारे में जो कि कन्नौद, खातेगांव, बागली सोनकच्छ, मानपुर आदि के जंगलों में सक्सेना ने दूसरे नाम से खरीदी है। ऐसी सैकड़ों एकड़ वन भूमि को दूसरे लोगों ने खरीदा है बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां, कालोनियां, जो रालामंडल के सामने रिंग रोड तक, चारों तरफ बनी हुई कालोनियों और फैक्ट्रियों के रूप में देखी जा सकती है वही हाल सुपर कॉरिडोर के पास में भी हुआ जहां से करोड़ों रुपए की बंदरबांट की गई यही हाल इंदौर वन मंडल की चोरल मानपुर महू रेंज में भी बरसों से चल रहा था। इसकी करोड़ों रुपए की कमाई मैं सक्सैना से लेकर ऊपर वन मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंची जिसमें यहां के तात्कालीन वन मंडलाधिकारीयों, मुख्य वन संरक्षकों और इंदौर के जिलाधीशों, उपजिलाधीशों, तहसीलदारों, पटवारियों ने भी ने भी मोटी कमाई कर अपनी भूमिका निभाई। यही कारण था कि सूचना के अधिकार में पिछले 4 सालों से लगातार जानकारी मांगे जाने के बाद में भी कभी भी जानकारी नहीं दी गई और अपील लगाने पर उसे महीनों तक नहीं सुना जाता। निशुल्क जानकारी देने के आदेश हो जाने के बाद में भी वहां बैठे घोर जालसाज, इस भ्रष्टाचार में हिस्सा खाने वाले कर्मचारी, अधिकारी देने में भारी नाटक नौटंकी कर आवेदक को चक्कर कटवाते रहते हैं। पर जमीनों से संबंधित, वृक्षारोपण, हेतु वृक्षों की पौध विकसित करने वाली रोपणीयों, नर्सरीयों में खरीदी, मजदूरों के भुगतान, आदि की जानकारी को भी बरसों बाद अभी तक नहीं दिया गया जिसमें सब का भ्रष्टाचार का मोटा शेरू हिस्सा था। दूसरी ओर जंगलों मैं वृक्ष कटाई की प्रक्रिया केवल सागौन के वृक्षों के लिए ही अपनाई जाती है। बाकी सभी प्रजाति के वृक्षों के लिए कोई निर्धारित मापदंड नहीं इसलिए जानबूझकर बीट गार्ड, उपवनपाल, वनपाल, अपने ही ग्रामीणों, वृक्ष माफियाओं, आदमियों से उन सभी प्रजाति की कटाई को अंजाम देते रहते हैं और वह लकड़ी लगातार बाजार में विक्की रहती है चोरी छुपे जिसका मोटा धन इन सब को भी प्राप्त होता रहता है।जबकि शिवराज ने आते ही 56 प्रजाति के वृक्षों की कटाई की खुली छूट दे रखी थी जब इसके संबंध में, समय माया के श्री अजमेरा को मालूम पड़ा तो उन्होंने इसकी जांच पड़ताल की और आदेश की, प्रति प्राप्त कर इसकी शिकायत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कार्यालय में कर दी परंतु सन 2006 से 2014 तक लगातार हर वर्ष पूरे प्रदेश भर में 8 से 10 को वृक्ष काटे जाते रहे। शिकायत के बाद जब हल्ला मचा उस पत्र को ही फर्जी करार दिया गया। शासकीय स्तर

जांच क्यों नहीं, घोर भ्रष्ट, भ्रष्टों के सरगना मुख्य वन संरक्षक धीमान की

पर कटाई रोक दी गई। परंतु वास्तविकता में पूरे प्रदेश में जंगल लगातार काटे जाते रहे। जिसका सबसे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण यह है, कि पिछले 40-50 सालों से लगातार प्रदेश के सबसे बड़े धार रोड पर स्थित जीएनटी मार्केट मैं लगातार हर दिन 30 से 40ट्रक, ट्रैक्टर ट्रॉली में ताजी कटी लकड़ी हर दिन कहां से बिकने आती है। जसि वन विभाग के लोग चुपचाप महीना खाकर देख रहे हैं। हाल यहां तक है कि सभी आरा मशीनों पर भरपूर लकड़ी हर गोदाम में भरी रहती है।सूत्रों के अनुसार रु6लाख महीने उप वन मंडल अधिकारी को भी मिलता था।

वन विभाग को वृक्षारोपण के लिए मिलने वाला अन्य विभागों से, जो कि नगर निगम इंदौर, इंदौर विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन, पर्यटन, विमानपत्तन, ग्रामीण विकास, ग्राम पंचायतों, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, सड़क विकास निगम, शिक्षा, आदि के धन मे भी भारी हेराफेरी की गई। पिछले 15 सालों में मिले करोड़ों रुपए की वृक्षारोपण का 90% विकास केवल कागजों पर ही हुआ। इसमें सक्सेना और उसके सहयोगी रहे वन मंडला अधिकारियों, से लेकर मुख्यालय वनपाल उपवनपाल, तक ने भी अपना धन हड़पने और भ्रष्टाचार करने में अपनी भूमिका अदा की। इसकी भी गहन जांच की जानी चाहिए। सक्सेना का जलवा और मुख्य वन संरक्षक धीमान जोकि धार, अलीराजपुर, झाबुआ आदि वनमंडलों तक वहां के वन मंडल अधिकारी से लेकर बीट गार्ड तक सभी अधिकारियों कर्मचारियों की पदस्थापना, स्थानांतरण, जांच,आदि में भी सक्सेना की वसूली और हिस्सेदारी रहती थी क्योंकि सक्सेना का भाई गौरी शंकर मंत्री का निजी सचिव था। इसलिए इंदौर उज्जैन संभाग के 15 जिलों के कर्मचारियों अधिकारियों की विभागीय जांच स्थानांतरण पदस्थापना आदि की कार्य वाहियों मैं भी मोटा लेनदेन कर सुलटाने का काम भी करता था। इसलिए इंदौर वन मंडल में अधिकांश वन मंडल अधिकारी 6-8 महीने साल भर में ही विदा कर दिये जाते थे।

वन विभाग को वृक्षारोपण के लिए मिलने वाला अन्य विभागों से, जो कि नगर निगम इंदौर, इंदौर विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन, पर्यटन, विमानपत्तन, ग्रामीण विकास, ग्राम पंचायतों, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, सड़क विकास निगम, शिक्षा, आदि के धन मे भी भारी हेराफेरी की गई। पिछले 15 सालों में मिले करोड़ों रुपए की रक्षा रोपण का 90% विकास केवल कागजों पर ही हुआ। इसमें सक्सेना और उसके सहयोगी रहे वन मंडला अधिकारियों, से लेकर मुख्यालय वनपाल उपवनपाल, तक ने भी अपना धन हड़पने और भ्रष्टाचार करने में अपनी भूमिका अदा की। इसकी भी गहन जांच की जानी चाहिए। जिसमें धीमान का हस्सिा भी था। कहानी अधूरी है समय व पत्र में स्थान के अभाव में अगले अंकों में प्रकाशित होगी।

वृक्षारोपण के नाम पर भी

2006 में शिवराज अपनी पत्नी साधना सिंह के प्रमोद महाजन से पारिवारिक रिश्तों और मोटी भेंट पूजा के चढ़ावे के कारण सांसद से मप्र के बाबु लाल गौर को हटा कर मुख्यमंत्री घोषित किये गये। उस समय वह विधायक भी नहीं था।तब से मुख्यमंत्री रहते हुए शिव ने जन से जून तक 52 प्रकार के वृक्षों की खुली कटाई की छूट देकर प्रदेश के प्रति वर्ष लगभग 4 से 6 करोड़ पेड़ 50 जिलों के जंगलों से कटवा कर बिकवा दिए। अर्थात मान लें 50 करोड़ कटवा कर मात्र 5000/- प्रति वृक्ष कमीशन मिला। कुल 50×5000=250000 करोड बेशक वन विभाग की खुली छूट शासन के आदेश पर दी गईं। साफ की हुई जमीनों पर राजनीतिक नेताओं, भूमाफियाओं के कब्जों पर पर्यटन व धार्मिक स्थलों पर बड़े होटल, कालोनी, खेती, खदानें चल रही हैं। लगभग 4लाख हेक्टेयर जमीन जो वन विभाग की थी, 2006 तक, अब राजस्व ग्रामों, तहसीलों में स्वयं शिवराज के षड्यंत्रों से बदल दी गईं है।

इन षड्यंत्रों पर ज्यादा हो हल्ला न मचे इसलिए वन विभाग के भू सर्वेक्षण अधिकारी के हर संभागीय व रेंज कार्यलयों से पद ही समाप्त कर दिए गए हैं । जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो हर रेंज की हर इंच जमीन व संपत्तियों का हिसाब रखे और किसी भी कब्जे की स्थिति में वरिष्ठों को सूचित कर कानूनी कार्यवाही कर वनभूमि का दुरूपयोग रोके। अपराधीयो पर कानूनी कार्यवाही के लिए कार्य करे। 1990 से सर्वेयरों की भर्ती ही नहीं की गई। जो थे उन्हें दूसरे कार्यों मे लगा दिया गया। वैसे भी वह पद सबकी आंखों की किरकिरी था। इंडियन फारेस्ट ईंटिंग आफिसर्स / भारतीय वनभक्षण अधिकारीयों, भूमाफियाओं, नेताओं यह खेल भी लाखों करोड़ का है। हर आई एफ एस, एस डी ओ, रेंजर, नेताओं की कमाई का बड़ा स्त्रोत है। पदस्थ करवाया। औंकारेश्वर, बांधवगढ, कान्हा, इंदौर के रालामंडल व हर जिले में वनभूमि पर हजारों हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जे की स्थितियाँ और अवैध कारोबार देखे जा सकते हैं। अब 6 करोड़ वृक्षारोपण की स्थिति को मेरे सारे बुद्धिजीवी पाठकों का यथार्थ और षड्यंत्रों को स्वयं समझ आ जायेगी। फिर 6 करोड़ पेड़ नर्मदा किनारे ही क्यों ?

क्या पेड़ों की आड़ मे रेत खनन में आसानी होगी? ताकि अपराधियों को बचने और भागने का पर्याप्त मौका मिले। खनन निरीक्षक, वन अधिकारी आसानी से लेनदेन कर सकें। ताकि डंफरों, नावों, खुदाई मशीनों को छुपाया व सुरक्षित रखा जा सके। बाकी बचे मप्र ने क्या पाप किया है। जो वहाँ वृक्षारोपण नहीं। वृक्षों के 6 करोड़ पौधों की वास्तविकता तो यह है, कि जनधन का अरबों बर्बाद करने के बाद भी 2 करोड़ से ज्यादा पौधे ही नहीं है। 4 करोड़ तो केवल कागजातों पर लगा हजम होगा। बाकी सच 03/07/17 के बाद स्थिती के अध्ययन के उपरांत ।

न घा भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण मैं केवल उपाध्यक्ष बदलने से काम नहीं चलेगा

और भी घाघ कार्यपालन यंत्री कुंडली मारे बैठे हैं संभागों में बरसों से

वर्तमान में नर्मदा क्षिप्रा, नर्मदा गंभीर, जो पूरी हो चुकी है, जबकि नर्मदा कालीसिंध का काम अभी शुरू हुआ है। आवश्यक था, इंदौर में कम से कम 1 संभाग की स्थापना की जाती, वैसे तो दो होने चाहिए। ताकि आसानी से काम इंदौर से नियंत्रित कर सकें। यह सारे काम बड़वाह के 32 नंबर से नियंत्रित व देखरेख किए जाते हैं। जब सभी नर्बदा परियोजनाओं में, अधिकांश परियोजनाएं तगिुने समय और दोगुना पैसा लगने के बाद में भी भ्रष्टाचार के चलते पूरी नहीं हो सकी। यह हाल बरगी बांध की दांई बांई नहरों से लेकर, इंदिरा सागर नहर, ओमकारेश्वर की दांई बांई नहरों का भी है। ऊपर से लिफ्ट इरिगेशन में बनने वाली अधिकांश प्रोजेक्ट में भी भारी भ्रष्टाचार हो रहा है।फरि का. यंत्री मीणा, 15 वर्ष से पुनासा में, करोड़ो के घोटाले, गुप्ता 5 वर्ष से ज्यादा समय से 21 नंबर, उइके बरसों से मनावर, टंडन बरसों से 32 नंबर में, बैठे हुए कर रहे हैं। बड़े-बड़े भ्रष्टाचार। दार्यी तट नहर ओम्कारेश्वर मैं दिया गया 18 वां समय वस्तिार। पूरे संगठन का हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार छुपाने 13 वर्षों बाद भी घाटी की साइट पर धारा 4 के अंतर्गत विवरण पूरा नहीं डाला जाता, अधिकांश जल उद् वाहन परयिोजनाएं मोटी कमाई के लिए, किसी का भी विवरण नहीं। इंदौर- शिप्रा सहिंस्थ लिंक परियोजना ₹432 करोड़ की, टेंडर गया रु396.25 करोड में, एमएस स्टील पाइप का व्यास 2मी का भुगतान हुआ, पाइप लगाया 180 सैंमी का, यही हाल अधिकांश उद् वाहन परियोजनाओं का है। इसलिए सैकड़ों करोड़ की योजनाएं बनाई जाती है ताकि आसानी से 10-20% कमीशन डकारा जा सके। जबकि प्रदेश की 12 बड़ी नदियों का करोड़ों क्यूसेक पानी प्रदेश से बाहर जाकर गंगा, यमुना और गोदावरी में भी मिल जाता है। नर्मदा पर बनाई जा रही जल उदबहन परियोजना का पानी भी अंत में गंगा में ही मिलेगा।

मध्य प्रदेश में सरकार बदलने से जनता को यह उम्मीद बनी है की शायद 15 वर्ष में जिस तरह से शिवराज सिंह ने भ्रष्टों को पाल पोष कर हर नर्मिण कार्य की दुगुनी तगिुनी लागत से कार्य करवाया गया जिस तरह से जनता से बिजली, सड़कों पैट्रोल आदि में लूटकर जनधन बर्बाद किया गया। शायद कांग्रेस की नाथ सरकार उन भ्रष्टों को तितर-बितर कर, ना केवल उनकी पुरानी फाइलें खोल कर भ्रष्टाचार को सामने लाएगी वरन दोषियों को सजा देने के साथ लंबे समय से अटकी परयिोजनाओं को शीघ्र पूरा करने में अपना दमखम दिखाएगी। परंतु नाथ के सरकार संभालने के बाद, घोर भ्रष्ट मक्कार पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कहने पर महा जालसाज, एतिहासिक भ्रष्ट सुधरिंजन मोहंती को मुख्य सचिव बनाना बताता है, कि 15 वर्ष से भूखे बैठे कांग्रेसी भी मोटी कमाई के लिए भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने से ऐसा लगता नहीं की वह कुछ अच्छा और बेहतर करेगी।

फिर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तो भ्रष्टाचारियों का विकास प्राधिकरण बन चुका है। जो म प्र जल संसाधन विभाग में अधिकांश घोर भ्रष्ट, निकम्मे और जालसाजों की श्रेणी में थे। वे चुन चुन कर भ्रष्टाचार से धन कमाने व लूटने के लिए नर्मदा घाटी में प्रतिनियुक्ति पर आये। नसिंदेह यह खेल, विकास प्राधिकरण की स्थापना के साथ ही शुरू हो चुका था। जो अभी तक सतत चल रहा है हर साल कुल आवंटित धन का 20 से 40% केवल भ्रष्टाचार की बंदरबांट में हीं चला जाता है। समय माया लगातार पिछले 20 सालों से इस पर कलम चला रहा है जिस के संबंध में पुराना इतिहास देखने के लिए इस www. samaymaya .com की साइट पर ईपेपर में

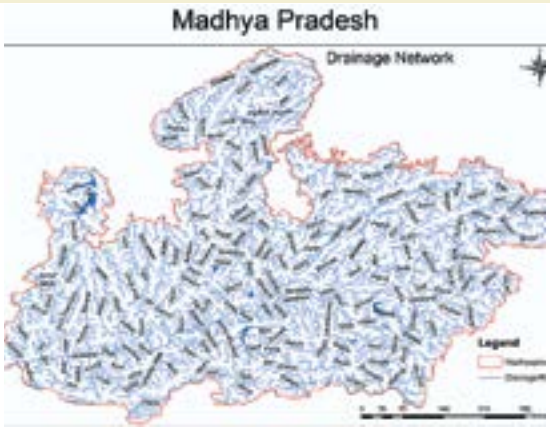

पढ़ा जा सकता है। जिसमें बांध, नहरों के, निर्माण और डूब के लिए भूमि अधिग्रहण की पुनर्वास में हजारों करोड के भ्रष्टाचार से लेकर बांधों और नहरों के निर्माण में सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया। अभी भी सतत यह प्रक्रिया इंदिरा सागर बांध की मुख्य नहर से द्वितीय व तृतीय स्तर की वितरणयिों के निर्माण में चल रहा है कोई भी काम समय पर पूरा नहीं होता जानबूझकर उसमें समय विस्तार और मूल्य वृद्धि का भावांतर भुगतान 2 से3 गुना तक हो जाता है। यही हाल बरगी की दाई बाई नहरों के निर्माण मैं भी पिछले 30 सालों से लगातार चल रहा है।

कार्यपालन, अधीक्षण यंत्री वा मुख्य अभियंता के सहयोग से करोड़ों रुपए अनेकों ठेकेदार हजम कर भाग गए। अधिकांश काम सैकड़ों करोड़ के इसीलिए करवाए जाते हैं। ताकि आसानी से 10- 20% का मोटा कमीशन आसानी से हजम किया जा सके। इसी कारण अनेकों उदवहन परियोजनाओं की शुरुआत की गई। जबकि पूरे प्रदेश के वर्षा के जल निकासी नक्शे के अध्ययन से निष्कर्ष निकाला गया। कि प्रदेश का अधिकांश जल प्रदेश की छोटी नदियों से इकट्ठा एकत्रित होकर 12-14 बड़ी नदियों में मिलकर नर्मदा नदी के माध्यम से गुजरात की खंभात खाड़ी में, तो चंबल 965 किमी की यात्रा कर, जिसका प्रदेश में जल संग्रहण क्षेत्र 59940 वर्ग किमी है जिसमें इंदौर से निकलने वाली शिप्रा, खान, तो पार्वती कालीसिंध कुनो और शओिप नदी भी चंबल में मिलती है जो जाकर इटावा में यमुना से और यमुना इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है । इस प्रकार सोन 500 किमी चलकर जिसका जल संग्रहण क्षेत्र 47849 वर्ग किमी है। टोंस नदी 238 किमी प्रदेश में बहकर गंगा में मिल जाती है। इस प्रकार 12 बड़ी नदियां जिनमें लगभग 400 से ज्यादा छोटी नदियों का जल प्रदेश से बहकर गंगा यमुना गोदावरी में मिल जाती है पर हम अपने उसका करोड़ों क्यूसेक पानी अपने प्रदेश में नहीं रोक पाते। इसके विपरीत हम मोटा धन खाने के लिए हजारों करोड़ की लिफ्ट इरिगेशन बनाते हैं ताकि मोटा धन हजम किया जा सके। जबकि प्रदेश में कहीं भी लिफ्ट इरिगेशन बनाने की जरूरत ही नहीं थी जो जल बरसात में नदियों के माध्यम से बहकर प्रदेश के बाहर जाता है हम उसको ही रोक लेते हैं तो भी हमारे यहां पर्याप्त पानी हर हर मानव बस्ती को देने के साथ साथ पर्याप्त जल कृषि की फसलों की सिंचाई के साथ उद्योगों के लिए भी आपूर्ति आसानी से कर सकते हैं। परंतु हमारे धूर्त प्रमुख अभियंता जल संसाधन के साथ और मक्कार भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारी छोटी-छोटी योजनाओं पर काम करते रहते हैं जनिका उद्देश्य अगले 25--50 साल के नियोजन का नहीं तत्काल में मोटा धन हजम किया जा सके, के लिए रहता है। वर्षा के जल का सही संचयन और उसका कृषि, मानव उपयोग और उद्योगों में उपयोग देखना है, तो पड़ोस के राजस्थान में जाकर देखा जा सकता है जहां पर वर्तमान में राजस्थान के कोटा और झालावाड़ जिले में गेहूं, चना, सरसों मसूर आदि की फसलें तू लहरा ही रही है साथ ही चारों तरफ संतरों की बगीचों की भी भरमार है। जहां छोटे छोटे से नालों से लेकर नदियों पर भी न केवल स्टॉप डैम बरन छोटी नदियों पर भी इसमें कंठाल नदी पर बढ़ा राजगढ़ डैम बना दिया। यही हाल पूरे राजस्थान में कम वर्षा जल को सहेज कर रखने से पूरे प्रदेश की आबादी को ना केवल पीने व जीने का पानी वरन कृषि व उद्योगों के लिए भी जल की व्यवस्था की जा रही है। दुख की बात तो यह है, कि हमारे प्रदेश की हजारों छोटी-छोटी नदियों के, जो फिर उसके बहाव क्षेत्र से बड़ी नदियों, और फिर 12 बड़ी नदियां जिसमें मात्र नर्मदा को छोड़कर बाकी सारी नदियों का पानी गंगा यमुना गोदावरी में मिल जाता है वह पानी अगर हम उपयोग कर पाते तो भी नर्मदा की नहरों से लिफ्ट इरिगेशन की जिसमें प्रतिदिन हजारों रुपए का बिजली खर्च है की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती जिस का बिल देने के लिए प्रशासन नर्मदा घाटी से कहता है वह नर्मदा घाटी प्रशासन से, और इस चक्कर में कृषि व उद्योगों के उपयोग की तो दूर, शनिवारी अमावस्या पर उज्जैन की शिप्रा घाट पर नहाने के लिए भी पानी नहीं पहुंच पाता। जिस के नक्शे दुनिया के हर व्यक्ति के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध है। पर प्रदेश के भारतीय प्रताडना सेवा अधिकारियों को पिछले 20 वर्षों से उपलब्ध नहीं हो पाए जो प्रदेश में पानी रोकने का भविष्य का नियोजन कर सकते।

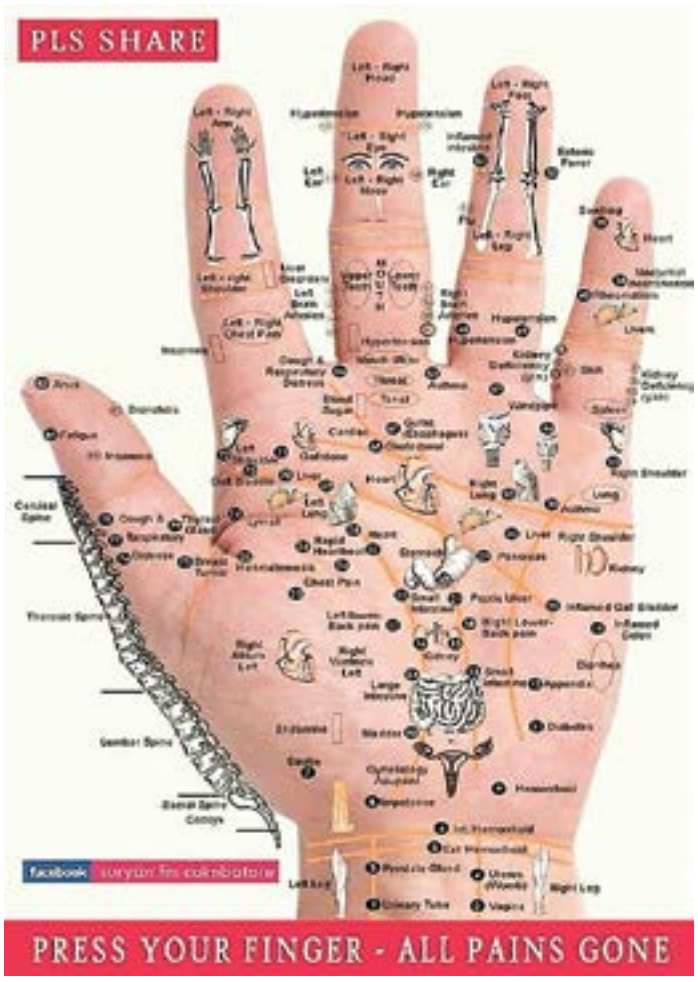

स्वयं को स्वस्थ रखने का हस्त दाव सिद्धांत

पूरी दुनिया में मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए अनेकों पद्धतियों का विकास हुआ। प्रकृति ने मनुष्य के शरीर की बनावट इस तरह से बनाई है कि वह चाहे तो अपने ही शरीर के हाथ की हथेली, कान व अन्य हिस्सों में कुछ खास बिंदु को दिवाकर अपने आप को स्वास्थ्य रख सकता है। यहां पर अभी हम मनुष्य के शरीर के हाथों की हथेली के और उस पर मनुष्य शरीर के सारे हिस्सों में उत्पन्न पीड़ा को दूर करने के लिए विशेष बिंदु पर दबाव बनाकर निरोगी रहने का शास्त्रीय तरीका प्रस्तुत कर रहे हैं।

जनता से लूटा हुआ धन मंत्रियों और अधिकारियों तुम्हारे बाप की जागीर नहीं

13 साल के बाद में भी सूचना के अधिकार में जानकारी नहीं और विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध कराते नहीं । खुले में मंचों से नेता जनता से मताकर्षण और चुनाव जीतने के लिए कर्ज माफी, मुफ्त का लैपटॉप, मोबाइल फोन, साइकिल व अन्य सामानों का लालच देकर चुनाव जीते जाते हैं क्या यह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं। आखिर यह यह धन मध्यमवर्गियों से ही लूटा जाता है और बदले में उन्हें तिरस्कार झेलना पड़ता है।

भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू हुए भले ही 70 साल गुजर गये हो। परंतु राष्ट्र मैं लोकतंत्र और शासन व्यवस्था परिपक्व नहीं हुई। यहां पर अभी तक आदिकालीन युग की जिसकी लाठी उसकी भैंस बली व्यवस्थाएं वर्तमान में भारत की शासन व्यवस्था में चल रही है। अर्थात सत्ताधीश और विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए खुले में धन और बल के दम पर जनता को लुभाने के लिए उन्हें लालच देकर जिस में किसानों को ऋणमाफी, युवाओं और छात्रों को जन धन से बेरोजगारी भत्ता, मुफ्त का लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल फोन साइकिल आदि का लालच देकर सत्ता हथियाने का खेल पिछले 70 सालों से जबकि यह चुनावी आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन होता है। इस बार 25 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सामाजिक संगठन द्वारा 2011में लगाई गई याचिका पर दिए गए निर्णय मैं स्पष्ट कहां और निर्णय लिया गया हर उम्मीदवार को उसके पुराने आपराधिक प्रकरणों जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट से लेकर न्यायालय में लंबित प्रकरणों जिसमें आरोप लगा दिए गए हो ना लगाये हो, जिन प्रकरणों में सजा हो गई हो सजा पूर्ण करने के बाद आदि सब की जानकारी आपको ना केवल उम्मीदवारी के फॉर्म में भरनी है, वरन चुनाव का मतदान होने से 48 घंटे पूर्व उन सभी प्रकरणों के बारे में आपको अखबार में विज्ञापन भी देना है।

मध्यमवर्गीय को लूटो, वोटों के लिए अमीरों और गरीबों को लुटाओ

इसके विपरीत 25 सितंबर 2018 के बाद भारत के 5 राज्यों में जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मेघालय आदि में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए परंतु किसी किसी भी उम्मीदवार ने भाजपा-कांग्रेस व अन्य सभी राजनीतिक दलों व निर्दलीय ने इस संबंध में विज्ञापन समाचार पत्रों में ही नहीं छापा जो कि खुले रूप से सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अब मानना था इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर सत्ता धीश और विपक्ष में राष्ट्रीय स्तर की दल कांग्रेस ने कोई भी टिप्पणी और कार्यवाही नहीं की। साथ ही एक दूसरे की इस मामले में कोई भी आरोप भी नहीं लगाया गया क्योंकि दोनों ही दलों के प्रत्याशी अधिकांश आपराधिक श्रेणी के अनेकों प्रकरणों में लिप्त हैं। इसमें अनेको तो हत्याओं की गंभीर अपराध मैं सजा पूरी कर चुके हैं, या उनके ऊपर न्यायालयों में आरोप लगाए जा चुके हैं और प्रकरण हम दिखाएं लंबित हैं, अधिकांश पर आपराधिक प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना में दर्ज हैं और प्रकरणसे संबंधित कार्रवाई न्यायालयों में भी लंबित है इसमें मुख्यमंत्री से लेकर राजस्थान का उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट जो अपराधों में लिप्त होने के उपरांत भी ना केवल चुनाव लड़ा उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले चुका है। अर्थात यह देश सभ्यय लोगों की सत्ता का देश नहीं यह देश आदिमकालीन असभ्य अपराधियों की सत्ता का देश है। यहां उच्च पदों पर बैठे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी यथार्थ में भारतीय प्रताड़ना सेवा के वो अधिकारी हैं, जो स्वयं घोर, बिकाऊ, गुलाम, जालसाज, चालबाज, सत्ता धीश नेताओं की रखैल और सफेदपोश अपराधी हैं। जो जिलों में जिलाधीश आयुक्त आदि के रूप में कार्यरत होते हैं। चुनाव आयोग के मुख्य प्रतिनिधि के रूप में बैठकर, सत्ताधीश राजनीतिक पार्टियों के लिए सारी जालसाजिया संपन्न करते हुए चुनाव कार्यों को संपन्न करवाते हैं।

निर्दलीय व छोटी पार्टी के उम्मीदवारों के साथ में उनका वाहशियाना व्यवहार, जिसमें उम्मीदवार का नाम बदलने से लेकर पार्टी के एबी फॉर्म को रद्द करने उसे निर्दलीय घोषित करने तक का कार्य करते हैं। जैसा कि 2014 में लोकसभा के चुनाव में इंदौर में पदस्थ जिलाधीश आकाश त्रिपाठी ने अजमेरा प्रवीण कुमार के साथ किया था। 4 अप्रैल 2014 को अजमेरा प्रवीण कुमार ने हिंदू महासभा का एबी फॉर्म लोकसभा प्रत्याशी के रूप में जमा कि या जिसे उस समय स्वीकार कर लिया गया परंतु 9 अप्रैल 2014 को अजमेरा प्रवीण कुमार का नाम बदलकर प्रवीण कुमार जैन कर दिया गया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा क ए बी फॉर्म जालसाजी पूर्ण तरीके से रद्द करते हुए उन्हें निर्दलीय घोषित कर दिया गया। जो इन हरामखोर जालसाजों की बदतमीजियों का उत्कृष्ट प्रमाण था। निसंदेह अखिल भारतीय हिंदू महासभा का बहुत बड़ा दल नहीं था।

भाजपा सरकार द्वारा बंद की गई कर्मचारियों अधिकारियों की पेंशन पुनः शुरू की जानी चाहिए

प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों को छठवां और सातवां वेतनमान मिल जाने से कर्मचारियों और अधिकारियों को को लगा कि भाजपा उनकी सबसे ज्यादा हितेषी पार्टी है जबकि भाजपा ने सत्ता संभालते ही सन 2006 में कर्मचारियों को ईपीएफ की जगह सीपीएफ का प्रावधान कर उन वर्तमान में कार्यरत जो सन 2006 के बाद भर्ती हुए थे अधिकारियों कर्मचारियों पेंशन खत्म कर दी। स्वाभाविक सी बात थी यह अप्रत्यक्ष घाटा कर्मचारियों और अधिकारियों को तत्काल समझ में नहीं आया। परंतु अब जब पुनः कांग्रेस सरकार आ गई है तो कर्मचारियों अधिकारियों के संगठनों को चाहिए। वह पुनः पेंशन लागू करवाने की सरकार से मांग करें। जब एक कर्मचारी 30 -35 साल नौकरी करता है।

सरकार उसका 10% वेतन में से काट कर स्वयं का भी 10% अंशदान जमा कर उसके बुढ़ापे की व्यवस्था कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य थी।

शास.कर्मियों को 35 वर्ष के बाद भी पेंशन नहीं, विधायक सांसद 10 दिन में भी पात्र

ताकि वह किसी भी प्रकार से सेवानिवृत्ति के बाद भी आर्थिक रूप से सक्षम बना रहे।

परंतु भाजपा ने आते ही इस व्यवस्था को सन 2006 में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इशारे पर खत्म कर दिया परंतु कर्मचारियों और अधिकारियों के संगठनों में इसके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई जबकि एक विधायक संसद मात्र 5 साल के लिए चुना जाता है। और कई बार तो वह सरकार महीने 2 महीने में गिर जाने के बाद में भी जीवन भर की जन धन से पेंशन का पात्र हो जाता है और यह सारे कानून विधायकों सांसदों ने अपने लिए आसानी से पास करवा लिए।

इसके विपरीत बेचारे कर्मचारियों अधिकारियों को दोनों 30- 35- 40 साल तक अपनी सेवाएं सरकार को दी और अपने ही धन के बदले में वह जीवन की आर्थिक सुरक्षा का जो प्रावधान था उसे सरकार ने खत्म कर दिया बेशक यह शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ निजी क्षेत्र के लंबे समय तक उद्योगों में संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की जीवन पर्यन्त आर्थिक सुरक्षा के विपरीत था। जिसे तत्काल बहाल करवाया जाना चाहिए आखिर पैसा तो सरकार वही देगी। जो उसने कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन में से जीवन भर काटा।

वैसे भी भाजपा की अधिकांश सरकारें पूजी पतियों के गुलाम कठपुतली होती है। उन्होंने पूंजी पतियों के इशारे पर अपने अधिकतम लाभ और कर्मचारियों अधिकारियों से संबंधित 54 से ज्यादा श्रम कानूनों को समाप्त कर दिया। ताकि पूंजीपति अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों का हर प्रकार से शोषण कर सकें यहां तक की न्यूनतम वेतन, कार्य के 8 घंटे, आदि की शर्तों को भी समाप्त कर दिया गया इसमें कर्मचारियों और अधिकारियों के पेंशन के भारी-भरकम भार से बचने के लिए अपने इशारे पर इस बार को भी खत्म कर दिया गया इस तरह से पूंजीपति अपने मोटे लाभ के लयि अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों का भरपूर शोषण करने के बाद में भी ना केवल न्यूनतम वेतन के भुगतान वर्ण उसकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के सभी प्रकार के कानूनी दायित्वों से बचने के लिए में सफल रहा। विशाल अधिकांश पूंजीपतियों ने मोटा धन राज्य व केंद्र सरकार से इन सारे कानूनों को खत्म करवाया जिसने जिसमें पेंशन भी शामिल था। यही व्यवस्था चीन में लागू की गई ताकि अधिकांश विश्व के बड़े उद्योगपति वहां पर अपने उद्योग लगाकर वहां के श्रमिकों का घोर शोषण कर 12 घंटे काम लेकर भी न्यूनतम वेतन भी नहीं देती थी।

जिसके दुष्परिणाम स्वरूप वहां की अधिकांश श्रमिक आबादी समय पूर्व, अर्थात 40-50 वर्ष की उम्र में ही बीमार, बूढ़ी, कमजोर और अल्प आयु हो गई। जिसका भारी खामियाजा चीन की सरकार को वर्तमान में अत्यधिक खर्च स्वास्थ्य पर कर भुगतना पड़ रहा है।

दूसरी ओर सभी शासकीय विभागों के कर्मचारियों अधिकारियों को जो पेंशन दी जाती है या थी। वह पेंशन कर्मचारियों अधिकारियों के वेतन से ही काटकर दी जाती है जबकि वेतन भुगतान के समय उसके कुल वेतन, भक्तों आदि के भुगतान में से आयकर की राशि वसूल कर ली जाती थी। इसके बाद पेंशन के भुगतान के समय में भी यदि पेंशन राशि आयकर की सीमा से ज्यादा होने पर उसमें से भी आयकर काट लिया जाता है अर्थात कर्मचारी अधिकारी को एक बार भुगतान किए गए वेतन पर दो बार आयकर की वसूली पूर्ण रूप से अवैधानिक है। इसके विपरीत विधायकों सांसदों मंत्रियों मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री वेतन और भत्तों से ना तो आयकर काटा जाता है दूसरी तरफ वे 10 दिन भी यदि विधायक और सांसद रह चुके हैं तो भी वे पेंशन की पात्रता के साथ उनकी पेंशन में से आयकर की कटौती नहीं की जाती आखिर यह दोहरा चरित्र कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ क्यों अपनाती है। जबकि चपरासी बाबू अधिकारी आदि सब के लिए उनकी न्यूनतम योग्यता, न्यूनतम और अधिकतम उम्र की सीमा के साथ परीक्षा देनी पड़ती है। इसके साथ ही उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकरण नयिुक्ति के समय नहीं होना चाहिए उनका स्वास्थ्य परीक्षण होता है। तब उनका चयन उस पद के लयि किया जाता है। इसके विपरीत पंच, सरपंच से लेकर विधायक, सांसद बनने के लिए ना ही कोई न्यूनतम योग्यता, न ही कोई चरित्र प्रमाण पत्र, वे हत्या लूट डकैती व देशद्रोह के अपराधी, आरोपी, सजा भोगे भी हो सकते हैं। न ही कोई परीक्षा स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। फिर भी चुनाव लड़ने के लिए पात्र होते हैं । जीत जाने पर पंचायतों की सत्ता से लेकर प्रदेश की और देश की सत्ता तक चलाते हैं। कानून बनाते हैं। देश की 132 करोड लोगों का भविष्य लिखते हैं। और अपने स्वार्थों की खातिर उनका भविष्य भी बर्बाद करते हैं। क्या यह लोकतंत्र है या लूट का अंध तंत्र है।

विश्व एडस दिवस का सच

डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन नहीं, वर्ल्ड हजार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन

यह केबल डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन नहीं अर्थात वास्त विकढता यह है यह वर्ल्ड हजार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन और यूरोपियन जालसाज डकैतों की बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों का विश्व स्वास्थ्य बिगाड़ो संगठन एक संयुक्त व्यावसायिक संवर्धन संस्था है। वही कंपनियां इस संगठन को धन देकर अपने हिसाब से चलाती हैं। पहले नई खोजों के नाम पहले कुछ भी उल्टा-सीधा बनाओ सिर बीमारियां खड़ी करो और अपना माल बेचो अर्थात उन ने जो बनाया है। उसे खरीदने के लिए पहले भय पैदा करो। फिर अपना माल, दवाइयां, उपकरणजिसमें मधुमेह, हृदय, किडनी, स्वाईन फ्लू, आदि की हजारों गुना दाम पर मोटा कमीशन सरकारों, डाक्टरों को बांट कर बेचों।

यह षड्यंत्र 1910 से अमेरिकी और युरोपियन कंपनियों द्वारा लगातार किया जा रहा है। हर 10 साल में कोई उल्टी-सीधी नई खोज करना फिर उसका परीक्षण करने नई बीमारी पैदा करना फिर अपना हजारों गुना में माल बेंचना। वही हाल उन्होंने अपने कंडोम बेचने के लिए ऐड्स नाम की बीमारी का पूरी दुनिया में हवा फैलाकर 10 पैसे के कंडोम को आसानी से 10 में बेचने का षड्यंत्र था जबकि एडस नाम की कोई बीमारी होती ही नहीं। जो अमेरिका ने अपने देश के बच्चों को 1980 में सरकार की तरफ से ध्यान हटाने के लिए और स्कूलों में ही बच्चों को संभोग केली कीड़ा में रत करने के उपरांत भी बच्चे पैदा ना हो लड़कियां गर्भ की शिकार ना हो। इसलिए उन्होंने पहले फ्री कंडोम बांटने उसका खर्चा निकालने के लिए दुनिया में एड्स की हवा फैलाई गई। ताकि बेंच कर मोटा धन बटोरता जा सके।

40 साल के बाद आज तक कंडोम का कोई भी वायरसों कीटाणु नहीं खोज पाए। क्योंकि यथार्थ में ऐड्स नाम की कोई बीमारी दुनिया में होती ही नहीं और डॉक्टर एलोपैथिक के जब बहुत सारी बीमारियां एक दूसरे के विपरीत स्वभाव की मानव शरीर में हो जाने के कारण जब अनियंत्रण की स्थिति बन जाती है। तो आसानी से अपने आप की खाल बचाने के लिए डॉक्टर चला देते हैं कि इसे एड्स हो गया। मैंने आयुर्वेद और होम्योपैथि का अध्ययन किया था और गाहे में बगाहे अभी भी पढ़ता रहता हूं। आयुर्वेद में 14 प्रकार के प्रमेह का वर्णन व उनकी चिकित्सा मिलती है। प्रमेह रोग स्त्री और पुरुषों की यौन और जननांग रोगों का विवरण देता है। जिसमें अंतिम उपदंश और सुजाक होते हैं। यदि दोनों एक साथ भी हो जाएं तो भी आयुर्वेद में चिकित्सा के साथ साथ उसके वृहत नियंत्रण के उपाय दिए हुए हैं। जो की महर्षि धन्वंतरि द्वारा हजारों वर्ष पूर्व ही लिख दिए गए थे। उसके बाद में सुश्रुत, चरक, आदि अनेकों समय2 पर जन्में आयुर्वेदाचार्य ऋषि-मुनियों ने भी इन पर काफी काम किया।

पुरुषों स्त्रियों को संभोग के उपरांत जननांगों को सहवास से फैलने वाले रोगों से बचाव के लिए तात्कालिक उपायों में अपने जननांगों को अपने ही मूत्र से प्रक्षालन का सबसे सटीक उपाय दे दिया था। होम्योपैथिक में भी उपदंश व सुजाक के नियंत्रण के लिए जर्मन वैज्ञानिक और होम्योपैथिक चिकित्सा के जन्मदाता हेनमन ने अनेकों औषधियां तैयार कर दी थी। बेशक 16 -17वीं शताब्दी में में मलेच्छ राष्ट्र फ्रांस और यूरोप में उपदंश व सुजाक महामारी का रूप ले लिया था। यथार्थ में लिंग को कवर करने के लिए क्यों बारीक पतले चमड़े का खोल बनाकर संभोग को पूरा करने के लिए कबर तैयार किया गया था ताकि योन रोग ना फैल सके स्त्री और पुरुषों में कंडोम का चलन तभी से शुरू हुआ था। निसंदेह पूरे आयुर्वेद में लिंग को कवर करके संभोग करने की कोई प्रणाली विकसित नहीं हुई थी। परंतु यौन रोगों से संबंधित, बारीकी से विश्लेषण और चिकित्सा की जितनी व्यवस्था आयुर्वेद में की गई है दुनिया की किसी भी अन्य चिकित्सा पद्धति में आज तक नहीं की जा सकी।

आयुर्वेद में भी प्रमेह की अंतिम दोनों अवस्थाओं उपदंश सुजाक में भी जब अपनी अंतिम अनियंत्रित अवस्था में पहुंचता है तो स्त्री पुरुषों की मृत्यु का कारण बन जाता है जो शरीर के हर अंग में फैल कर भारी विकृतियों उत्पन्न कर देता है। निसंदेह कंडोम ऐसे सभी यौन रोगों और अनावश्यक स्त्रियों में गर्भ को रोकता है। जिसे 1998 से लगातार बार-बार मेरे समय माया द्वारा प्रकाशित करने के कारण जो कि अमेरिका के व्हाइट हाउस, व अन्य देशों के दूतावासों को डब्ल्यूएचओ को भी पीडीएफ कॉपी भेजी जाती है। जानबूझकर उन्होंने एड्स के प्रचार की अपेक्षा अस्पतालों में भी यौन रोग और गर्भनिरोधक के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया।

इसके संबंध में भोपाल के जी टीवी कंपलेक्स में सन 1960 से लेकर 2008 तक चलने वाली ब्रिटिश लाइब्रेरी में 98 के अंत में लंदन टाइम्स में नार्वे के 200 डॉक्टरों के एक समूह ने इस पर काफी शोध करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला की यथार्थ में एड्स नाम की कोई बीमारी नहीं होती। वह केवल कंडोम बेचने और उससे अरबों रुपए प्रतिदिन की कमाई करने का षडयंत्र मात्र है। एड्स के भय को फैलाने और कंडोम से मोटी कमाई करने में एशियाई देशों में बढ़ती आबादी को रोकने के लिए वर्ल्ड हजार्डियस आर्गेनाइजेशन ने हीं इस प्रपंच का षड्यंत्र रुचकर एड्स नाम की काल्पनिक बीमारी को पैदा कर यह भय 1980 से सभी प्रसार माध्यमों पर फैलाना शुरू कर दिया था। वैसे इस षड्यंत्र के पीछे विश्व शैतान संघ का छिपा षडयंत्र यह भी था कि एशियाई देशों में पारिवारिक संबंधों और मूल्यों को खत्म कर यौनाचार की उच्श्रृंखलता फैला कर आसानी से हिंदू धर्म को नष्ट किया जाए और ईसाइयत को बढ़ावा दिया जाए। इसमें वे पूर्णतया सफल रहे हिंदू धर्म के पारिवारिक मूल्यों को नष्ट कर उच्श्रृंखलता को बढ़ाने में वे सफल रहे। मेरे पाठकों को अब समझ में आ गया होगा कि एडस नाम की बीमारी क्या है।

प्रस्तुतकर्ता प्रवीण अजमेरा

मोदी का अंतरिम बजट 2019, पाखंड और आंकड़ों की बाजीगरी

पेज 1 से जारी

इसके विपरीत राजकोषीय घाटा रुपए 591064 करोड का अनुमानित है वास्तविकता में यह 7 लाख करोड़ तक भी पहुंच सकता है।यथार्थ में इस पूरे बजट में पिछले वित्तीय वर्ष में अपनी झूठी छल कपट पूर्ण प्रशंसा के दृश्य श्रव्य विज्ञापनों का देश विदेश में जो खर्च किया गया उसने इस राजस्व घाटे को लगभग 10% बढ़ा दिया। जिसकी बजट मे। देश के बजट में दिखावे औरपूजी पतियों के लाभ और अपनी मोटी कमाई के लिए स्मार्ट सिटी, सुपर कॉरिडोर सुपर एक्सप्रेस वे, हाई स्पीड ट्रेन जैसे सैकड़ों अवांछित कार्यों के लिए पिछले वर्षो में जो धन खर्च किया गया। उससे सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। देसी केंद्रीय वह सभी राज्य सरकारों के सभी मंत्रालयों में जिसमें रक्षा मंत्रालय में भारत की सुरक्षा के लिए देश की सीमाओं पर आवश्यक जल थल और नभ के लिए सेनाओं में आवश्यक 20000 अधिकारियों और 5लाख सैनिकों की, रेलवे में खाली पड़े 10 लाख से ज्यादा पदों की, अर्ध सैन्य बलों जिसमें सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, सभी राज्यों की पुलिस मैं लगभग 20 लाख सैनिकों की, सभी विभागों में आवश्यक लगभग 5लाख अधिकारी निरीक्षक, व केंद्र व राज्यों के शिक्षा संस्थानों में उच्च शिक्षा से

लेकर प्राथमिक शिक्षा तक लगभग 10 लाख शिक्षकों की तत्काल आवश्यकता है, 1000000 कंप्यूटर ऑपरेटर, बाबू व अन्य कर्मचारियों की भर्ती की शासकीय विभागों की जाती। जिन की भर्तियां सन 1990 के बाद से विश्व व्यापार के छोटे देशों की सरकारों को मोटा कमीशन बांटकर उनके प्राकृतिक व मानव निर्मित आय के सभी स्त्रोतों पर कब्जा कर मोटा लाभ कमाने के लिए न्यूनतम कर्मचारी भार के अंतर्गत उनकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करो संगठन के दिशा निर्देशों के कारण लगभग 30 सालों से भर्तियां नहीं की गई।

सभी मंत्रालयों में 1990 की अपेक्षा कार्यभार 5 से 10 गुना ज्यादा बढ़ गया परंतु कर्मचारियों की संख्या 5 गुनी करने की अपेक्षा 1990 की तुलना में आधी रह गई इस प्रकार वास्तविकता में अधिकांश सरकारी कार्यों को बाहरी संस्थाओं को ठेके पर देकर एक तरफ स्तर हीन काम चलाऊ काम करवाया जा कर दुगुना धन बर्बाद किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ शासकीय कार्यों में बाहरी हस्तक्षेप बढ़ने से गोपनीयता समाप्त हो रही है मोदी को अपने इस अंतरिम बजट में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर यदि एक करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाता तो मोदी को सत्ता में पुनः आने से कोई नहीं रोक सकता था। वैसे भी सरकारी बजट झूठे आंकड़ों की जनता को दिखाऊ, काम चलाऊ बाजीगरी भर होता है। जिसका अनुभव पिछले 5 सालों में हमारी वर्तमान और युवा पीढ़ी ने अरबों रुपए रोज के टीवी समाचार चैनलो पर आधे से 1 घंटे के व 5से 10 के पेज के झूठी प्रशंसा के विज्ञापनों पर जनधन के खर्च और आंख मीच कर लूटाने से देखा जा सकता है।

जिससे न केवल मोदी सरकार स्थाई होती और रोजगार बढ़ने से देश के आम नागरिक की क्रय क्षमता बढ़ने से अन्य दोगुने रोजगार निजी क्षेत्रों में बढ़ जाते तब यथार्थ में देश में संपन्नता आती।परंतु देश के आम जन की आधारभूत आवश्यकताओं जिसमें बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार को छोड़ देश के युवाओं को निकम्मा बनाने के लिए बेरोजगारी भत्ते की घोषणा कर दी गई केवल चुनावी वोट इकट्ठे करने के लिए फेकू मोदी की बात पर जनता को विश्वास ही नहीं रहा क्योंकि जिन झूठी घोषणाएं, वादों और दवि सपनों के बाग दिखा कर सत्ता हथियाई गई थी। जनता के दिमाग से वह नशा काफूर हो चुका है। उल्टे ही अच्छे खासे चलते हुए अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करते आगे बढ़ते हुए देश को इस हरामखोर जाल साज आपराधिक मानसिकता के मोदी और अमित शाह ने अपनी लूट और कमाई के लिए बर्बाद कर दिया अपने पूंजीपति आकाओं के लिए बैंकों का, बीमा कंपनियों का संविलियन कर एक तरफ रोजगार समाप्त किए जाएंगे, आपसी व्यवसायिक प्रतियोगिता समाप्त कर आम जनता को रुकने के लिए छोड़ दिया जाएगा दूसरी तरफ निजी क्षेत्रों में बढ़ती हुई बैंकिंग और बीमा व्यवसाय लूट के अड्डे बन चुके हैं।

मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग, कदम-कदम पर जालसाजी और भ्रष्टाचार का तांडव

माही बांध की आदिम जाति की विकास निधि से खेलकूद में जनधन की बर्बादी

पूरे विभाग में कदम कदम पर भ्रष्टों और जालसाजों का डेरा है। सूचना के अधिकार में जानकारी देने के नाम पर इंदौर में बैठा भ्रष्ट और मक्कार मुख्य अभियंता वाईसी शर्मा ने कानून का मजाक उड़ाते हुए अपना नया आदेश निकाल दिया। जिसमें अपने कार्यालय के सहायक यंत्री को अपना लोक सूचना अधिकारी घोषित कर दिया यही हाल उसने अपने सभी संभागीय कार्यालयों में वहां के सहायक यंत्री को लोक सूचना अधिकारी कार्यपालन यंत्री को वहां का अपीलीय अधिकारी घोषित कर दिया हरामखोर ने, स्वाभाविक था कोई भी संभाग जानकारी नहीं देता। जोकि धारा 19 के कानून का खुला मजाक है जिसमें जिलाधिकारी और संभागीय अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी और उससे वरिष्ठ को वहां का अपीलीय अधिकारी बनाया गया है।

दूसरी ओर धारा 4 की 17 बिंदुओं की जानकारी 13 साल गुजर जाने के बाद भी विभाग की उप संभाग से लेकर मुख्यालय तक विभागीय साइट पर नहीं डाली गई। यहां तक की माही बांध और उसकी नहरों के आदिवासी विकास की आवंटित लेखा शीर्ष 23/4701 निधि से इंदौर में 9 से 14 फरवरी तक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करा ली गई। इस खेलकूद प्रतियोगिता में सभी खिलाड़ी 55 वर्ष की उम्र से अधिक थे। नर्मदा घाटी विकास विभाग का जाल साज बाबू आशिक अली जो विभाग की खेलकूद संघ का अध्यक्ष है। जो पिछले 12-15 वर्षों से शासकीय धन का भारी दुरुपयोग कर एक तरफ अपने शासकीय कार्य से गायब रह कर अपनी मौज मस्ती में उपयोग कर घूमता फिरता रहा है। तो दूसरी तरफ खुले में सरकारी कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए झूठे दिलों से पैसा हजम करता रहा है। जिसकी अनेकों जाचें लंबित है इसके उपरांत भी इस मुख्य अभियंता ने हीं रुपए 38.90 लाख पत्र क्रमांक509/कार्य--22/स्पोर22/नताक इंदौर दिनांक 9.11.18 पत्र भेजकर स्वीकृति प्राप्त की। जिसे यहां के आयोजक कार्यपालन यंत्री अब अनुविभागीय अधिकारी सोनी जो पिछले 15 वर्ष से इंदौर में जमा हुआ है मुख्यालय देपालपुर होने के बावजूद वहां के कार्यालय में ताला डाला रहता है सोनी इंदौर में ही डेरा डाले जमे रहते हैं और की शर्मा चाकरी करते हैं।

श्यामगढ़ में रुपए 1650 करोड का गांधी सागर बांध से मोटर से पानी उठाकर मंदसौर के शामगढ़ में पहुंचाकर जो बांध बनाने जा रहे हैं उसका भी उद्देश्य लगभग रु500 करोड़ हजम करना है। पूर्व में भी विभाग ने उदवहन परियोजनाओं के भारी बिजली खर्च और रखरखाव के चलते सभी परियोजनाओं को बंद कर दिया था परंतु मोटे कमीशन के चलते हैं शिवराज सरकार ने ऐसी योजनाओं को ना केवल नर्मदा घाटी में लगभग रु 15हजार करोड से ज्यादा की परियोजनाओं को अंजाम दिया जा रहा है ताकि 30 से 40% तक का धन हजम किया जा सके । वर्तमान में मध्यप्रदेश में17 बड़ी परियोजनाएं जिसमें बाणसागर, बरियापुर, बारना, हरसी, चंबल नहरे, कोलार महान, माही, राजघाट, हलाली, अपर बाणगंगा, तवा, सिंध, थनवार, उर्मिल, 84 छोटी परियोजनाएं व सेकडों लघु परियोजनाएंधीमी गति के समाचारों की भांति लागत बढ़ाने, समय विस्तार के माध्यम से पैसा हजम करने के लिए अधिकांश जिलों में चल रही है। यहां प्रतिवर्ष लगभग रुपए 50हजार करोड खर्च में 10हजार करोड से ज्यादा यहां पर मंत्री से लेकर उपयंत्री तक हजम कर लिया जाता है इसलिए यहां बैठे हरामखोर सूकरों की फौज जानकारी देने के नाम पर जालसाजी पूर्ण बहानों की सूची थमा देती है। फिर अधिकांश उप यंत्री सहायक यंत्री कार्यपालन यंत्री अधीक्षण यंत्री तक एक ही स्थान पर 20--20 वरसों से कुंडली मारे भ्रष्टाचार के दम पर बैठे हुए हैं। जिन की जानकारी कोई भी कछार का मुख्य अभियंता, चाहे वो नर्मदा ताप्ती हो, गंगा, जमुना, चंबल, नर्मदा, माही, धसान केन, सिंध, बानगंगा, बेतवा, ताप्ती कछारों के मुख्य अभियंता वाह अधीक्षण यंत्री के साथ उनके घोर धूर्त कार्यपालन यंत्री तक अपने भ्रष्टाचारों में गले तक डूबे होने के कारण देना नहीं चाहते। यहां तक की खरगोन जिले में 1992 से पदस्थ भगोरा जो वहीं पर 2002 में कार्यपालन बाद में 2010 में अधीक्षण यंत्री बनकर मोटा भ्रष्टाचार करते हुए और धन लुटाते हुए बैठा हुआ है जिसकी कम से कम 15 खरगोन जिले की परियोजनाओं में एक बार टेंडर होने के बाद आधा अधूरा काम करवाया भुगतान किया और काम बंद कर दिया उसके बाद में उसी कार्य का पुनः निविदा जारी कर कार्य प्रारंभ करवा दिया गया की अनेकों जातियां और प्रकरणों में मध्य प्रदेश महालेखाकार की 2005 से हनी को टिप्पणियों और लोक लेखा समिति में पहुंचने के बाद में भी ना तो उसे हटाया गया और ना ही उस हरामखोर जाल साज की जांच की गई। आश्चर्यजनक तो यह है 1992 से लेकर 2019 तक कांग्रेस भाजपा दोनों ने शासन किया परंतु उस बंदे का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया और ना ही कोई जांच प्रारंभ की गई सुविधा स्वाभाविक है कि ऐसे भ्रष्टों को बचाने उनसे मोटा धन ऐंठने के लिए उनके वरिष्ठ स्तर पर बैठे पूर्व के दीर्घकाल तक जमे रहे प्रमुख सचिव आर एस जुलानिया के खास मुख्य अभियंता मुंह लगे शर्माजो इंदौर में पदस्थ किया गया है। जालसाज ने सब को बचाने के लिए जनधन को अपने बाप की जागीर मान लूटपाट और भ्रष्टाचार की जानकारी देने से बचने सूचना के अधिकार कानून को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर लागू कर दिया है यहां तक की वहां बैठा घोर निकम्मा और अपने ही विभाग के हर कर्मचारी अधिकारी से इसे हर काम के पैसे मांगने वाला व्यास बाबू धारा 6 (3) में सूचना अधिकार के पत्रों के अंतरण की तो दूर वह शुल्क के पत्र भी कभी किसी को नहीं भेजता और उनके पत्रों के जवाब 4-4 साल तक नोटिस बोर्ड पर लटकते रहते हैं।

वैसे इस विभाग के कार्यों की शासकीय अनुसूचित दरों की पुस्तिका, से किसी भी कार्य का प्राक्कलन बनाते समय ही वर्तमान दरों से 20 से 25% ज्यादा कीमत के अनुमान के बनाए जाने के साथ ही त्वरण गति के माध्यम से नहरो के बहाव क्षेत्र को भी 40-50% तक ज्यादा दिखाकर जानबूझकर इसी प्रकार सिंचाई के क्षेत्र को भी 40% तक ज्यादा दिखाया जाता है। प्रमुख सचिव व अभियंता प्राक्कलन स्वीकार करने फिर प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भी मोटा धन हड़पा जाता है। मुख्यालय में यदि संबंधित मुख्य अभियंता अधीक्षण व कार्यपालन यंत्री मनचाहा धन खर्च करते हैं तो प्राक्कलन मैं बिना जांच पड़ताल और मीन मेख निकाले प्रशासनिक स्वीकृति आंख मीच कर दे दी जाती है।फिर वही हाल तकनीकी स्वीकृति के लिए भी होता है। इसके बाद निविदा जारी की जाती है निविदा स्वीकृति से लेकर कार्यादेश जारी होने तक हर कदम पर ठेकेदार को धन बांटना पड़ता है। यही कारण है, की हर वरिष्ठ मंत्री जल संसाधन विभाग चाहता है ताकि मोटी कमाई की जा सके। निसंदेह इसमें हस्सिा मुख्यमंत्री का भी होता है। दूसरी और यदि यह स्वीकृति हजारों करोड़ के किसी बड़े बांध और परियोजना की होती है ऐसा पैसा केंद्र सरकार के जल संसाधन विभाग को भी बांटना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में जहां प्रारंभ से लेकर अंत तक पग पग जालसाजी की रोटी डग डग डकैती का धन हो, वहां अपने आप को घोर ईमानदार बताने वाला वाई सी शर्मा जो हर अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री से जहां पर बहुत ज्यादा काम है जैसे खरगोन बड़वानी बुरहानपुर धार खंडवा शाजापुर आगर झाबुआ मनावर माही नीमच मंदसौर रतलाम संभागों से लाखों का महीना कमाने वाला उनकी जानकारी कैसे सार्वजनिक हो जाने दे ।

बसंत

केलिन में, क्यारिन में आई बहार,
बसंत आयो, आयो चहुँ दिशी निखार,
धरा ने करा सतरंगी श्रृंगार।
प्रेमी कल्पे, करे, मिलन पुकार।

अमराई मोरन से महकी,
मस्त पवन घर आंगन बहती।
वन, बागन, चिड़ियां चहकीं।
धरा पर कामाग्नि में देह दहकीं।

महके टेसु बन अंगार।
वन में महुआ की मादकता।
विरहाग्नि में पिहू पिहू कर
संगनी की करे पुकार।

कवि

प्रवीण अजमेरा

युवाओं को रोजगार दो, निकम्मा मत बनाओ भत्ता दे कर

सत्ताधीशो जनधन बाप की जागीर नहीं जिसे कहीं भी लुटाओ

केंद्र में अकेले रेलवे में 10 लाख से ज्यादा पद, केंद्रीय रिजर्व बलों सैन्य बलों मैं भी 20 लाख से ज्यादा, बैंकों, बीमा, तेल, गैस कंपनियों, केंद्रीय सरकार के सभी विभागों में जिसमें डॉक तार, आयकर, कस्टम एंड एक्साइज, सीपीडब्ल्यूडी जैसे लगभग 200 से ज्यादा विभागों में 20 लाख से ज्यादा,यही हाल देश के सभी राज्यों के शासकीय विभागों के हैं पूरे देश में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों अधिकारियों आदि के पद खाली पड़े हुए हैं।

1990 के बाद से केंद्र व राज्य के अधिकांश विभागों में भर्तीयां ही नहीं हुई। अधिकांश विभागों में 70 प्रतिशत काम संविदा कर्मियों दैनिक वेतन भोगियों से बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाया जा रहा है आखिर इनकी स्थाई भर्तियां क्यों नहीं की जा रही। ताकि केवल केंद्रीय सरकार के रक्षा मंत्रालय से लेकर डाक तार व रेलवे तक सभी मंत्रियों के विभागों में एक करोड़, देश के सभी राज्यों में भी कर्मचारी अधिकारियों जट्टू इंजीनियर में लगभग 2 करोड लोग भर्ती कयि जा सकते हैं और उन्हें रोजगार दिया जा सकता है पर इसके विपरीत रोजगार देने की अपेक्षा उन्हें मुफ्त का बेरोजगारी भत्ता देकर एक तरफ निकम्मा, कामचोर, आलसी बनाने का सरकारी प्रयास जारी है तो दूसरी तरफ उन करोड़ों युवा शिक्षित इंजीनियर, डॉक्टर, तकनीशियन, वैज्ञानिकों प्रबंधकों आदि का मनोबल तोड़ कर, उनकी शिक्षा मेहनत आदि को बर्बाद कर उनको मानसिक व शारीरिक से रूप से कमजोर बना बनाकर इस देश की पूरी नस्ल बर्बाद की जा रही है और यही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और पाकिस्तान चाहते हैं। तीसरी तरफ यूरोपियन व देशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी यही चाहती है कैसे पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं का कम कीमत पर आसानी से ज्यादा काम लेकर भरपूर शोषण करने का यह बेरोजगारी भत्ता माध्यम बन जाए। उन्हीं के इशारे पर सरकार बेरोजगारी भत्ता देकर भारत के युवाओं को भारत में ही आलसी और निकम्मा बना कर उन्हें बदनाम किया जा सके और यूरोप में घुसने से रोका जा सके। दुनिया की हर लोकतांत्रिक देश की सरकारें यथार्थ में पूंजीपतियों की गुलाम होती है। जो देश के टुकडखोर सत्ताधीशों को मोटे टुकड़े डालकर जनता को लूटने के लिए अपनी सबसे नचा कर काम आती है।

दूसरी और एक तरफ पूंजी पतियों का रखैल मोदी रुपए 21000 न्यूनतम वेतन की घोषणा करता है। वहीं केंद्र की अनेकों योजनाओं और विभागों में जिसमें मुख्य रूप से मनरेगा में वहा काम करने वाले प्रयोगशाला सहायक को मात्र रुपए 3000 और 5000 का भुगतान किया जा रहा है। पिछले 10 सालों से साथ ही संविदा नियुक्ति,राज्य सरकार की सभी विभागों जिसमें पिछले 15 सालों से कंप्यूटर ऑपरेटर जो कि तकनीकी कर्मचारी है 5000 8000 रुपए महीने में काम लिया जा रहा है और वह भी 3-5माह तक उन्हें भुगतान नहीं मिलता।दूसरी ओर जो कि वे नियमित कर्मचारी नहीं है इसलिए उन्हें 9:00 बजे से बुलाकर रात में 8:09 बजे तक काम करते हैं उन्हें कोई छुट्टी की व्यवस्था भी नहीं होती उन्हें जब चाहे जैसे चाहे बुलाकर ना केवल कंप्यूटर चलाने वरण साफ सफाई और चपरासी की भांति काम लिया जा रहा है।

जब भी वो बेचारे अधिक भुगतान और नियमितीकरण की मांग करते हैं तो उन्हें वहां के अधिकारी कर्मचारी धमका देते हैं करना हो तो करो वरना जा सकते हो क्योंकि उन्हें उनके नाम से वेतन नहीं दिया जाता हाजिरी नहीं ली जाती अधिकांश ऐसे कर्मचारी इंजीनियर जो न्यूनतम मजदूरी रु300 रोज से भी कम पर अपनी नियमित सेवाएं दे रहे हैं। केंद्र व राज्यों की सरकार कि हर विभाग में जब सारा काम कंप्यूटर से किया जा रहा है फिर कई सरकार है उनके वभिाग जिसमें हमारी मप्र सरकार भी है।खुले में पिछले 10 सालों से दम भर रही है कि हमारा सारा काम कंप्यूटर पर कागज वहिंन ऑनलाइन हो रहा है। जब सरकार ने 1990 के बाद किसी भी विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती ही नहीं की तो फिर कंप्यूटर कौन चला रहा है और जब जरूरत नहीं है तो कंप्यूटर पर काम कौन कर रहा है। अर्थात बेरोजगारों का घोर शोषण स्वयं हर स्तर पर स्वयं केंद्र व राज्यों की सरकार व उसके सारे वभिाग स्वयं ही कर रहे हैं।

आखिर सरकार में बैठे धूम धूम चक घोर धूर्त भारती प्रताणना सेवा के अधिकारियों जो कि प्रेम हर साल हजारों करोड़ रुपए जनधन का छल कपट और भ्रष्टाचार से डकार जाते हैं।देश की सरकार हर मंत्रालय उसके सभी विभागों में भारतीय प्रताड़ना सेवा, भारतीय अपराध सरंक्षण सेवा, भारतीय वन लूटो सेवा, भारतीय आगम सेवा आदि के, और राज्यों के राज्य प्रताड़ना सेवा अधिकारी तक हर वर्ष लाखों-करोड़ों शासन का और दूसरी तरफ जनता से लूटकर यह सुख की खोज सूकरो की फौज हजम कर जाती है परंतु जो वास्तविक कार्य करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर जो पिछले 15 वर्षों से हर विभाग का सारा काम डीपीआर डिजाइन करने से लेकर पत्राचार सारा लेखन कार्य, सारी बजटिंग प्लानिंग भुगतान, योजना जानकारियां भेजने का कार्य करते हैं वही आधारभूत सेवादार कर्मी दैनिक मजदूरी से कम पर काम करने के लिए मजदूर है। ना उन का नियमितीकरण किया जाता है। न हीं पूरा भुगतान दिया जाता है। पर बंधुआ मजदूर की तरह उन्हें जोता और उनका शोषण हर तरीके से किया जा रहा है। पर उन्हें तकनीकी स्तर का कर्मचारी मानकर न्यूनतम वेतन 30 से 40,000 दिया जाना चाहिए उसके ऊपर भी हनी को देशभर में उच्च न्यायालयों में लगी याचिकाओं पर स्पष्ट लेने देने के बाद में भी कोई भी सरकार उन्हें तकनीकी कर्मचारी मानकर पूरा भुगतान देने को तैयार नहीं दूसरी तरफ मुफ्त में बिना काम लिए अपने वोटों के लिए जन धन से लूटे गए धन को बेरोजगारी भत्ता देकर युवा पीढ़ी को नकारा निकम्मा बना देना चाहती है तो दूसरी तरफ उनकी अपनी प्रतिभाओं उनकी शिक्षा आदि को नष्ट कर देना चाहती है।दुनिया में जिन देशों की सरकार ने अपने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना शुरू किया उसका भारी दुष्परिणाम ना केवल सरकार को बरन देश और देश की जनता को भी लंबे समय तक भोगना पड़ रहा है। सरकार में बैठे घोर लालची धूर्तों को किसी भी घोषणा से पहले दीर्घकाल में उसके परिणाम को सोचना समझना चाहिए।

खुले में ई टेंडरिंग में होती है गुंडागर्दी, जिसमें प्रमुख अभियंता से उपयंत्री तक सब है शामिल

मनपसंद ठेकेदारों को या बड़े गुंडागर्दी करने वाले ठेकेदार खुले में सब को धमकाकर ले लेते हैं, मनमर्जी के ठेके, ये खेल लोक निर्माण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन, नर्मदा घाटी, गृह निर्माण मंडल, ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, सड़क डकैती विकास निगम, पुलिस गृह निर्माण निगम, सभी विकास प्राधिकरणो, नगर निगमों नगर पालिकाओं,आदि सब में खुलकर पिछले कई वर्षों से चल रहा है। बकवास है पारदर्शिता की दलीलें।

सरकार के पास नहीं हैं प्रमुख अभियंता अखिलेश अग्रवाल का विकल्प। रु 50लाख का सॉफ्टवेयर 200 करोड़ में बनवाया गया घोर जालसाज टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज से, जिस नेक्स्ट टेंडरिंग को पूर्व में रखरखाव का ठेका दिया गया था उसमें टेंडर फ़ीस के 3 साल में 300 करोड़ से ज्यादा हजम कर के निकल गई वह। नई सरकार को चाहिए की सबसे पहले वह ई टेंडरिंग के घोटालों और सिंहस्थ में हुए दोगुने से सौ गुनी ज्यादा तक के हर विभाग के टेंडर् में और कार्यों में हुए भ्रष्टाचार को बेनकाब कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश थे किसी को भी सिंहस्थ से संबंधित कोई भी जानकारी किसी भी विभाग की सूचना के अधिकार में ना दी जाए इसलिए नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, लोक निर्माण, जल संसाधन, खाद्य एवं औषधि, कोषालय, सिंहस्थ मेला कार्यालय, डीपीआर, गृह निर्माण मंडल प्रदूषण मंडल, जिलाधीश कार्यालय पुलिस, जेल, धर्मस्व, शिक्षा, उज्जैन विकास प्राधिकरण ,आदि किसी ने भी कोई जानकारी किसी को भी नहीं दी।

पूर्व की भूखेरा जन पार्टी की सरकार को 15 साल के शासन में यह एहसास होने लगा था कि अब सत्ता उनके बाप की बपौती है। वे कुछ भी करते रहे कोई उनसे कुछ नहीं कह सकता कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होगा। वे जनता का धन कैसे भी लूटे और लुटाऐं। जिस सॉफ्टवेयर को भारत सरकार के उपक्रम सीडैक ने 25लाख में बनाया था। उसी सॉफ्टवेयर को मध्य प्रदेश की सरकार ने 25 करोड़ में बनवाया जो कभी भी ढंग से पूरा काम नहीं कर सका और जिस के महानायक थे अनुराग जैन इन्होंने प्रदेश में अधिकांश विभागों के सॉफ्टवेयर जो रुपए 25 50 लाख में बनाए जा सकते थे 50 से 300 करोड़ में बनवाए जिसमें लोक निर्माण का ई टेंडरिंग का रुपए 300 करोड़, कोषालय का 400 करोड़, ई पंजीयन 5.5सौ करोड, कृषि, उद्यानिकी, शिक्षा उच्च शिक्षा स्वास्थ्य आदिम जाति, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आदि सभी के सॉफ्टवेयर जो रुपए 10 20 लाख के थे उन्हें सैकड़ों करोड़ में बनवाया गया और 90 से 95% पैसा हजम कर लिया गया। मध्य प्रदेश सरकार ऐसे ही दो लाख करोड़ का कर्जा लेकर हजम नहीं कर गई उसके लिए उसने 15 साल में अपने खास चहेतो जिसमें टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज, विप्रो, के शेयरों को मार्केट में दो 300 कीमतो को 3000 तक पहुंचा दिया।

मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग में प्रमुख अभियंता, अखिलेश अग्रवाल को 7 साल 7 माह से अधिक समय हो गया हैं। इसी तरह सी पी अग्रवाल भी लोक निर्माण विभाग के सचिव रहे थे जो अब प्रमुख अभियंता तकनीकी परीक्षण सामान्य प्रशासन की प्रति नियुक्ति पर हैं एवं पी.डी.बारस्कर प्रमुख अभियंता, राज्य योजना आयोग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं और अनिल चंसोरिया, प्रमुख अभियंता नगरीय प्रशासन में प्रतिनियुक्ति पर हैं तथा आर के मेहरा, लोक निर्माण विभाग मंत्रालय मैं सचिव के पद पदस्थ हैं

पी.आई.यू के संचालक विजय सिंह वर्त्तमान में एक वर्ष की संविदा पर हैं जिनका इसी माह में संविदा समाप्त हो रही हैं। मुख्य अभियंता वास्तुविद शशिकांत निमाडे का दूसरा वर्ष हैं। सविंदा पर हैं,इस तरह एक प्रमुख अभियंता ओर एक मुख्य अभियंता का पद शिवराज सरकार ने अतिक्रमित कर रखा हैं। इन दो सविंदा के कारण SDO से लेकर प्रमुख अभियंता एवं मुख्य अभियंता के पद रिक्त होते हुये सविंदा से कारण,अभी

ई टेंडरिंग प्रणाली को जालसाजो ने बना दिया मजाक, दिखावा रह गया ई टेंडरिंग

तक रिक्त नहीं हैं। इस कारण विभागीय मुख्य अभियंता,अधिक्षण यंत्री,कार्यपालन यंत्री और सहायक यंत्री पद तक के लोग पदोन्नति या प्रभारो से वंचित हुये हैं

इसी लिये अधिकारी कर्मचारी में शिवराज सरकार के प्रति आक्रोश था, जिसका मूल कारण था। अर्थ आप लगा लीजिये,और परिणाम सामने हैं और अधिकारी एवं कर्मचारियों ने अपनी सरकार के विरुद मतदान किया, क़माल की बात यह हैं कि सपाक्स वर्ग और अपाक्स वर्ग ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने अपना पक्ष रखा था लेक़िन, "माई के लाल" का डायलॉग सरकार को ले डुबा, कहने का तात्पर्य यह हैं कि देश एवं प्रदेश के लोग सोशल जस्टिस को पसंद करते हैं। अपवाद स्वरूप सरकार अपने चहेते को मौका भी दे तो नीति भी यही होनी चाहिये के अन्य को सामान्य अवसर मिलना चाहिए, परन्तु शिवराज सरकार अपने चहेतों को उपकृत करते समय नैसर्गिक न्याय को भूल गई थी जिसका परिणाम सबके सामने आया हैं, अब अखिलेश अग्रवाल सपाक्स ओऱ आर के मेहरा, पी डी बारस्कर अज़ाक्स वर्ग का नेतृत्व कर रहे हैं,यह भी सत्य हैं कि शिवराज सरकार का विरोध इन दोनों वर्गों ने अपने अपने तरीके से किया हैं उसका परिणामस्वरूप बदलाव आया हैं अब सरकार के पाले में गेंद हैं सरकार दोनो को खुश रखती हैं या किसी को नाराज़।

अथ सेतु संभाग कथाएं

सेतु परिक्षेत्र मैं प्रदेश भर में 8 संभाग कार्यरत है जहां घोर भ्रष्ट इंजीनियरों का ही बोलबाला है। सारे हरामखोरों जालसाजों को सारी कमाई समय विस्तार और मूल्यवृद्धि से करनी होती है कोई भी पुल पूरे प्रदेश भर में कभी भी समय पर नहीं बनता। सेतु परिक्षेत्र का यह 50 साल पुराना इतिहास है। यह दुर्घटनाओं का भी कारण बनता है। प्रदेश के विकास की गति को रोकता है। यही कारण है कि यहां बैठे हरामखोरों की फौज कभी सूचना अधिकार में जानकारी नहीं देती और न ही इन सूकरों ने अपनी नोंच खसोंट के चलते मुख्यालय में बैठा अधीक्षण यंत्री किसी भी अपील का उचित निर्णय ही करते और सारी अपील रद्द कर दी जाती है क्योंकि सेतु संभाग की कार्यपालन यंत्री ही इन टुकड़खोरों को टुकड़े डालकर पालते हैं।

सेतु के रीवा संभाग के प्रभारी कार्यपालन यंत्री परिहार ने ठेकेदार से साठ-गांठ कर लगभग सवा करोड़ का भुगतान एडवांस में कर दिया हैं? मामला यह हैं कि सेमरिया चौराहे सतना मार्ग पर फ़्लाई ओवरब्रिज बन रहा हैं। उक्त कार्य निर्माण में भारी अनियमतित्ता सामने आयी हैं उल्लेखनीय हैं कि उक्त निर्माण के नाप लिए बिना ही भुगतान कर दिया गया हैं, सभी स्लैब का पूरा निर्माण नहीं किया गया हैं लेकिन स्लैबों का भुगतान कर दिया गया हैं। सेतु निर्माण की आइटम दर उच्चतम गुणवत्ता की होने के कारण अधिक से अधिक रखी जाती हैं सेतु एवं पुल के कार्य पर सुरक्षा कारणों से अनेक आईटमों का बदलाव भी किया गया हैं। इतना सब होने के बाद भी यदि ठेकेदार को एडवांस भुगतान किया गया हैं। तो भ्रष्टाचार की श्रेणी का अपराध हैं। ऐसे कार्य एवं अपराध करने के आदतन आदि हैं प्रभारी कार्यपालन यंत्री, श्री परिहार काफ़ी समय से यहाँ पदस्थ हैं। जिनके विरुद्ध विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कई सवाल उठा चुके हैं। ओर कांग्रेस के प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री से शिकायत की हैं।

यहां यह भी उल्लेखनीय हैं कि वर्ष 2016-17 में लाखों का भुगतान एक ठेकेदार को कर दिया गया जब बात विभाग के बाहर आयी तो कार्यपालन यंत्री परिहार ने उन पियरो को वर्षा में बहा बता कर अपने आप को बचा लिया था। क़माल हैं ठेकेदार को आजतक 3C एवं काली सूची में नहीं डाला गया हैं। दूसरा अपराध हैं एक पुल पर पियर डालने के बाद जब सैलेब डाली गई तो 60 सेंटीमीटर एक सैलेब से दूसरी सैलेब में ऊंचाई नीचाई का अंतर था, फ़िर परिहार ठेकेदार के साथ आए और परिहार का निलबंन रुक गया था। इसका मतलब साफ़ हैं, कि ऐसे कामो में पूर्व सरकार का संरक्षण था। इस लिए आदतन आपराधिक षडयंत्र के काम बढ़ते गये ओऱ इस अधिकारी का हौसला बढ़ता गया और वह इस तरह के कृत्य निरन्तर करता रहा हैं। और करता रहेगा, परिहार की लोकायुक्त में अनेकों शिक़ायत लंबित हैं,

8 करोड़ का कूनो नदी बना पुल बह गया लेक़िन ग्वालियर सेतु कार्यपालन यंत्री/ठेकेदार पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और 8 करोड़ रु वसूली अधिकारी और ठेकेदार से नहीं हुई हैं।

अथ मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग परियोजना क्रियान्वयन इकाई कथाएं

मध्य प्रदेश की लोक निर्माण विभाग की परियोजना क्रियान्वयन इकाई में प्रदेश के 51 जिलों के संभागीय परियोजना यंत्री मैं अधिकांश वही इंजीनियर बैठाए गए हैं जो कि भवन एवं पथ के कार्यों में घोर भ्रष्टाचार, कमीशन बाजी और लापरवाही पूर्व तरीके से कार्य करते थे और जिनका पुराना इतिहास काफी निराशाजनक रहा है। उन्हीं को सभी शासकीय विभागों के भवनो इसमें स्कूल व उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, न्यायालय भावनों, पुलिस, जेल, आदिम जाति कल्याण, महिला एवं बाल विकास, कृषि विभाग, उद्यानकी, आबकारी, जिला पंचायतों के भवनों,तहसील, उप जिलाधीश जिलाधीश कार्यालय कोषालयो, श्रम, उद्योग, खनिज आदि के भवनों के पिछले 5 सालों में निर्माण किए गए 12 सौ से ज्यादा भवनों में घोर अनियमितताएं की गई। जिसके अंदर भवनों के मूल डिजाइन को बदलकर ही पूरा निर्माण करवाए और मोटा कमीशन हजम कर लिया गया सबसे ज्यादा खुदाई और मलबे के परिवहन में यातायात में अनेकों स्थान पर 50 से लेकर 200 %ज्यादा वसूली की गई। निर्माण में APD इंदौर ने झबुआ DP के विरुद्ध निर्माणाधीन स्लैब गिरने एवं मजदूरों के घायल होने के बाद भी अधिकारियों एवं ठेकेदार पर अभी तक कोई कार्रवाही नहीं की गई हैं। झाबुआ मैं कोई भी भवन मानक स्तर का पर नहीं बनाया गया ओर निर्माण सामग्री भी मानक स्तर की नहीं इस्तेमाल की गई उसके बाद भी ठेकेदारों का भुगतान किया जा रहा हैं। DP झाबुआ में रहते ही नहीं हैं। इंदौर या अन्य जगह पर घूमते फिरते रहते हैं। इसी तरह इंदौर DP ने प्रमुख सचिव, प्रमोद अग्रवाल के मना करने के बाद भी अमानक कार्य का भुगतान किया एवं GM कॉलेज और एम वाय में निर्माणाधीन कार्यो में SBC का बदलाव एंव अमानक स्तर की समग्री लगाई, क़माल हैं डिजाइन बदलाव और कार्य कि लागत बढ़ने के लिये कौन जिम्मेदार हैं। जांच के लिये एक आयोग की आवश्यकता हैं। परिक्षेत्रों,ओर मंडलों मैं APD, PD और PIU में टेंडर घोटाला,दर स्वीकृति,आवंटन से अधिक व्यय,आयटमों में बदलाव मुख्य कमीशन का कार्य बे-धड़क हैं.....

बदलाव मौसम,राजनीति,प्रशासन का नियम हैं और लोकनिर्माण विभाग में यह बदलाव पौने आठ साल में हुआ है। पूर्व प्रमुख अभियंता अखिलेश अग्रवाल राज में लोकनिर्माण विभाग में अर्थिक संकट नहीं था।वहीं नव प्रमुख अभियंता आर के मेहरा को आर्थिक संकट सौगात में मिला है। विभाग के पास PMSY. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें, मध्य प्रदेश सड़क डकैती विकास निगम में प्रमुख अभियंता पद की प्रतिनियुक्ति म ं ग

मनपसंद ठेकेदारों को या बड़े गुंडागर्दी करने वाले ठेकेदार खुले में सब को धमकाकर ले लेते हैं, मनमर्जी के ठेके

लंबित पड़ी

है। कुछ मुख्यअभियन्ता,कुछ अधीक्षण, कार्यपालन, सहायक व उप यंत्री भी बदले जाने हैं चाहिए जो 10-20 साल से एक ही स्थान पर कुंडली मारे भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हालात यह है की अपने वरिष्ठों को सुनते ही नहीं। परियोजना क्रियान्वयन इकाई में भी परियोजना संचालक अतिरिक्त परियोजना संचालक संयुक्त परियोजना संचालकों के साथ संभागीय परियोजना इंजीनियरों को भी तुरंत बदला जाना चाहिए। यह सभी बदलाव की बयार देख रहे हैं। परियोजना संचालक विजय सिंह सविंदाकर्मी हैं। ये भी जाने अंजाने किसी का हक़ प्रभावित कर रहे है, उपलब्धि 20 हज़ार करोड़ के काम समेटने में नहीं हैं, उपलब्धि इस बात में विश्वस्तरीय धन खर्च करना और काम लोकल स्तर का होना है। ड्राइंग डिज़ाइन में भारी खमिया तो की बात सामने आई आजहै ही लेक़िन स्तरहीन काम पर यदि मीडिया में बहस हो जाय तो पक्रिड़ की बिल्डिंगों को आप डिब्बों ओर खोके से अधिक संजा नहीं दें पायेंगे। इंदौर में पिछले 7 वर्षों से बैठे संयुक्त परियोजना संचालक खरात जिन्होंने संयुक्त संचालन रहते हुए भारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। सभी तेरह संभागों में बाहरी भवनों की सलाहकार भ्रष्ट इंजीनियरों से मोटे कमीशन पर भारी भरकम ड्राइंग व डिजाइनिंग करबा कर कार्यों को जिसमें 15 से 20% तक का मार्जिन रखकर अंजाम दिया जा रहा है। बुरहानपुर, उज्जैन, खंडवा, इंदौर, मंदसौर नीमच, रतलाम, झाबुआ, बड़वानी, अलीराजपुर, खरगोन, जिलों में निर्मित सभी विभागों के भवनों की जांच करवाई जानी चाहिए स्वीकृत की गई ड्राइंग ऑफ डिजाइन क्या अनुसार इकाई द्वारा निर्मित भवनों की वास्तविक लागत, कार्य की गुणवत्ता आदि का आकलन करने और स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाने पर मालूम पड़ेगा किस प्रकार भवनों के निर्माण में भ्रष्टाचार और लूटपाट का तांडव हुआ। यह देखते हुए खराब को तत्काल हटाया जाना चाहिए। अतिरिक्त परियोजना संचालक कार्यालय में सिर्फ़ निविदा का प्रतिशत ओर समय वृद्धि, और उपयोग की गई सामग्री अनुसार अतिरिक्त स्वीकृति से एक सफल व्यवसायी के रूप में चला हैं। ड्राईंग डिज़ाइन, क़्वालिटी, प्राक्कलन मैं बाहरी कंसल्टेंट में सिर्फ़ फर्जीवाड़ा चलाकर इस विभाग में इंजीनियरिंग को मैनेज़र बनाकर रख दिया गया । जिसके कारण इंजीनियर अपनी प्रतिभा दिखाने के बजाय प्रबंधक बन सत्ता की चाशनी को चखता रहे हैं। यह विभाग के साथ छल कपट हैं।

कल तक अखिलेश अग्रवाल प्रमुख अभियंता रागदरबारी हुआ करते थे। लोक निर्माण विभाग में कोई किसी का स्थायी दोस्त/दुश्मन नहीं हैं, समय और परिस्थितियों के अनुसार लोग अपनी गोटियां खेलते हैं रोटियां सकते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ जो होगा वह भी अच्छा होगा,इतना ज़रूर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री कमलनाथ पर्यावरण प्रेमी ओर मानक स्तर के कार्य गुणवत्ता की परख रखते हैं कोई उनको बहला/समझा नहीं सकता हैं।

उम्मीद है विभाग हरित परियोजनाओं पर भी कार्य करेगा। साथ ही सभी सड़कों के निर्माण चाहे वह लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण किसी के द्वारा भी बनाई जाए या इन विभागों के अंतर्गत बनी हुई है, जितना पैसा सड़कों के दोनों किनारों और बीच में बनाई मार्ग विभाजक के रूप में हरियाली के लिए छोड़ी गई भूमि पर तत्काल प्राक्कलन व नियमों के अनुसार सघन वृक्षारोपण कर सड़कों को नवजीवन प्रदान करने के साथ सड़कों पर दौड़ने वाले लाखों वाहनों के धुए को वायुमंडल में फैलने से रोकते वृक्षों द्वारा शोषित कर लयिा जाए। दूसरी तरफ वाहन चालकों को उस हरियाली में से न केवल सड़क का सफर वरन जीवन का सफर भी सुहाना लगे और वाहन चालक तरोताजा बने रहकर संतुलित मस्तिष्क से स्वयं सुरक्षित वाहन चलाते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें और भारत में भारी दुर्घटनाओं से बचाव किया जा सके। निसंदेह हर सड़क निर्माण में दोनों तरफ और बीच में हरियाली की व्यवस्था के लिए हर सड़क की प्राक्कलन में धन की व्यवस्था की जाती है। जिसका पूरा धन ठेकेदार के साथ मिलकर विभागीय इंजीनियर हजम कर जाते हैं। जिसका दुष्परिणाम सड़कों पर होने वाली प्रतिदिन हजारों दुर्घटनाओं मैं होती 2000 लोगों की मौत के रूप में सामने आता है जो कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा है जिस के मूल कारण मेंसड़कों के किनारे वृक्षों का पर्याप्त विकास और ध्यान न रखा जाना है।

साप्ताहिक समय माया

इंदौर में ही क्यों आखिर घोर भ्रष्ट और जाल साज आकाश त्रिपाठी

हम भ्रष्टन के, भ्रष्ट हमार, लेन-देन का रखो व्यवहार

भू माफिया भाजपाई नेताओं के साथ मिलकर पूरे बाईपास पर सैकड़ों कालोनिया कटवाई। बीआरटीएस में करोड़ों जनता के धन धन के बर्बाद किए। विद्युत कंपनी में रहकर पूजी पतियों उद्योग पतियों के करोड़ों के बिल माफ किए, दूसरी तरफ गरीबों को उनकी झोपड़ियों छोटे मकानों में इसी आकाश त्रिपाठी के समय पर लाखों के बिल देकर किसी की हृदयाघात में मौत हुई, किसी ने आत्महत्या कर ली और हजारों के ऊपर बिजली चोरी के केस लाद दिये गए।विलो में 3 से 5 गुना ज्यादा तेज मीटर से हजारों करोड़ की अंटसंट वसूली की गई पूरे पश्चिम विद्युत वितरण क्षेत्र में। कंपनी में सारा रख रखाव का पैसा जो हर वर्ष पूरे इंदौर उज्जैन के 15 जिलों में 300 से 500 करोड़ था कागजों पर दिखा कर ही हजम कर लिया गया। जानबूझकर खंबे बदलने के नाम पर पुराने कमजोर खंबे बड़ी कंपनियों से लगाकर पुराने करोड़ों खंबे उनके पुनः स्थापन का शुल्क भारी कमीशन खाया गया। ट्रांसफार्मरों रखरखाव में समय पर उचित तेल पानी नहीं किया गया जिससे हजारों ट्रांसफॉर्मर बर्बाद हुए। यह आकाश त्रिपाठी की बिजली कंपनी का प्रबंध संचालक रहते हुए उपलब्धियां थी। शायद कमलनाथ सरकार ने ऐसे भ्रष्ट को इसीलिए इंदौर संभाग का आयुक्त बना कर पुरस्कृत कर दिया। ताकि भविष्य में त्रिपाठी पूरे इंदौर संभाग के 8 जिलों से ग्रामीण विकास का आदिम जाति विकास का अरबों करोड़ रुपए इकट्ठा कर कांग्रेस के नेताओं की झोली भरते रहे।फिर चुनावों में लोकसभा चुनाव 14 जिताने और विधानसभा 13 में इंदौर की अधिकांश सीटें भाजपा को दिलवाने में गिनती और वोटिंग में भारी षडयंत्र का जिम्मेदार है

मध्यप्रदेश में भाजपा ने 3 विधानसभा चुनाव इतनी आसानी से जीत कर सत्ता नहीं चलाई। उसने अपने वफादार भारतीय प्रताड़ना सेवा, राज्य प्रताड़ना सेवा के वफादार, आज्ञाकारी, पदोन्नत अधिकारियों को लोकसभा व विधानसभा जीतने के लिए 1 साल पहले से ही जिलों में जिलाधीश, उप, सहायक जिलाधीश, तहसीलदार बनाकर इसी निर्देश के साथ बैठाले जाते थे। कि आने वाले चुनाव में येन,केन, प्रकरेण, साम, दाम, दंड, भेद, किसी भी तरह भाजपा को जिताना है।

भारतीय प्रताड़ना सेवा अधिकारी आकाश त्रिपाठी भाजपा का खास वफादार सिपहसालार जिसने2013 मैं मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनवाने के लिए 9 में से 8 विधायक भाजपा के ईवीएम की जालसाजी के साथ ही बिना ऑफिस एक्सल शीट बनाएं आराम से नामों की घोषणा कर दी गई थी। ईवीएम मशीन खुलने और उसके बाद उसकी ऑफिस एक्सल शीट बनाने हर चक्र की कुल प्राप्त मतों, की वर्गीकृत कंप्यूटराइज सीट में ऑडी और खड़ी महायोग को सत्यापित ही नहीं किया गया। बेशक यह खेल पूरे मध्यप्रदेश में खेला गया भाजपा के हाथ से जाती हुई सत्ता को पुनः भाजपा को सौंप दिया गया। थे। वहां बैठे विभिन्न शासकीय विभागों के जिला अधिकारियों से लेकर घोर जालसाज मक्कारों ने फिर फरवरी में 14 ही सुमित्रा महाजन को 45 लाख वोट से जिताने का वादा कर दिया था। इसके लिये प्रारंभ से ही हर प्रकार के छल कपट शुरू कर दिए गए थे यहां तक की मैंने हिंदू महासभा से अजमेरा प्रवीण कुमार के नाम से अपना नामांकन 4 अप्रैल 2014 को एबी फॉर्म के साथ जमा किया। जिसे उस दिन स्वीकार कर लिया गया। पार्टी के बैनर पर। परंतु 9 अप्रैल 14 को मुझे भाजपा के इशारे पर हिंदू वोट न कट जाए नोटिस दिया गया कि आप हिंदू महासभा से प्रत्याशी नहीं रह गए हैं। जबकि प्रदेश में दूसरे कई हिंदू महासभा के प्रत्याशी खड़े हुए थे। उनके नामांकन रद्द नहीं किए गए।जब मैंने इसका कारण जानना चाहा और लिखित दस्तावेज मांगे तो मुझे भारतीय चुनाव आयोग का जिस अनुराग शर्मा का पत्र दिया गया।भारतीय चुनाव आयोग दिल्ली में उस नाम का कोई व्यक्ति वहां पर कार्यरत नहीं था। दूसरी तरफ नाम अजमेरा हटा दिया गया और प्रवीण कुमार जैन कर दिया गया जबकि जैन के नाम से फॉर्म ही नहीं भरा था मैंने पूछा तो मुझे स्पष्ट निर्देश दिए गए। आपको हिंदू महासभा से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं आप। ज्यादा हो तो फॉर्म वापस ले लो।नहीं तो निर्दलीय लड़ो और आपका नाम अजमेरा नहीं लिखा जाएगा। यह जालसाजी इस वफादार श्वान आकाश त्रिपाठी की थी। मैं खड़ा हुआ मैंने अपने ही पेपर में ताई का सच लिखा और अपना विज्ञापन छाप दिया मुझे नोटिस दिया गया यह पैड न्यूज है। इसके विज्ञापन के पैसे चुनाव खर्च में जोड़िये। इस प्रकार मुझे हर कदम पर परेशान किया जाने लगा फोन टेप किए जाने लगे वैसे वो आज भी हो रहे हैं।उस समय मुझसे कोई सीधी बात तो नहीं करता था पर जो मेरे सहयोगी थे उनको भाजपा के सहयोगी धमकाते थे कि आप अजमेरा का साथ छोड़ दो वरना कानूनी लफड़े में उलझा दिया जाओगे। अर्थात भाजपा के इशारे पर भाजपा के अतिरिक्त सभी प्रत्याशियों के टेली फोन टेप किए जा रहे थे। और जानकारी सीधी भाजपा मुख्यालय पर पहुंच रही थी। मेरे टेलीफोन टेप करके प्रशासन, भाजपा को सारी खबरें भेज रहा था। यह सच सारे मीडिया वाले जानते थे।इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है जबकि मेरे पास सो 50 आदमी भी नहीं थे बात यहीं खत्म नहीं होती।

चुनाव आयोग में हर बात के हर काम के झंडे पोस्टर ढोल लाउडस्पीकर, सभाओं कार्यकर्ताओं उनकी संख्या चुनाव कार्यालय उस पर दैनिक खर्च गाड़ियां उनको दैनिक पेट्रोल, कर्मचारियों के खाने पीने, आदि की खर्च का पूर्ण विवरण चुनाव आयोग की दिशा निर्देशों और खर्च के अनुसार देना था जो कि करोड़ों रुपए में था। स्वामी था सारा सारा खर्च का कोई विवरण नहीं दिया गया केवल दिखावी आंकड़े भर दिए गए। चुनाव के दिन महाजन ने हर बूथ पर 50 से 100 भाजपाई कार्यकर्ता थे। साथ ही देपालपुर सांवेर तक के कार्यकर्ताओं से लेकर चुनाव ड्यूटी पर लगे सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों सुरक्षा सैनिकों पुलिस आदि के लिए भी भोजन की व्यवस्था अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा की जा रही थी। उनके चाय नाश्ते व खाने-पीने, न्यूनतम एक लाख से ज्यादा पैसे ज्यादा खर्च किया खाने पीने और उनके भाजपाइयों को नगद कैश देने में 2226 बूथ पर अर्थात रु22 करोड 26लाख एक ही दिन का न्यूनतम खर्च था। इसके विपरीत सरकारी सूकरों ने 70 लाख में ही खर्च समेट दिया। ताई ने 800 से ज्यादा सभाएं की जिसमें 500 से ज्यादा सभाएं मंदिरों, मंदिर परिसरों, सार्वजनिक स्थानों पार्कों आदि में बिना प्रशासनिक आज्ञा के, की गई। चुनाव आचार संहिता के नियमों के विरुद्ध। पर तात्कालिक कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने कहीं कोई एक्शन नहीं लिया। आंख मींच कर अंध सहयोग करता रहा।

फिर सब बड़ी जालसाजी गिनती के दिन हुई जहां कहीं कोई ऑफिस एक्सेस सीट नहीं बनाई गई। ईवीएम की जालसाजी के बाद भी ईवीएम मशीनों से वोटों की गिनती रात में 10:00 बजे तक चलती रही परंतु ताई को 3:30 बजे ही साढे 4लाख वोट से जीता घोषित कर दिया गया। कांग्रेस के मंत्री मंडल को इन सब जालसाजीयों को देखते हुए आकाश त्रिपाठी को कहीं लूप लाइन में डालना था परंतु उन्होंने इस भाजपा भक्त को जो इंदौर में पिछले 8-9 सालों से जमा हुआ है इंदौर का संभागायुक्त बना दिया जो इनकी भारी भूल होगी।

भाजपा की चुनावों में भरपूर मदद करने और ईवीएम के जल साजियों, गिनती में मनमाने तरीके से भाजपा के प्रत्याशी को जिताते हुए सत्ता दिलवाने में सहयोग करने का पुरस्कार देते हुए उसे इंदौर में पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का यहीं पर प्रबंध संचालक नियुक्त कर दिया गया।उसमें भी इसने दोनों हाथ एक तरफ जनता को लूटा, तो दूसरी तरफ उद्योगपतियों, पूंजीपतियों केक करोड़ों के बिल माफ किए और 15 जिलों में विद्युत कंपनी के वितरण में हर कदम रखरखाव वितरण आदि में करोड़ों के भ्रष्टाचार का धन मुख्यमंत्री तक पहुंचाता रहा। अगर इसकी बारीकी से जांच की जाये, तो हर ठेके खरीदी में करोड़ों का भ्रष्टाचार नजर आएगा।

कंपनी में सारा रख रखाव का पैसा जो हर वर्ष पूरे इंदौर उज्जैन के 15 जिलों में 300 से 500 करोड़ था कागजों पर दिखा कर ही हजम कर लिया गया। जानबूझकर खंबे बदलने के नाम पर पुराने कमजोर खंबे बड़ी कंपनियों से लगाकर पुराने करोड़ों खंबे उनके पुनः स्थापन का शुल्क भारी कमीशन खाया गया। ट्रांसफार्मरों रखरखाव में समय पर उचित तेल पानी नहीं किया गया जिससे हजारों ट्रांसफॉर्मर बर्बाद हुए। यह आकाश त्रिपाठी की बिजली कंपनी का प्रबंध संचालक रहते हुए उपलब्धियां थी।

विद्युत कंपनी में रहकर पूजी पतियों उद्योग पतियों के करोड़ों के बिल माफ किए, दूसरी तरफ गरीबों को उनकी झोपड़ियों छोटे मकानों में इसी आकाश त्रिपाठी के समय पर लाखों के बिल देकर किसी की हृदयाघात में मौत हुई, किसी ने आत्महत्या कर ली और हजारों के ऊपर बिजली चोरी के केस लाद दिये गए।विलो में 3 से 5 गुना ज्यादा तेज मीटर से हजारों करोड़ की अंटसंट वसूली की गई पूरे पश्चिम विद्युत वितरण क्षेत्र में। कंपनी में सारा रख रखाव का पैसा जो हर वर्ष पूरे इंदौर उज्जैन के 15 जिलों में 300 से 500 करोड़ था कागजों पर दिखा कर ही हजम कर लिया गया। जानबूझकर खंबे बदलने के नाम पर पुराने कमजोर खंबे बड़ी कंपनियों से लगाकर पुराने करोड़ों खंबे उनके पुनः स्थापन का शुल्क भारी कमीशन खाया गया। ट्रांसफार्मरों रखरखाव में समय पर उचित तेल पानी नहीं किया गया जिससे हजारों ट्रांसफॉर्मर बर्बाद हुए। यह आकाश त्रिपाठी की बिजली कंपनी का प्रबंध संचालक रहते हुए उपलब्धियां थी। शायद कमलनाथ सरकार ने ऐसे भ्रष्ट को इसीलिए इंदौर संभाग का आयुक्त बना कर पुरस्कृत कर दिया। ताकि भविष्य में त्रिपाठी पूरे इंदौर संभाग के 8 जिलों से ग्रामीण विकास का आदिम जाति विकास का करोडों रुपए इकट्ठा कर भाजपा के नेताओं की झोली भरते रहे।फिर चुनावों में लोकसभा चुनाव 14 जिताने और विधानसभा13 में इंदौर की अधिकांश सीटें भाजपा को दिलवाने में गिनती और वोटिंग में भारी षडयंत्र का जिम्मेदार है।

जिनके पास 30x10 का मकान था उनको भी 45000 के बिल दिए जाते रहे और जांच करवाने के बाद में उन्हें माना कि 1 एलईडी में 45000 का बिल देना निश्चित ही गलत है इसके विपरीत जो उनके गली मोहल्ले में आने वाले मीटर रीडर को महीना नहीं देते उनके हजारों में विल दिए जा कर उन्हें मानसिक रूप से पूरे 15 जिलों में पिछले 4 सालों से ज्यादा प्रताड़ित किया गया।परंतु प्रबंध संचालक त्रिपाठी को अपनी मोटी लूट और हजारों करोड़ की कमाई से मतलब था जनता से कदापि नहीं दूसरी तरफ जानबूझकर सूचना का अधिकार में जानकारी मांगने पर जानकारी देने से बचने के लिए सूचना आयुक्त ने बड़े-बड़े वकील खड़े कर दयि जाते। पर सारे लाभ हानि खाते से लेकर हर बर्ष के चिट्ठों में झूठे आंकडे दिखाकर पिछले 4 सालों से लगातार साल में दो बार बिजली की कीमतें बढ़ाने का षडयंत्र रचा जा कर जनता से लूट के रास्ते तैयार किए जाते थे और कीमतें बढ़ाकर लूट का यह षड्यंत्र लगातार पिछले 15 सालों से चल रहा है इसमें आकाश त्रिपाठी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसकी जांच होनी ही चाहिए और पुरस्कार स्वरूप त्रिपाठी को संभागायुक्त की जगह किसी छोटे-मोटे विभाग में बैठाया जाना चाहिए।

लोकसभा चुनाव में पुनः ईवीएम की जालसाजी से जीतने का षड्यंत्र

पृष्ठ 1 से जारी

इसलिए तत्काल ईवीएम मशीनों से चुनाव करवाना बंद किया जाए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह मांग उठेगी कि भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाए रखने के लिए किसी भी हाल में ईवीएम से अगला चुनाव नहीं होना चाहिए। जिसे हर हाल में स्वीकार करना पड़ेगा और मत पत्रों से चुनाव करवाने पर किसी भी हाल में पुनः मोदी अमित शाह सत्ता में नहीं लौट पाएंगे। इसलिए बेहतर होगा की तीनों राज्यों में जानबूझकर चुनाव हार लिया जाए। ताकि भारत की जनता के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह की कोई भविष्य में मांग ना उठे और वो धूर्त हाल फिलहाल तो अपने उद्देश्य में सफल होते नजर आ रहे है।वैसे चुनाव आयोग में और सर्वोच्च न्यायालय में सभी स्थानों पर मोदी ने अपने मनपसंद व अपने पक्ष में काम करने वालों की स्थापना कर दी है। स्वाभाविक है, चुनाव आयोग में बार बार आवेदन देने और मत पत्र को चुनाव करने के लिए कहा जाने के बाद में बार बार इस मांग को ठुकराने के बाद में सर्वोच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध याचिकाओं को भी खारिज कर दिया जाना।मोदी की कामयाबी मे आड़े नहीं आएगा। यह तो वैसे भी हर सत्ताधीश का अपना शगल होता है। कि वह चारों तरफ अपनी पसंद के लोगों को जो अपने पक्ष में कार्य करें हर बड़े पद पर सुशोभित करे। फिर मोदी और शाह तो केवल झूठे वादों जिन्हें वो पूरा नहीं कर सकते थे। के दम पर ही सत्ता हथियाने में सफल रहे। और जब उनसे पूछा गया कि आपने यह वादे किए थे। यह सब कब पूरे होंगे तो खुले में उन्होंने स्वीकार किया यह सब चुनावी वादे थे अर्थात चुनाव जीतने का फरेबी हथकंडा था। अब जब सत्ता में है तो चलाने, कमाने, अपने आप को बचाने और फिर सत्ता हथियाने यह सब तो करना ही पड़ेगा।दूसरी तरफ यदि शिवराज र्और रमन अगर 4थी बार मुख्यमंत्री बने तो वो भी अगले प्रधान मंत्री पद के दावेदार बन जाएंगे इसलिए भी उनको हराना व हटाना जरूरी था क्योंकि उनकी लोकप्रियता से मोदी के प्रधानमंत्री पद पर आंच आने लगी थी। सबसे पहले कांग्रेस को चाहिए कि भले ही उन्होंने में 3 राज्य जीत लिए हों। परन्तु अगला चुनाव कोई भी ईवीएम से ना हो पाए। अन्यथा यह अपने ऊंट घोड़ों को पिटवा कर वजीर व राजा को बचा कर ले गए हैं। अभी। परन्तु भविष्य में आने वाले लोकसभा चुनावों में ईवीएम की जालसाजी से चुनाव जीतेंगे। यह सलाह भी उसके पूंजीपति मित्रों की ही है। वैसे भाजपा ने पिछले लोकसभा व उप्र व गुजरात के चुनाव कैसे जीते हैं। अंध भक्तों ने देखे।

57 महीनों में मोदी ने चारों तरफ मचा दी घोर तबाही

पृष्ठ 1 से जारी

देश के विकास के सपने दिखाने के बहाने अपने बापों के लिए यह भेड़िया विदेश में जाकर बड़े-बड़े सौदे बाजी करता रहा है। उनके व्यापार के लिए जिसमें अंबानी के लिए रफाल, अदानी के लिए ऑस्ट्रेलिया में स्टेट बैंक से रु25000 करोड का स्टेट बैंक से कर्ज दिलवाया।बची खुची कसर उसने अपने बापों के लिए 1 जुलाई2017 को बिना पूर्व तैयारी के जीएसटी लाद दिया गया। जिसका मूल उद्देश्य था सारे देश के लगभग 10 करोड छोटे व्यापारी, उत्पादक चोट छोटे उद्योगों को कानून के जाल में फंसा कर नष्ट कर दिया जाए ताकि इनके बापू के व्यवसाय दिन दूनी रात चौगुनी गति से फले फूले 30 करोड़ लोग बेरोजगारों कर इनके यहां भीख मांगते नजर आए। किए झूठी घोषणाएं वादे, तो इन दोनों गुजराती गिद्दों के डीएनए में शामिल है।तीन राज्यों में चुनाव हारने के बाद अब मीडिया ने उसके सारे सच को जो 5 साल में देश व जनता के साथ कियाअब दैनिक समाचार पत्रों ने खुलकर लिखना शुरू कर दिया है अन्यथा पिछले साढे 4 साल तक इस देश का सारा मीडिया यथा टीवी समाचार चैनलों दैनिक समाचार पत्रों सब चुप थे। गुजराती मोदी निसंदेह तुम जैसा झूठा, मक्कार, फरेबी, देश को बेचने वाला पूंजी पतियों का, गुलाम नेता, इतिहास में और वर्तमान में धरती पर तो कोई नहीं।

भारत में वर्तमान में लंबी सस्ती और सुविधाजनक यात्राओं के लिए रेल के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं जो कि पिछली एक शताब्दी से इतिहास और वर्तमान मै सध्दि कर रही थी। आपने उन रेलों की यात्रा को इतना महंगा कर दिया। उसे फ्लेक्सी किराये से जोड़ दिया। जैसे-जैसे उस ट्रेन की यात्रियों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही करिये भी बढ़ता जाएगा जैसा कि हवाई जहाज के किराए में होता है। यहां तक की ru₹3/- का प्लेटफार्म टिकट रु10 में कर दिया। आम नागरिक रेल से यात्रा करने में डरने लगा।दूसरी तरफ महंगे ऐसी चेयर कार फर्स्ट क्लास का किराया हवाई जहाज से ज्यादा हो जाने के कारण लोगों ने मजबूरन रेलो को त्याग कर हवाई यात्रा करना शुरू कर दिया। यह आपकी उपलब्धि नहीं आप की लूट व बदतमीजी का परिणाम है। आप 180 किमी गति ट्रेन की बात कर रहे हैं। ना। उससे पहले 20 साल पहले भी डेढ़ सौ किलोमीटर की गति से गाड़ीयां चलाई जा चुकी है। परंतु तीव्र गति से गाड़ी चलाने में परेशानी यह है कि भारत की पटरियों पर जितना वजन, भार, दाब एक दनि में गुजरता है। उतना वजन, दुनिया की किसी भी रेलवे की पटरियों पर नहीं गुजरता फिर भी भारत में रेल की पटरियों की इतनी क्षमता नहीं 200 किमी की गति को झेल सकें। दूसरी ओर आपने तो आते ही अपने खास पूंजी पतियों से मोटा कमीशन खाकर 456 रेलवे स्टेशन गिरवी कर दिए। आप की तैयारी तो रेलवे को पूरा का पूरा टाटा और अंबानी को सौंपने की है। यदि रेलवे कर्मचारियों के संघों ने इसका विरोध नहीं किया होता तो आपने अभी तक टाटा अंबानी और बिरला को पुरी रेलवे लाखों करोड़ का कमीशन खाकर अंबानी और टाटा को सौंप दी होती। आप और आपकी भूखेरा जन पार्टी तो पूरी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली-पानी सड़कें, रेलवे, कर संग्रहण व अधिकांश सार्वजनिक संपत्तियों, उपक्रमों, शिक्षा संस्थानों, अस्पतालों, बैंकों, बीमा कंपनियों , सब को पहले बर्बाद कर, घाटे में दिखाकर लाखों करोड़ का मोटा कमीशन लेकर निजी हाथों में सौंपने के लिए तुला हुआ है यह आपकी 4 साल की उपलब्धियों का कच्चा चट्ठा है। जैसा कि पूर्व में भाजपा ने सन 1999 से 2003के कार्यकाल में किया था जब आपने हजारों करोड़ का कमीशन खाकर आप के उद्योग व विनिवेश मंत्री अरुण शौरी ने कयि था। उस वक्त बाल्को, भिलाई स्टील प्लांट, केजी बेसिन6 की गैस दो अरब लाख क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का भंडार आप ने हीं अंबानी को कोड़ियों में दे दिया था। और जब आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उस गैस पर रॉयल्टी की मांग कीजो अरबों रु थी। तो उसके हेलीकॉप्टर में अंबानी बंधुओं ने गड़बड़ी करवाकर उसके हेलीकॉप्टर को दुर्घटना करवा कर खत्म कर दिया जिसकी रिपोर्ट अमेरिकी सीनेट में भी उठी थी। जो किस्मत से हमारे हाथ लगी तब हमें मालूम पड़ा कि आपकी भाजपा और आपके अंबानी देश में क्या-क्या गुल खिला रहे हैं।

आपने यह नहीं बताया कि इसरो आपके आने से कई वर्ष पहले से ही काम कर रहा था और उसने कई बार 20 20 सैटलाइट एक साथ भेजे हैं। उसकी उपलब्धियों पर उसके सर पर सेहरा बंधा है। आपके सर पर नही।

आपने भीम ऐप की चर्चा की आपको मालूम है कि जिस गूगल से आप हर चीज को डाउनलोड करने की बात करते हैं। वह दुनिया का बाप आप की सरकार की सारी जानकारियां जिसे आप के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी गोपनीय बता कर सूचना के अधिकार में नहीं देते हैं। गूगल और उसके दूध कर्मचारी और अधिकारी उन आपकी सारी गोपनीय जानकारियों को आप की सब्जी देशों के साथ साझा करके अरबों डॉलर की कमाई करते हैं। अब देश के ठेले वाले तक के डाटा को इकट्ठा कर रहा है। हम सब के डाटा तो हैं ही उसके पास आज तक चीन की तरह गूगल का विकल्प तैयार नहीं किया देश के अंदर। वह कांग्रेसी $120 का क्रूड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने पर भी 80 का पेट्रोल बेचते थे, देश में, तब आप और आपकी भाजपा मंचों से गले फ़ाड चल्लाया करते थे।फ़िरे आपकी किस्मत से, आपकी सत्ता संभालते ही वह क्रूड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 15-16 में $30 का का बिक रहा था तो भी आपने अपने बाप अंबानी की कमाई के लिए सारे क्रूड खरीदी के अधिकार को सौंप कर देश में ru₹70 से रु95 प्रति लीटर पेट्रोल बेचा। यह नहीं बताया। आपने जो उसमें चार गुना कमीशन खाने के बावजूद भी वह पेट्रोल कभी रु40 भी नहीं आया जबकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 4 गुना कीमत कम हो चुकी थी। फिर नोटबंदी से 40 करोड़ लोग 2 महीने के लिए बेरोजगार हो एकदम सड़कों पर आ गए किसके लिए की थी आपने नोट बंदी अपने बाप अंबानी अडानी टाटा बिरला और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए। GST आपने उनके फायदे के लिए लगा है ना इससे भी 50लाख छोटे मध्यम उद्योग बंद हो गए और 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए समझ में आ रहा है।आपको। गप्पू मोदी जीतने के बाद कभी पत्रकारों की खुले में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करवाई क्यों डर लगता है अपने लूट डकैती और भ्रष्टाचार के कुकर्मों से। वैसे अपनी जाति व कर्मो के छिछोरे इतिहास के अनुकूल तुम्हीं ने अश्लीलता की सीमाओं को त्याग मंचो से अपने 56 इंच सीने की की महिमा का बखान किया था जो एक राजनेता के लिए घोर अशोभनीय था। ऐसे एकल तारीफों के वीडियो तो अमेरिकी वेश्या सनी लियोन ने भी बहुत सारे डाले उसकी नग्नता के दम पर ही भारत में उसे बहुत सारा नाम र्और काम मिला। 2महीने बचे है, कौन से देश की सुन्दरी की यात्रा बाकी है। अंतमि जनधन से और हजारों करोड़ बर्बाद कर विश्व भ्रमण कर लीजिएगा। अगर पुनः सत्ता नहीं मिली तो फिर गुजरात की गलियों में उसी मवाली गिरी के धंधे में उतरना पड़ेगा।

साप्ताहिक समय माया

धूर्त मोदी की चाल में फंस सवर्ण भूल गए सारे अपराध और पाप

जिस आरक्षण और एट्रोसिटी कानून को समाप्त करने, सपाक्स का आंदोलन खड़ा हुआ। जो भाजपा सवर्णों की रोटी-बोटी खाकर, धन बल पाकर, सत्ता हथियाई। वही 40 करोड सवर्ण, भूखेरा जन पार्टी को सत्ता के मद में कीड़े मकोड़े और जानवर दखिने लगे। ऊसको जब 3 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा तो उसे अपनी औकात याद आ गई। परंतु दूसरी तरफ सवर्ण यह भीख का टुकड़ा पाकर, यथार्थ में अपनी बर्बादी ही करेगा उसके होनहार बच्चे जो मेहनत से पढ़ाई कर बड़े-बड़े पदों पर देश में विदेश में अपना लोहा मनवाते हैं। सरकारी नौकरी न मिलने के कारण अच्छा व्यापार, व्यवसाय व उद्योग स्थापित कर सैकडों को रोजगार देते हैं। वे स्वयं इस आरक्षण में उलझ कर अपने आप को मकड़ी के जाल में, अच्छी नौकरी पाने के चक्कर में उलझा लेंगे। जबकि उनकी वंशानुगत व्यवसाय की परंपरा से वे ज्यादा बेहतर तरीके से अपना और अपने परिवार का जीवन यापन और बच्चों को शिक्षण आदि कर सकते हैं।

भारत के घोर धूर्त, झूठे, मक्कार गुजराती भुखेरे मोदी ने, पूजी पतियों से धन लेकर जिस तरह मीडिया को खरीद कर एक तरफ झूठे सपने, कितना पिक्चर जनता को दिखाएं अपनी झूठी वाह वाही अपने आप को एक महान हिंदु संरक्षक बताया प्रचारित किया। तो दूसरी तरफ देश के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को खरीद व लालच देकर ईवीएम की जालसाजी से प्रधानमंत्री बनते ही पूंजीपतियों की चरणों में लोट लगाकर जिस तरह से देश को, जनता को पैट्रोल डीजल की चोगुनी कीमत वसूलने के साथ ही नोटबंदी, जीएसटी, बर्बाद किया। अंग्रेजों के पट्टे के आजाद भारत के 70 वर्ष कें इतिहास में कोई इतना घोर धूर्त, कम शिक्षित प्रधानमंत्री दूसरा नहीं हुआ। जो कि अंधी कठपुतली की तरह, अपनी पूंजीपति आकाओं, अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला, के लिए उनके बैंकों के लाखों करोड़ के ऋण जो उन्होंने अपनी अनेकों कंपनियों के नाम से लिए थे। जनता को नोटबंदी के कारण नोट बदलने के नाम, और गरीब जनता को लालच देकर उसके बैंक अकाउंट खुलवा कर बैंकों में लाखों करोड का धन जमा करवा, और बाद में बैंकों में लेन देन के ऊपर, शुल्क लगा कर व न्यूनतम बैलेंस के नाम पर बैंकों ने एक तरफ रुपए 4.5 लाख करोड़ हजम कर लिया। दूसरी तरफ भारी भरकम हर लेनदेन पर और सेवाओं के नाम शुल्क में भारी बढ़ोतरी कर जनता को हर तरह से लूटा और इस तरह से बैंकों के लाखों करोड़ के डूबंत बनाकर, आम जन से वसूली की गई। इस तरह से उस धन से अपनी आकाओ के लाखों करोड़ माफ करवा दिया गए। अखिल इन सब में लुटा कौन? वहीं डरपोक, धर्म भीरु, अपने और परिवार कें जीवन को संवारते हुए, आप अपनी इज्जत का ख्याल रखने वाले नम्नि मध्यमवर्गीय सवर्ण। जिसका भाजपा ने सत्ता में आते ही गर्वनर कुकर खुले में हर कदम कदम पर उसका अपमान करना शुरू कर दिया। भेड़िया जानवर पार्टी की दिग्गजों की नजर में यह निम्न मध्यमवर्गीय सवर्ण कीड़े मकोड़े और जानवरों से ज्यादा कुछ नहीं था। इन सब से भी जब पेट नहीं भरा। तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत अपने दलति वोटो के लिए एट्रोसिटी एक्ट अध्यादेश लाकर लाद दिया गया। इस पर जब मध्यमवर्गीय सवर्ण का आक्रोश फूटा और उसने जब इस भुखेरा जन पार्टी को 3 बड़े राज्यों में अपने मताधिकार के प्रयोग कर धूल चटा दी तो इन्हें फिर अपनी लोकसभा की सत्ता हाथ से जाते दिखने लगी तब इन्होंने निम्न मध्यमवर्गीय सवर्णों को फांसने के लिए 10% के आरक्षण का टुकड़ा डालकर भ्रमित करने का असफल प्रयास किया। यह आरक्षण भी मात्र सरकारी नौकरियों में मिल सकता है पर इस के संबंध में, इस सामान्य वर्ग के आरक्षण की घोषणा होते ही केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस आरक्षण का कोई लाभ होने वाला नहीं क्योंकि नौकरियां मलि कहां रही है सरकार में। यथार्थ में सवर्णों को आरक्षण की अपेक्षा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के लिए, छात्रवृत्ति, निशुल्क बड़े शिक्षण संस्थानों में व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वे अपनी प्रतिभाओं का सदुपयोग अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए कर सकें। अन्यथा मेरी तरह दो वक्त की रोटी की, शिक्षण शुल्क आदि की व्यवस्था न हो पाने के कारण, मुझे इंजीनियरिंग, सनदी व लागत लेखाकार, प्रबंधन, आदि का अध्ययन नहीं कर पाया। सवर्णों की हर समाज में ऐसी आर्थिक तंगी के कारण 50% छात्र जो निम्न मध्यमवर्गीय स्तर के हैं अध्ययन से वंचित हो जाते हैं। इसलिए आरक्षण की अपेक्षा वित्तीय रूप से कमजोर सवर्ण विद्यार्थियों को आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की तरह अच्छे अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां, निशुल्क छात्रावास ही सरकार दे देवे तो भी काफी होगा। जबकि सच यह भी है यथार्थ में केंद्र सरकार में सौ से ज्यादा विभागों मे, 500 से ज्यादा सरकारी उपक्रमों, संस्थानों आदि में जिसमें रेलवे, रक्षा, सुरक्षाबलों, डाक विभाग मैं ही करीब पिछले 30 सालों से भर्तियां ना होने के कारण लगभग एक करोड़ से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं परंतु यह भूखेरा जन पार्टी, रक्षा और सुरक्षाबलों को छोड़कर अपने आका बापों को सौंपने और निजीकरण के बहाने करोड़ों रुपए हजम करने के लिए रेलवे, डाक विभाग, एयरइंडिया, आयकर, केंद्रीय कस्टम ब इक्साइज, केंद्रीय शिक्षण संस्थानों चिकित्सा संस्थानों व अन्य विभागों में भर्तियां नहीं कर रही। जैसे की, लाल किले से लेकर, रेलवे कें 456 रेलवे स्टेशनों को मोटा कमीशन खाकर पूंजीपतियों के हवाले कर दिया गया। सवर्णों कें सरकारी नौकरियों में आरक्षण से लघु बुद्धि वाले सवर्ण, मात्र भ्रम से हर्षित हो रहे हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि जो 50% बचा हुआ हिस्सा अनारक्षित था उसको अब 10% पर समेट कर सवर्णों को आरक्षण नहीं यथार्थ में उनके साथ छल किया गया है जो केवल चुनावी शिगुफा है जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है की 50% से ज्यादा कोई आरक्षण नहीं किया जा सकता दूसरी तरफ जिस व्यक्ति की रु8 लाख आय हैं अर्थात लगभग रु65000 प्रतिमाह की आय वाला सवाल वैसे भी एक दो बच्चों वाला ही होता है वह अपने व्यवसाय में अपने बेटे को लगाएगा या इनके आरक्षण के लिए, सरकारी संविदा नौकरी में जहां इंजीनियरों को रु10 से 12000 से15हजार- प्रति माह की नौकरी से 5 साल के डिग्री कोर्स के लिए ऋण का ब्याज भी नही निकलता। ऊपर से जनता की वरिष्ठ अधिकारियों, की नेताओं की सरकारी नौकरी में गालियां सुनो, बत्तमीजीयां झेलो। वो अलग से। शायद यह बात सवर्णों को अभी तक समझ में नहीं आई जो बड़े टुकड़ा पाकर खुश हो रहे हैं। निसंदेह पूरे विश्व के लोकतंत्र में 90% लोकतांत्रिक सरकारें देसी विदेशी पूंजीपति बहुराष्ट्रीय कंपनियों की रखैल होती है। स्वाभाविक है भारत में भी देसी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने हर सरकार को चाहे वह कांग्रेस की हो या भाजपा की, सबको कठपुतली की तरह नचा कर अपने मोटे लाभ के लिए मनचाहे कानून बनवाते हैं। अपनी तरह से सत्ता को में जाकर जनता का नचा कर जनता का हर तरीके से घोर शोषण करते हैं यही पूंजीवाद का सबसे बड़ा अभिशाप है।

न्यायालय न्याय के मंदिर नहीं जुए के अड्डे, न्यायिक व्यवस्था पूंजीपतियों सत्ताधीशों की रखैल

भारतीय न्याय प्रणाली घोर भ्रष्ट, भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार, भूतपूर्व राष्ट्रपति के आर नारायणन ने स्पष्ट कहा था कि न्यायालय न्याय की मंदिर नहीं जुए के अड्डे हैं यहां जो जितना बड़ा दांव खेलता है। उसे उतना न्याय मिलता है। इस तथ्य को बड़े-बड़े वकील और न्यायाधीश भी दबी जुबान से स्वीकार करते हैं न्याय केबल जिला न्यायालयों में ही होता है। जहां पर न्यायाधीश परीक्षा पास करके आते हैं। उच्च व सर्वोच्च न्यायालय में तो न्यायाधीशों की नयिुक्तियां राज्यों और केंद्र के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की इच्छा से अपने खास और पसंद के वकीलों की की जाती है। जो उनकी इच्छा के अनुकूल उनके और उनके आका पूंजीपतियों के हितों का ध्यान रखते हुए उनके पक्ष में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर फैसले देते हो। यह प्रथा भारत के सभी उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में पिछले 70 साल से चली आ रही है। इसीलिए आधार कार्ड , ईवीएम से वोटिंग आदि से जनता और देश के साथ के न्याय के नाम घोर अन्याय किया जा रहा है। जनता के साथ आधार कार्ड से जो छल कपट, किया जा कर उनके बैंक खातों से करोडो रु की हर दिन जालसाजी से निकाले जा रहे हैं। आमजन के खातों से 90% धनराशि निकल जाने के बाद, पहले तो पुलिस और बैंक उसकी रिपोर्ट नहीं लिखते, फिर सरकार और बैंक ना तो पेसा लौटाते हैं। नहीं उसके आधार कार्ड और मोबाइल से उसका लिंक खत्म करते हैं। इसके विपरीत आधार कार्ड से उसके मोबाइल फोन, गाड़ी, मकान, दुकान, बैंक अकाउंट आयकर, राशन कार्ड नंबर, आदि की जानकारी गूगल और इंटरनेट के माध्यम से आसानी से पता कर ली जाती है। और फिर उन्हें आसानी से उनके बैंक खाते मोबाइल सर्वजनिक कर महिलाओं को पुरुषों को ना केवल भारत भारत पाकिस्तान चीन सीरिया नाइजीरिया अमेरिका व पूरी दुनिया से जाल साज गुंडे बदमाश आसानी से डरा धमकाते हैं। जिस पर देश की पुलिस, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। फिर भी यह सब जानकर भी सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की खोटी नियत और मोटी कमाई के लिए आधार कार्ड के विरुद्ध अनेकों केसो में सुनवाई की परंतु उसे हटाया नहीं। आधार कार्ड पर अभी तक जन धन से लगभग 13 वर्ष में डेढ लाख करोड से ज्यादा खर्च किया जा चुका है। जिससे मोटी कमाई सत्ताधीशों उनके भाई भतीजों और उनके आका पूंजीपतियों को करवाई गई है। बदले में आमजन का जीना मुश्किल करते हुए हर व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी खाना पीना उठना बैठना सब का रिकॉर्ड देसी और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास पूरी दुनिया में उपलब्ध हो चुका है। यही हाल देश के हर मंत्रालय, वहां पर कार्यरत कर्मचारीयों अधिकारीयों से लेकर राष्ट्र के व राज्यों के गृह, रक्षा मंत्रालयों सैन्य बलो मैं कार्यरत सैनिकों, सैन्य अधिकारियों की हर गतिविधियों पर नजर रखने उनकी व्यक्तिगत डेटा , देश में बैठे शत्रुओं, आतंकवादी गिरोहों, शत्रु राष्ट्रों यथा पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, रूस, अमेरिका ब्रिटेन से लेकर नाइजीरिया, सीरिया के जालसाज हैकरों के पास में भी उपलब्ध है। जिस के दुष्परिणामों में, वहां पर बैठे हैं कर , भारतीय बैंकों में, आसानी से सेंध लगाकर दिन के 24 घंटे और साल के ३६५ दिन में किसी व्यक्ति, संस्था, कंपनिओं, किसी के भी खाते से उसके बैंक खाते एटीएम , डेबिट, क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेकर आसानी से करोडो रुपए हर दिन दूसरों की खातों में अंतरति कर देते हैं। जब तक खातेदार की नींद खुलती है तब तक अंतरित धन को जाल साज निकाल चुके होते हैं। उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कार्ड के कारण जालसाजी के शिकार हुए आज तक ऐसे लाखों बैंक पीड़ितों को न तो बैंकों को धन लौटाने के लिए आदेशित किया और ना ही कोई भी राहत उपलब्ध करवाई। यहां तक की भारतीय वित्त मंत्रालय और उसके अंतर्गत कार्यरत बैंकों को ऐसी जालसाजियों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए सख्त निर्देश दिये, नहीं बैंकों को उसके कर्मचारियों

राम मंदिर के लिए 70 साल से बहानेबाजी, सबरीमाला का शीघ्र फैसला

अधिकारियों को सजा का प्रावधान किया हो आर्थिक दंड सहित किन्ही भी पूरे देश में पीड़ितों का भुगतान करवाया हो। आधार कार्ड से आम से लेकर खास तक सारी जानकारियां सारी दुनिया को सार्वजनिक होने से रोकने के लिए भारतीय सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं। दूसरी तरफ देश की जनता की, यहां तक की सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के साथ ही अपने ही देश की सैन्य बलों की साइबर सुरक्षा की तरफ सरकार जानबूझकर सब जानकारी होते हुए भी आंख मीच कर पर बैठी हुई है।यही कारण है कश्मीर में देश के अन्य हिस्सों में पुलिस सैन्य बलो पर होते लगातार हमले और उसमें सैनिकों की हत्या मृत्यु स्पष्ट करती है। आधार कार्ड की आधार हीनता की सच्चाई यों को। यह सब जानकर भी सर्वोच्च न्यायालय खुले में आधार कार्ड के पक्ष में फैसले दे रहा है। वही हाल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के संबंध में भी सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है । यथार्थ में सर्वोच्च न्यायालय की अपनी सीमा है परंतु सत्ताधीशों के इशारे पर, ईवीएम से चुनाव करवाने पर जनता को विवश करता है। उसे व्यापक जनहति से कोई लेना देना नहीं। उसके न्यायाधीशों को अपने आकाओं के हितों को साधने के लिए बैठाया गया है। दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हिंदुओं के गौवध, गौमांस निर्यात, दही हांडी, हिंदुओं के त्योहारों दिवाली पर पटाखे, होली पर पानी प्रयोग आदि पर, देश के जाने-माने और हिंदुओं की आस्था कें प्रतीक महाकाल , सबरीमाला और अन्य मंदिरों की पूजा, 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश आदि पर फैसले सुना दिए जाते हैं। परंतु गौ मांस के सेवन से कभी मुस्लिमों को नहीं रोका गया। साथ ही यही हाल राम मंदिर के निर्माण के लिए, हिंदुओं की हतैषी बनने वाली वर्तमान की भाजपा और पूर्व की जनसंघ के लिए 70 वर्षों से तारीख पे तारीख दी जा रही है। यह मामला बहुत बड़ा नहीं है फिर भी जानबूझकर उसे वर्तमान भाजपा के सत्ताधीशों कें राजनीति करने, उनके इशारे पर जानबूझकर उसे विवादित बनाकर रखने, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने, वोटो के लिए लटकाए रखने में ही स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ज्यादा विश्वास रखते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय कि न्यायाधीशों ने, सबसे ज्यादा बलात्कार,जानबूझकर, कानून को भौथरा बनाने, सरकारी भ्रष्टाचार व सरकारी भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों को बचाने के लिए मनमर्जी के फैसले, कांग्रेस सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने शासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया था। के विरुद्ध दिए ताकि आसानी से देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा सके और मजबूत किया जा सके। वह एकमात्र कानून जिसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 19 में की गई थी उस कानून को सरकार को बनाते बनाते 58 साल गुजर चुके थे जिसके बाद में भी सर्वोच्च न्यायालय मैं बैठाए गए, सांसारिक काम, क्रोध, मद, मोह से बंधे हुए जिन अपने खास वकीलों को न्यायाधीश बना कर पदों पर सुशोभित किया जाता है। आखिर इन नैसर्गिक मजबूरियों से कैसे बच सकते हैं। फिर जिन्होंने बैठाया है। उन आकाओं की इच्छापूर्ति और उनके पक्ष में फैसले देना भी तो आवश्यक है।इसलिए इस सूचना अधिकार कानून को पूरी तरह से औचित्य हीन बनाने का प्रयास सरकार की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशो के साथ ही सभी सत्ताधीश मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी अमर फल खाकर आए हैं जो इस धरती पर जनता का खून पीते हुए, जन से धन लूट कर धरती पर सहस्त्रों वर्षों तक ऐशो आराम करेंगे। इसलिए वे जन धन का हिसाब कैसे दें।शासकीय कार्यालय में बैठे अधिकांश श्वान अधिकारी कर्मचारियों की फौज यह मानती है कि वेतन तो केवल हाजरी का मिलता है। यदि ऊपरी कमाई और भ्रष्टाचार नहीं तो कैसी नौकरी। उसे सरकारी काम से नहीं। ऊपरी कमाई से मतलब है। यदि ऊपरी कमाई नहीं तो काम बिगाड़ना, रोकना, अटकाना कैसे हैं? फिर सूचना का अधिकार की जानकारी मांगने वालों को सर्वोच्च न्यायालय ने जो अनशन उल्टे सीधे फैसले दिए हैं। वह सूकरों की फौज उनका संदर्भ लेकर सरकारी काम को अपने बाप की जागीर मान जानकारी देने से साफ मना कर देते हैं। उन को यह नहीं मालूम कि ये सारे कानून कायदे जिसका वह मखौल उड़ा रहे हैं। किसी भी दिन उनकी अकाल विदाई का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कारण भी बन सकते हैं।

वैसे भी यथार्थ में कानून धूर्तो के बनाए शब्दों के मायाजाल हैं जो अपनों के पोषण और नरिीहो के शोषण के काम आते है। दूसरी ओर कानून सत्ताधीशों की अदृश्य शब्दावली रूपी हथियार हैं।जिनसे जनता का तन, मन, धन से भरपूर शोषण कर अपनी सुख सुविधा की हुकूमत चलानी है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, आम्बेडकर नगर इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 94256-37958, इंदौर। मोबा. 94251-25569, 9479535569